



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 41	शिमला, शनिवार, 24 अप्रैल, 1993/4 वंशाख, 1915	संख्या 17
	<b>विषय सूची</b>	
भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	578—622 तथा 632
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	622—626
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनलियल कमिशनर तथा कमिशनर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि	626—628
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	628—630
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	630—632
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

24 अप्रैल, 1993/4 वंशाख, 1915 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'समाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं:-

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या 3-4/92-ई० एल० एन०-II, दिनांक 12 अप्रैल, 1993.	निर्वाचन विभाग	भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/93 (3), दिनांक 23 मार्च, 1993 का अंग्रेजी रूपान्तरण सहित प्रकाशन।
संख्या 3-25/91-ई० एल० एन०, दिनांक 16 अप्रैल, 1993.	निर्वाचन विभाग	भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 82/हि०प्र०- वि०स०/1 व 2/90 का इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन।
संख्या एल०एस०जी०-ए०(3) 17/92, दिनांक 16 मार्च, 1993.	स्थानीय स्वशासन विभाग	नगरपालिका समिति, हमीरपुर में इशतहार और विज्ञापन चिपकाने की विनियमित करना, उपविधि. 1993 का प्रकाशन इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित।
No. LLR-E (9)-1/88-Vol.-II (loose), dated 2nd April, 1993.	Law Department	Appointment of Shri N. K. Sharma, Advocate as Advocate-on-record for H. P. Government Liti- gation work with Supreme Court w. e. f. 24-1993.

भाग 1--वैधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

शिमला-171002, 10 दिसम्बर, 1991

# NOTIFICATIONS

Shimla-1, the 31st March, 1993

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-VIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the District and Sessions Judge, Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge (Forests), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-III and IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Mrs. Kiran Agarwal, District and Sessions Judge (Forests), Shimla with effect from 19-4-1993 to 5-5-1993 with permission to prefix Sunday falling on 18-4-1993 and to suffix gazetted holiday falling on 6-5-1993, or until she returns from leave.

Shimla-1, the 31st March, 1993

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-VIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Sub-Judge-cum JMFC (II) Paonta Sahib as Drawing and Disbursing Officer in respect of the court of Sub Judge-cum-Sub Divisional Judicial Magistrate (I), Paonta Sahib and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-III and IV establishment attached to the aforesaid court under head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Shri D.S. Khenal, Sub Judge-cum-S.D.J.M. (I), or until he returns from leave.

Shimla-1, the 31st March, 1993

No HHC/Admn. 6 (23)/74-VIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of Himachal Pradesh Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare Shri George, Additional Chief Judicial Magistrate-cum-Sub Judge 1st Class, Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Sub Judge-cum-Judicial Magistrate (II), Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the Class-III and IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" till the new incumbent is transferred and posted there.

By Order,

Sd/-

Additional Registrar (Admn.).

हिमाचल प्रदेश सरकार

धार्मिक विभाग (नि-1)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 4 दिसम्बर, 1991

संख्या का० (नि-1)-बी० (15)-3/79.—इस विभाग की सम संख्या अधिसूचना दिनांक 1-1-91, जिस द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के संवर्ग के पदों का निर्धारण किया गया है, का क्रम जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्ष आदेश करते हैं कि उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) के 39 पदों में से जिन में, 3 पद भरमौर, काजा तथा पांगी के श्री सम्मिलित हैं का पदनाम 1-1-91 में परियोजना अधिकारी एवं उप मण्डलाधिकारी (ना०) भरमौर/काजा/पांगी होगा।

संख्या पर (ए०-1)-ई० (3)-9/91.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर (ए०-1)-बी० (6)-1/91 दिनांक 30-8-91 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जी० के० श्रीवास्तवा, एच०ए०एस०, का भू-अर्जन अधिकारी (लोक निर्माण-1) शिमला के पद पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेशों को सहर्ष रद्द करने के आदेश देते हैं। श्री जी० के० श्रीवास्तवा, एच०ए०एस० पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला के पद पर ही तैनात रहेंगे।

शिमला-171002, 10 दिसम्बर, 1991

संख्या का० (नि-1)-बी० (2)-2/88.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर श्री ईश्वर दास, अवसर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को (जिन्हें उप-सचिव नामों-दिष्ट किया गया है) 1-12-1991 से नियमित आधार पर उप-सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के पद पर रु० 3700-5000 के वेतनमान रु० 400/- प्रतिमाह विशेष वेतन सश्रित पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

श्री ईश्वर दास 1-12-1991 से 2 वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

राज्यपाल, यह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री ईश्वर दास उपरोक्त पदोन्नति पर उप-सचिव (मुख्य मन्त्री तथा जनजातीय विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार के पद पर ही कार्यरत रहेंगे।

शिमला-171002, 17 दिसम्बर, 1991

संख्या 1-15/73-कार्मिक-1.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्ष श्री सी० पी० पाण्डे, भा० प्र० से० (हि० प्र०-80) को विदेशी प्रशिक्षण से लौटने पर सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद पर तैनात करने के लोकहित में तत्काल से आदेश देते हैं।

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 1991

संख्या पर (ए०-1)-ए० (4)-1/91.—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री बी० पी० मल्होत्रा, स्थाई बरिष्ठ वास्तुकार, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को मुख्य वास्तुकार, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पद पर वेतनमान रु० 5900-6700 में नियमित रूप से पदोन्नति करने के सहर्ष तत्काल से आदेश करते हैं।

2. श्री बी० पी० मल्होत्रा 2 वर्ष तक परिवीक्षा काल पर रहेंगे।

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 1991

संख्या पर (ए०-1)-ई० (3)-9/91.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक हित में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण तथा तैनाती आदेश सहर्ष तत्काल से करते हैं :-

1. श्री जी० के० श्रीवास्तवा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला को स्थानान्तरित करके मण्डलायुक्त, धर्मशाला के सहायक आयुक्त के पद पर तैनात किया जाता है।
2. श्री टी० एन० शर्मा, मण्डलायुक्त धर्मशाला के सहायक आयुक्त को स्थानान्तरित करके, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला तैनात किया जाता है।

शिमला-2, 21 दिसम्बर, 1991

संख्या पर (नि-1)-बी० (2)-2/90.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर (ए०-1) बी० (2) 5/85, दिनांक 10-9-86 का क्रम जारी रखते हुए तथा उसमें

दी गई जर्नी को व्यवस्थित रखते हुए श्री कर्नार सिंह मिन्हास को दिनांक 20-5-85 से 22-1-86 तक पूर्णतया काल्पनिक तौर पर अवसर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, रु 1400-1850 जमा रु 200/- प्रतिमास विशेष वेतन (दिनांक 1-1-1986 से रु 3000-4500 जमा रु 400/- प्रतिमास विशेष वेतन) के वेतनमान के पर पर पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

श्री कर्नार सिंह मिन्हास दिनांक 23-1-86 से 30-6-86 तक पदोन्नत ही अवसर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार पदोन्नत रहे हैं।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/  
मुख्य सचिव।

शिमला-2, 23 दिसम्बर, 1991

संख्या का 0 (नि-1)-ए 0 (2)-1/86.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री डब्लू राम शर्मा, नायब तहसीलदार, उप-तहसील, झण्डूता, जिला जिलासपुर को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियों उन तहसील, झण्डूता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या होम-बी (बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुरूप होंगी।

हस्ताक्षरित/  
विशेष सचिव।

शिमला-171002, 28 दिसम्बर, 1992

संख्या 3-34/66-डीपी-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, महर्ष श्री अमर नाथ विद्यार्थी, भा 0 प्र 0 से 0 वित्तियुक्त एवं सचिव (आवकारी एवं करधान, जननातीय, खाद्य एवं आपूर्ति तथा सङ्कास्ति) हिमाचल प्रदेश सरकार के 11-1-1993 से 19-1-1993 के प्राकल्पिक व वैकल्पिक अवकाश के दौरान वर्ष 1990-93 की रियायती यात्रा अवकाश सुविधा अपने परिवार के आश्रित सदस्यों सहित शिमला से बंगलौर तथा वापसी की अनुमति प्रदान करते हैं।

भारत के राष्ट्रपति यह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री अमर नाथ विद्यार्थी, भा 0 प्र 0 से 0, वित्तियुक्त एवं सचिव आवकारी तथा करधान, जन जातीय, खाद्य एवं आपूर्ति तथा सङ्कास्ति) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस 0 एस 0 सिद्धू, भा 0 प्र 0 से 0 वित्तियुक्त एवं सचिव (लोक निर्माण), हिमाचल प्रदेश सरकार अतिरिक्त रूप से करेंगे।

शिमला-171002, 28 दिसम्बर, 1992

संख्या 2-25/64-डीपी-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, श्री अमर नाथ, भा 0 प्र 0 से 0, वित्तियुक्त एवं सचिव (विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में इस विभाग की अधिलेखना समसंख्यक दिनांक 17-11-1992 द्वारा स्वीकृत किमे गये 13 दिनों के रूपांतरित विकास दिनांक 11-1-1993 से 23-1-1993 को सहर्ष रद्द करने के स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री अमर सिंह, भा 0 प्र 0 से 0 के पक्ष में खण्डवर्ष 1990-93 में प्रदान की गई रियायती यात्रा अवकाश सुविधा को भी रद्द किया जाता है।

हस्ताक्षरित/  
मुख्य सचिव।

(सचिवालय प्रशासन सेवाएं-1)

शिमला-171002, 28 दिसम्बर, 1992

संख्या कामिक (स 0 प्र 0-1) बी (6)-3/89.—भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के विशेष निजी सचिव

श्री अमरा वर्ण को मूलपूर्व मुख्य मन्त्री श्री शान्त कुमार के साथ आगामी आदेशों तक तैनात करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,  
मुख्य सचिव।

(नि 0 I)

शिमला-171002, 29 दिसम्बर, 1992

संख्या 10-3/73-डीपी-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्णेश्वरी नेगी, भा 0 प्र 0 से 0 (परिवारिकार्थी), सिरमौर जिला को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियाँ सिरमौर जिला की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या होम-बी (बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुरूप होंगी।

शिमला-171002, 29 दिसम्बर, 1992

संख्या 10-2/72-डीपी-नियुक्ति-2.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अरुण कुमार शर्मा, तहसीलदार, जसवा, जिला कांगड़ा को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियाँ जसवा तहसील की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या होम-बी (बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुरूप होंगी।

शिमला-171002, 30 दिसम्बर, 1992

संख्या 10-2/72-डीपी-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण देव शर्मा, सहायक आयुक्त, मण्डला-मुक्त, कांगड़ा, धर्मशाला को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियाँ धर्मशाला की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या होम-बी (बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुरूप होंगी।

शिमला-171002, 30 दिसम्बर, 1992

संख्या का (नि-1)-ए (2)-2/90.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बी 0 एल 0 राणा, नायब तहसीलदार (ग्रामीण), जिला शिमला को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियाँ तहसील शिमला के ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या होम-बी (बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुरूप होंगी।

शिमला-171002, 30 दिसम्बर, 1992

संख्या का (नि-1)-ए (2)-2/90.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के 0 डी 0 शर्मा, नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था वृत्त ठेला, जिला शिमला को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियाँ वृत्त ठेला की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जाएगी जो कि गृह विभाग,

हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या होम-बी (बी) 12-5/84 दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1992 के अनुरूप होगी।

शिमला-171002, 30 दिसम्बर, 1992

संख्या का (नि-1)-ए(2)-2/90.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चेतन राम चौहान, नायब तहसीलदार, जुन्ना, जिला शिमला को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियाँ जुन्ना की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या होम-बी(बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 व 27-12-1984 के अनुरूप होंगी।

शिमला-171002, 1 जनवरी, 1993

संख्या 3-29/71-डी०पी०-नियुक्ति—भारत के राष्ट्रपति, श्री बी० के० बन्सल, भा० प्र० से०, निबंधक, भू-अभिलेख, हिमाचल प्रदेश के पक्ष में 8 दिनों का अजित अवकाश दिनांक 1-1-1993 से 8-1-1993 तथा राजपत्रित अवकाश दिनांक 31-12-1992 व 9, 10-1-1993 को जोड़ने की अनुमति सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भारत के राष्ट्रपति यह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री बी० के० बन्सल, भा० प्र० से० की उपरोक्त अवकाश अवधि के दौरान उनका कार्य श्री द्वारा जाल नाशाद, भा० प्र० से०, पंजीयक, सहकारी नभाएँ, हिमाचल प्रदेश अपने कार्य के अतिरिक्त देखें।

श्री बी० के० बन्सल, भा० प्र० से० के पक्ष में खण्ड वर्ष 1990-93 की रियायती यात्रा अवकाश सुविधा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों सहित निम्न प्रकार से व्यतीत करने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

क्रम संख्या	नाम/सम्बन्ध	यात्रा आरम्भ की तिथि	स्थान जहाँ प्रयोजन किया है
1.	स्वर्ग	31-12-1992	शिमला से मुम्बई तथा वापसी।
2.	पत्नी	15-12-1992	शिमला से मोआ तथा वापसी।
3.	कु० पूजा (बेटी)	23-12-1992	सखनऊ से गोआ तथा वापसी दिल्ली।
4.	निशान्त बन्सल (बेटा)	21-12-1992	दिल्ली से गोआ तथा वापस दिल्ली।

हस्ताक्षरित/-  
आयुक्त एवं सचिव।

शिमला-171002, 1 जनवरी, 1993

संख्या 1-39/72-कार्मिक-खण्ड-2.—भारत के राष्ट्रपति, श्री के० लाल, भा० प्र० से० (हि० प्र०-1973), विशेष कार्य अधिकारी (पुलिस क्लज), हिमाचल प्रदेश सरकार को स्थानान्तरित करके तत्काल से मण्डलायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी तैनात करने के सहर्ष आदेश देते हैं। वे कुमारी बिमला मणन, भा० प्र० से०, प्रबन्ध निदेशक, हि० प्र० राज्य सघु उद्योग तथा निर्यात निगम को इस पद के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे।

शिमला-171002, 1 जनवरी, 1993

संख्या 1-39/72-कार्मिक-खण्ड-2.—भारत के राष्ट्रपति, श्री के० लाल, भा० प्र० से० (हि० प्र०-1973), विशेष कार्य अधिकारी (पुलिस क्लज), हिमाचल प्रदेश सरकार को भारतीय प्रशासनिक सेवा

के सुपरटार्डम वेतनमान रुपये 5900—8700 में दिनांक 8-7-199 से पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

भारत के राष्ट्रपति, श्री के० लाल, भा० प्र० से० (हि० प्र०-1973 को दिनांक 23-11-1989 अर्थात् उस तिथि से जिस तिथि उनके कनिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सुपरटार्ड वेतनमान दिया गया है, नोशनल पदोन्नति देने के भी सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-171002, 5 जनवरी, 1993

संख्या 5-1/71-कार्मिक-1.—भारत के राष्ट्रपति सहर्ष श्रीमती आश स्वर्ण भा० प्र० से०, (हि० प्र० : 73) आयुक्त एवं सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार जो कि 25-8-1993 तक अध्ययन अवकाश पर है की सेवाएँ केन्द्र सरकार के अधीन वतौर संयुक्त सचिव, भारत सरकार के युवा मामलों एवं खेलकूद विभाग के पद पर उनके कार्य भार संभालने की निधि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर सोचने व आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
मुख्य सचिव

शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या 3-42/74-डीपी-नियुक्ति.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 30-11-1992 का अधिकरण करते हुए भारत के राष्ट्रपति, श्री रवि डोंगरा, भा० प्र० से०, मण्डलायुक्त शिमला मण्डल, शिमला के पक्ष में 20 दिनों का अजित अवकाश दिनांक 11-1-1993 से 30-1-1993 तक तथा राजपत्रित अवकाश दिनांक 9, 10-1-1993 व 31-1-1993 को जोड़ने की अनुमति सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भारत के राष्ट्रपति यह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री रवि डोंगरा, भा० प्र० से० की उपरोक्त अवकाश अवधि के दौरान उनका कार्य श्री एस० के० सूद, भा० प्र० से०, आयुक्त एवं सचिव (विचाई एवं जन स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्य के अतिरिक्त करेंगे।

श्री रवि डोंगरा, भा० प्र० से० के पक्ष में खण्ड वर्ष 1990-93 के दौरान शिमला से आगरा तक तथा वापसी अपने परिवार के आश्रित सदस्यों सहित उपरोक्त अवकाश के दौरान रियायती यात्रा अवकाश सुविधा व्यतीत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षरित/-  
मुख्य सचिव।

शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या का (नि-1)-ए(2)-1/86.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बलदेव राम ठाकुर, तहसीलदार, धुमारवी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियाँ बिलासपुर तहसील की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जाएगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या होम-बी(बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुरूप होंगी।

हस्ताक्षरित/-  
आयुक्त एवं सचिव।

शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या 3-9/74-डीपी-नियुक्ति.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 26-11-1992 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत के राष्ट्रपति सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री योगेश खन्ना,

भा0प्र0 से0, आयुक्त एवं सचिव (प्रशासनिक सुधार तथा प्रशिक्षण), तथा अनिश्चित कार्यभार आयुक्त एवं सचिव (कृषि तथा सचिवालय प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश के अजित अवकाश दिनांक 11-1-1993 से 23-1-1993 के दौरान उनका कार्य श्री पी0 मित्रा, भा0प्र0 से0, विशेष सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार अतिरिक्त रूप से देखेंगे।

हस्ताक्षरित/-  
मुख्य सचिव।

(सचिवालय प्रशासन सेवाएं-I)

शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या का(म0 प्र0-1)बी(2)-2/92.—भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित अधिकक ग्रेड-II को अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) वेतनमान रुपये 2200-50-2400-60-2700-75-3000-100-4000 जमा रुपये 200/- विशेष वेतन के पद पर सचिवालय में पूर्णतया अस्थायी तौर पर तत्काल में पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश करते हैं :—

1. श्री मोहन लाल गुप्ता
2. श्री योगिन्द्र सिंह

यह पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील नं0 2615/87, श्री गुरु लाल नेगी तथा अन्य बनाम भारत राम कपरेट और अन्य तथा माननीय प्रशासनिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश में दायर अपील नं0 4/1988, श्री बंध राज और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य तथा अपील नं0 161/1988 श्री ज्योति स्वरूप और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य के अन्तिम निर्णय पर निर्भर होगी।

इस पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी का इस पद पर नियुक्त रहने, वरिष्ठता या नियमित पदोन्नति का अधिकार नहीं होगी।

के आदेश में  
हस्ताक्षरित  
आयुक्त एवं सचिव।

(नि-1)

शिमला-171002, 7 जनवरी, 1993

संख्या 3-3/73-डी0पी0-नियुक्ति.—इस विभाग द्वारा अधिसूचना सम सं0 दिनांक 22-12-92 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत के राष्ट्रपति सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री पी0 आइ0 संधान, भा0प्र0 से0, सदस्य (वित्त एवं लेखा) हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड, शिमला के प्रजिण एवं अजित अवकाश दिनांक 1-1-93 से 18-2-93 के दौरान उनका कार्य अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड अतिरिक्त रूप से देखेंगे।

शिमला-171002, 7 जनवरी, 1993

संख्या 3-4/72-डी0 पी0-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, श्री एस0 के0 सुद, भा0प्र0 से0, आयुक्त एवं सचिव (मिर्बाई एवं जन-स्वास्थ्य, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में 25 दिनों का अजित अवकाश दिनांक 27-1-1993 से 20-2-1993 तक तथा राजपत्रित अवकाश दिनांक 24-1-1993 से 26-1-1993 व 21-2-1993 को जोड़ने की अनुमति सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. भारत के राष्ट्रपति यह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री एस0 के0 सुद, भा0प्र0 से0 की उपरोक्त अवकाश अवधि के दौरान उनका कार्य श्री एस0 एस0 परमार, भा0प्र0 से0, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश, राज्य वित्तीय निगम, शिमला एवं आयुक्त एवं सचिव (गृह एवं सतर्कता), हिमाचल प्रदेश सरकार अतिरिक्त रूप से देखेंगे।

3. भारत के राष्ट्रपति, श्री रवि दीपरा, भा0प्र0 से0 मण्डलायुक्त शिमला मण्डल के अजित अवकाश के दौरान जिनका कार्य अतिरिक्त रूप से श्री एस0 के0 सुद, भा0प्र0 से0, आयुक्त एवं सचिव (मिर्बाई एवं जन स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपा गया है के कार्य को 27-1-1993 से 30-1-1993 तक श्री एस0 एस0 परमार, भा0प्र0 से0, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम को सौंपने के भी सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-171002, 7 जनवरी, 1993

संख्या 3-5/72-डी0 पी0-नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति, श्री एस0 एस0 परमार, भा0प्र0 से0, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम एवं अतिरिक्त कार्यभार आयुक्त एवं सचिव (गृह एवं सतर्कता) हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में 13 दिनों का अजित अवकाश दिनांक 11-1-1993 से 23-1-1993 तक तथा राजपत्रित अवकाश दिनांक 9, 10-1-1993 व 24, 25, 26-1-1993 को जोड़ने की अनुमति सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. भारत के राष्ट्रपति यह भी सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री एस0 एस0 परमार, भा0प्र0 से0 के उपरोक्त अवकाश के दौरान उनका कार्य श्री एस0 के0 सुद, भा0प्र0 से0, आयुक्त एवं सचिव (मिर्बाई एवं जन स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार अतिरिक्त रूप से देखेंगे।

3. श्री एस0 एस0 परमार, भा0प्र0 से0 के पक्ष में 1990-93 की शिथिलता याता अवकाश मुविद्या करने परिवार के आश्रित सदस्यों सहित शिमला से गोआ तक तथा वापसी की उपरोक्त अवकाश के दौरान व्यतीत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

शिमला-171002, 8 जनवरी, 1993

संख्या 3-15/71-डी0 पी0-नियुक्ति.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 27-12-1992 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, कृमारी परमिन्दर हीरा, भा0प्र0 से0, आयुक्त एवं सचिव (कल्याण, श्रम, मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अतिरिक्त कार्यभार मण्डलायुक्त, काँगड़ा मण्डल, धर्मशाला के अजित अवकाश दिनांक 18-1-1993 से 6-2-1993 के दौरान उनका कार्य निम्न अधिकारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त सौंपने के सहर्ष आदेश देते हैं :—

- (1) श्री योगेश खन्ना, भा0प्र0 से0 आयुक्त एवं सचिव (प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण), हिमाचल प्रदेश सरकार दिनांक 27-1-1993 से 6-2-1993 तक आयुक्त एवं सचिव (कल्याण, श्रम, मुद्रण तथा लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश सरकार के रूप में।
- (2) श्री के0 लाल, भा0प्र0 से0, मण्डलायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डा, दिनांक 18-1-1993 से 6-2-1993 तक के दौरान मण्डलायुक्त, काँगड़ा मण्डल, धर्मशाला के रूप में।
- (3) श्री पी0 मित्रा, भा0प्र0 से0, विशेष सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार दिनांक 18-1-1993 से 23-1-1993 के दौरान विशेष सचिव (कल्याण, श्रम, मुद्रण तथा लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश सरकार के रूप में।

हस्ताक्षरित/-  
मुख्य सचिव।

शिमला-171002, 12 जनवरी, 1993

संख्या का (नि-1)-बी (3)-27/78-II.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 27-11-1992 का क्रम जारी रखते हुए, भारत के राष्ट्रपति, श्रीमती सरोजनी ठाकुर, भा0प्र0 से0, विशेष सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार को 23 दिनों के अजित अवकाश दिनांक 1-1-1993 से 23-1-1993 तक व्यतीत करने के लिए दिनांक 30-12-1992 (प्रसूत) को दिल्ली में कार्यभार छोड़ने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

हस्ताक्षरित/-  
आयुक्त एवं सचिव।



शिमला-171002, 14 जनवरी, 1993

(नि०-II)

57

--

se

in

..

संख्या 3-2/75-डी० पी० नियुक्त-II.—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, श्री डी० पी० जोशी, निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश को बेतनमान रुपये 4500—6100 में निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश के पद पर दिनांक 1-9-1992 से स्थाईकरण के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
मुख्य सचिव।

शिमला-171002, 20 जनवरी, 1993

संख्या 10-7/73-डी० पी० नियुक्ति.—भारत के राष्ट्रपति फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रोतम लाल नेगी, सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल) मवाली, जिला कल्लू की कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियाँ कुल्लू जिला की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जायेंगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या : होम-वी (बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुरूप होंगी।

शिमला-171002, 21 जनवरी, 1993

संख्या का (नि-1)-ए (2)-2/90.—भारत के राष्ट्रपति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एच० एस० भोगल, नायब तहसीलदार (प्रशिक्षणाधीन) शिमला (ग्रामीण) को कार्यकारी दण्डाधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियों को तत्काल से प्रयोग करने के सहर्ष आदेश देते हैं। यह शक्तियाँ तहसील शिमला (ग्रामीण) की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रयोग में लाई जायेंगी जो कि गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों संख्या : होम-वी (बी) 12-5/84, दिनांक 4-12-1984 तथा 28-12-1984 के अनुरूप होंगी।

हस्ताक्षरित/-  
विशेष सचिव।

शिमला-171002, 22 जनवरी, 1993

संख्या 3-14/66-डी० पी० नियुक्ति.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 28-12-92 का अधिक्रमण करते हुए भारत के राष्ट्रपति, श्री अमर नाथ बिद्यार्थी, भा० प्र० सी० बितायुक्त एवं सचिव (आवकारी एवं कराधान, जन जातीय, खाद्य एवं आपूर्ति तथा सहकारिता), हिमाचल प्रदेश सरकार को 27-1-1993 से 5-2-1993 तक के आकस्मिक अवकाश के दौरान 1990—93 की रियायती यात्रा अवकाश सुविधा अपने परिवार के आश्रित सदस्यों सहित शिमला से बंगलौर तथा वापसी की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

भारत के राष्ट्रपति यह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री अमर नाथ बिद्यार्थी, भा० प्र० सी० की उपरोक्त अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पी० टी० बांगडी, बितायुक्त एवं सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार अनिवार्य रूप से करेंगे।

हस्ताक्षरित/-  
मुख्य सचिव।

शिमला-171002, 3 फरवरी, 1993

सं० कामिक (नि०-II) बी० (4)-1/92.—भारत के राष्ट्रपति डा० रामेश्वर शर्मा, सदस्य, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पक्ष में 10 दिनों का दिनांक 11-1-93 से 20-1-93 तक (9, 10-1-93 को राजपत्रित अवकाश पहले जोड़ते हुए) अर्जित अवकाश, इस शर्त के साथ कि उनके द्वारा मांगा गया अवकाश उनके खाते में बकाया है, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डा० रामेश्वर शर्मा, सदस्य, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिस स्थान से अवकाश पर गये हैं, उसी स्थान पर अवकाश से लौटने के पश्चात् कार्यग्रहण करेंगे।

आदेशानुसार,

मधु सुंदन मुखर्जी,  
मुख्य सचिव।

Shimla-171001, the 27th March, 1993

No. 3-17/66-DP-Appnt.—Consequent upon his selection for appointment as member, Central Administrative Tribunal, Calcutta Bench, the President of India is pleased to order that Shri M. S. Mukherjee, I.A.S. (H. P. 1962), Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh shall retire from Government service, at his own request, with effect from the 26th April, 1993 (A.N.) in pursuance of the provisions contained in Rule 16(2) of the All India Service (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

By order,

S. K. CHAUHAN,  
Additional Chief Secretary.

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 7 जनवरी, 1993

संख्या आयु० ख (10)-3/91.—प्रत्यक्ष खेद के साथ सूचित किया जाता है कि डा० सुख देव बाली, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, तलमेडा, जिला ऊना का आकस्मिक निधन दिनांक 7-11-1992 को हो गया है।

हस्ताक्षरित/-  
बितायुक्त एवं सचिव।

# NOTIFICATIONS

Fairlawns, Shimla-171012, the 21st December, 1987

**No. HIPA (Exam.) 5/74-XII.**—The result of the departmental examination of the Excise and Taxation Inspectors in the Excise and Taxation Department of Himachal Pradesh Government held during October, 1987 is notified as below:—

Sl. No.	Name, designation & Address	Roll No.	S U B J E C T S							Papers in which the officer has already passed			Papers in which the officer must pass in order to complete the Deptt. Exam.
			Law of Crimes	Excise Law	Law Relating to Allied Taxes	Property Tax Law & Practice	Sales Tax Law & Practice	Book Keeping & General Commercial Knowledge	Landa Script (Amritsari or Mahajani)	Session	Roll No.	Papers	
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	S/Shri												
1.	Rajesh Kumar Sharma, ETI, C.L.B.P. Mehatpur, Distt. Una.	2201	—	—	Pass	—	—	Fail	—	9/86 4/87	1106 1605	5 1,2,4,7	3,6
2.	Ram Sarup, ETI, M.P. Barrier, Kandrori, Distt. Kangra (H. P.)	2202	—	Pass	—	Fail	—	Fail	Pass	4/87	1617	1,3,5	4, 6
3.	Naresh Gupta, ETI, V & P.O. Nurpur, Naizpur (Kangra).	2203	Pass	—	—	—	—	Pass	—	9/86 4/87	1113 1613	5, 7 2,3,4	—
4.	Parshotam Chand, ETI, M.P. Barrier, Behral Distt. Sirmaur.	2204	—	Pass	—	—	—	Fail	—	9/86 4/87	1110 1618	3,4,5 1, 7	6
5.	Bhagi Rath Dhalaria, ETI, M. P. Barrier Tuna-Hatti, Distt. Chamba.	2205	Fail	Fail	Fail	Fail	Fail	Fail	Pass	—	—	—	1 to 6
6.	Rajinder Prasad, ETI, M. P. Barrier Dharwal.	2206	A	A	—	—	A	A	—	4/86 4/87	1414 1619	3, 7 4	1,2,5,6
7.	Chhatan Gutuk, ETI, Pooh Circle at Pooh, Distt. Kinnaur.	2207	A	A	—	A	—	A	—	9/86	1101	3,5, 7	1,2,4,6
8.	Manoj Kumar, ETI, M. P. Barrier Govindghat, Distt. Sirmaur.	2208	A	A	A	A	A	A	—	9/86	1114	7	1 to 6
9.	Yog Raj Sharma, ETI, C/o A. E. & T. C. Bilaspur.	2209	Pass	Fail	Pass	Fail	Fail	Fail	Fail	—	—	—	2, 4, 5, 6, 7.
10.	Santosh Kumar Sharma, ETI, Karsog, Distt. Mandi.	2210	—	Pass	—	—	—	—	—	11/82 7/85	2519 2507	3,4,5,6,7 1	—
11.	Surinder Singh Jamwal, ETI, M/s Rangar Breweries Ltd., Mehatpur, Distt. Una.	2211	A	A	A	A	A	A	A	—	—	—	1 to 7

गोपाल, हिमाचल प्रदेश, 24 दिसम्बर, 1987/4 दिसम्बर, 1915

1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Parshotam Ram, ETI, M. P. Barrier Kandwal, Teh. Nurpur, Distt. Kangra.	2212	—	Fail	Pass	—	—	—	—	4/86 9/86	1410 1119	1,4,6 5,7	2
13.	Rajinder Parshad Sharma, ETI, M. P. B. Parwanoo, Distt. Solan.	2213	—	Fail	Pass	—	—	A	—	4/86 9/86	1417 1118	1,4 7	2,6
14.	Sham Lal Negi, ETI, M. P. B. Parwanoo, Distt. Solan.	2214	—	Fail	—	—	—	Fail	—	4/83 4/86 9/86 4/87	7817 1418 1117 1610	3,5 1 7 4	2,6
15.	Ajay Kumar Awasthi, ETI, M.P. B. Parwanoo, Distt. Solan.	2215	—	Fail	Fail	—	—	Fail	—	4/86 9/86 4/87	1419 1116 1608	4,5 7 1	2,3,6
16.	Mohar Singh Hitashi, ETI, M.P. B. Parwanoo, Distt. Solan.	2216	—	Fail	Pass	—	—	Fail	—	9/85	1115	5,7	2,6
17.	Amar Nath, ETI, M. P. Barrier Goalthi, Bilaspur.	2217	—	—	Pass	—	—	—	—	1/85 7/85 9/86	2504 2515 1109	5,6 2,4,7 1	—
18.	Gopal Krishan Mehta, E T I., M. P. Barrier, Santokhgarh, Distt. Una.	2218	Fail	Fail	—	—	Fail	A	—	4/79	132	3,4,7	1,2,5,6
19.	Pratap Chauhan, ETI, Solan Brewery, Distt. Solan.	2219	—	—	—	—	—	Fail	—	9/79 7/85 4/86	1527 2513 1422	2,3,5 7 1,4	6
20.	Sher-Singh Sidhta, ETI, M. P. B. Bahral, Distt. Sirmaur, H. P.	2220	—	—	Fail	—	—	Fail	—	9/86 4/87	1105 1604	1,4,5,7 2	2,6
21.	Nag Singh, ETI, Tehog, Distt. Shimla	2221	A	A	A	A	A	A	A	—	—	—	1 to 7

NOTES :—

(i) 'A' indicates 'Absent'.

(ii) Every possible care has been taken in compiling information given in column Nos. 8, 9, 10 & 11. It is, however, possible that some mistake therein may have occurred inadvertently. All concerned are therefore requested to check the aforesaid information and to bring to the notice of the Board any mistake found therein.

Sd/-

(MRS. SHANTA CHAUHAN),

Secretary,

H. P. Board of Departmental Examinations,  
Fairlawns, Shimla-171012.



No. HIPA (Exam) 59/80-VI.—The result of the Himachal Pradesh State Electricity Board Supervisory Accounts Service (Part-II) Examination held during the month of April, 1992 is hereby notified as below :—

Sl. No.	Name and Designation with place of posting	Roll No. assigned	P A P E R S							
			Paper V Precis and Draft		Paper VI Advance Accounting and Auditing		Paper VII Industrial and Commercial Laws		Paper VIII Accounts Rules and Procedures	
			Maximum Marks	Marks obtained with %age	Maximum Marks	Marks obtained with %age	Maximum Marks	Marks obtained with %age	Maximum Marks	Marks obtained with %age
			150		200		100		200	
1	2	3	4	5	6	7				
1.	Shri Subhash Chander, Divisional Accountant, Electrical Division H. P. S. E. B., Jawali, District Kangra (H. P.).	929001	—	94** (47%) Fail	—	—	—			
2.	Shri Krishan Singh Rana, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, Baner Construction Division, H. P. S. E. B., Jia, District Kangra (H. P.).	929002	39 (26%) Fail	52 (26%) Fail	39 (39%) Fail	96 (48%) Fail				
3.	Shri Sudarshan Kumar, Divisional Accountant, Power House Civil Maintenance Division, H. P. S. E. B., Bhabanagar.	929003	50 (33.3%) Fail	98 (49%) Fail	40 (40%) Fail	80 (40%) Fail				
4.	Shri O. P. Kaushal, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, M & T Division, H. P. S. E. B., Sundernagar-174 402 (H. P.).	929004	—	75 (37.5%) Fail	—	—				
5.	Shri D. R. Sharma, Divisional Accountant, Office of the Chief Accounts Officer, F & A Wing (Pay Fixation Section), H. P. S. E. B., Vidyut Bhavan, Shimla-171 004.	929005	—	—	—	97** (48.5%) Fail				
6.	Shri Baldev Raj Gupta, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, Electrical Division, Sarka-ghat, District Mandi (H. P.).	929006	A	A	A	A				

\*\* Is required to obtain 60% marks in the next examination.

1	2	3	4	5	6	7
7.	Shri Chhaju Ram Verma, Divisional Accountant, Electrical Division, H. P. S. E. B., Nahan.	929007	68 (45.3%) Fail	60 (30%) Fail	—	—
8.	Km. Sunceta Sharma, Divisional Accountant, Transmission Division, H. P. S. E. B., Saproon Solan, Distt. Solan (H. P.).	929008	—	118** (59%) Fail	—	—
9.	Shri Krishan Chand Verma, Divisional Accountant, Electrical Division, H. P. S. E. B., Kumarsain, District Shimla (H. P.).	929009	A	A	A	A
10.	Shri Mehar Chand Sharma, Divisional Accountant, Office of the Chief Accounts Officer, Finance & Accounts Wing, H. P. S. E. B., Vidyut Bhawan, Shimla-171 004.	929010	—	107** (53.5%) Fail	—	—
11.	Shri Om Prakash Bhardwaj, Divisional Accountant, Office of the Chief Accounts Officer, F & A Wing, H. P. S. E. B., Kumar House, Shimla-171 004.	929011	35 (23.3%) Fail	33 (16.5%) Fail	41 (41%) Fail	83 (41.5%) Fail
12.	Shri Tara Dutt Sharma, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, City (Electrical) Division, H. P. S. E. B., Shimla-171 001.	929012	—	76** (38%) Fail	—	—
13.	Shri Gulshan Aggarwal, Divisional Accountant, Office of the Accounts Officer, NJPC, F & A Wing, Shakuntlam, Sanjauli, Shimla-12.	929013	—	74 (37%) Fail	—	88 (44%) Fail
14.	Shri Gita Ram Sharma, Divisional Accountant, Office of the Accounts Officer, Nathpa Jhakri Power Corporation Ltd. Jhakri (H. P.).	929014	—	84** (42%) Fail	—	—
15.	Shri Mohinder Nath Tewari, Divisional Accountant, Electrical Division, H. P. S. E. B., Jawali, District Kangra (H. P.).	929015	48 (32%) Fail	51 (25.5%) Fail	45 (45%) Fail	81 (40.5%) Fail

1	2	3	4	5	6	7
16.	Shri Manohar Lal Chandel, Divisional Accountant, Thiro Construction Division No. II, H.P. State Electricity Board, Bhuntar, District Kullu, Himachal Pradesh.	929016	50 (33.3%) Fail	84 (42%) Fail	45 (45%) Fail	—
17.	Shri Inder Singh Patial, Divisional Accountant, Parbati Investigation Division No. I, H. P. S. E. B., Sarabai, P. O Bhuntar, District Kullu (H. P.).	929017	A	—	—	—
18.	Shri Ganga Ram Thakur, Divisional Accountant, Investigation-cum-Construction Division No. I, H. P. S. E. B. Kol Dam, Sundernagar, District Mandi, (H. P.).	929018	—	85** (42.5%) Fail	—	—
19.	Shri Satish Kumar, Divisional Accountant, Banking Section, Finance and Accounts Wing, H. P. S. E. B., Vidyut Bhavan, Shimla-4.	929019	—	62** (31%) Fail	—	—
20.	Shri Ravinder Nath Sharma, Divisional Accountant, Electric Gaj and Baner Power House Division, H. P. S. E. B., Kangra (H. P.).	929020	A	A	A	A
21.	Shri Amar Singh Verma, Divisional Accountant, Finance and Accounts Wing, H. P. S. E. B., Kumar House, Shimla-171 004.	929021	31 (20.6%) Fail	A	31 (31%) Fail	56 (28%) Fail
22.	Shri Bhagat Ram, Divisional Accountant, (Electrical) Division, Manali, District Kullu (H. P.).	929022	35 (23.3%) Fail	38 (19%) Fail	25 (25%) Fail	110 (55%) Fail
23.	Shri Rattan Lal Kaundal, Divisional Accountant, F & A Wing, WAP-I, H. P. S. E. B., Kumar House, Shimla-171 004.	929023	—	50** (25%) Fail	—	—
24.	Shri Beli Ram, Divisional Accountant, Electrical Division, H. P. S. E. B., Nadaun, District Hamirpur, H. P. Pin-177 033.	929024	A	A	A	A
25.	Shri Ramesh Kumar Kaushal, Divisional Accountant, F & A Wing, H.P. S.E.B. Vidyut Bhavan, Shimla-171 004.	929025	38 (25.3%) Fail	59 (29.5%) Fail	46 (46%) Fail	95 (47.5%) Fail

\*\* Are required to obtain 60% marks in the next examination.

1	2	3	4	5	6	7
26.	Shri Mani Ram Sharma, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, Electrical Division, H. P. S. E. B. Rajgarh, District Sirmaur H. P., Pin-173101.	929026	—	A	—	—
27.	Shri Bhoop Chand Guleria, Divisional Accountant, Shimla Electrical Division No. I, H. P. S. E. B., Shimla-171 002.	929027	48 (32%) Fail	A	39 (39%) Fail	79 (39.5%) Fail
28.	Shri S. D. Sharma, Divisional Accountant, Larji Construction Division No. II, Larji, District Kullu (H. P.).	929028	—	95 (47.5%) Fail	—	—
29.	Shri Jaswant Singh, Divisional Accountant, Central Store Division H. P. S. E. B. (NJPC), Parwanoo.	929029	—	134 (67%) Pass	—	—
30.	Shri Nant Ram Kashyap, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, Bhaba Construction Division No. II, H. P. S. E. B. Katgaon, District Kinnaur (H. P.).	929030	A	A	A	A
31.	Snri Y. P. Kapoor, Divisional Accountant, Office of the Executive Engineer, H. P. S. E. B. Mandi (H. P.).	929031	68 (45.3%) Pass	98 (49%) Pass	—	95 (47.5%) Pass

ABBREVIATIONS : 'A' denotes 'ABSENT'.

Sd/-  
Secretary.

## सहकारिता विभाग

## ग्रधिसूचनाएं

शिमला-171002, 22 जनवरी, 1993

संख्या कोप-ए(2)-14/85.—भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाओं अधिनियम, 1968 (वर्ष 1969 का 3) की धारा 35(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की संमेलनक अधिसूचना दिनांक 14-12-1992 द्वारा जगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सोमित, सोहन के मंचालक मण्डल में मनोनीत दो सरकारी सदस्यों सर्वश्री राजकुमार मयूज श्री जिलोकी नाथ, डगशार्डी, डा0 डगशार्डी, तहसील व जिला सोहन तथा श्री हेत राम शर्मा सुख श्री पूर्ण चन्द, गांव बड़ाग, डाकखाना धार चण्डी, बाया दाड़नाचाट, तहसील ग्रामी गिला सोहन का मनोनयन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से रद्द करने का महर्ष आदेश प्रदान करते ।

Shimla-171002, the 22nd March, 1993

File No. Coop. A (4)-3 93.—The President of India, is pleased to constitute a Screening Committee in the office of the Registrar, Co-operative Societies, Himachal Pradesh consisting of the following members to scrutinise the sanction of funds by the State Government and the National Co-operative Development Corporation, New Delhi under Centrally Sponsored Scheme of distribution of consumer articles in rural areas:—

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Registrar, Co-operative Societies Himachal Pradesh, Shimla-9.  | Chairman          |
| 2. Joint Secretary (Co-operation) to the Government of Himachal Pradesh.                                      | Member            |
| 3. Deputy Regional Director, National Co-operative Development Corporation, Deputy Regional Office, Shimla-1. | Member            |
| 4. Deputy Registrar (Consumer) Directorate of Co-operation, Shimla-9.   | Member-Secretary. |

The above Screening Committee will meet once in a month and consider consolidated proposals of Lead and Link Societies. Minutes of meeting may be sent to the NCDC for further necessary action. The proposals in respect of Link Societies for margin money approved by the Screening Committee will be submitted to the State Government for sanction. The proposals of Lead Societies for margin money assistance will be submitted to the Regional Director, NCDC for sanction whereas the other components of assistance i.e. Transport Vehicle to the Lead Societies and Furniture and Fixtures to Lead and Link Societies will be sent to the State Government for further submission to National Co-operative Development Corporation.

By order,

A. N. VIDYARTHI,  
Financial Commissioner-cum-Secretary.

## FOREST FARMING AND CONSERVATION DEPARTMENT

## NOTIFICATIONS

Shimla-171002, the 3rd February, 1988

No. 1-18/72-SF(Estt)-II.—In partial modification of this department notification of even Number, dated 4th February, 1987, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to define the following two working Plan Divisions in the Department of Forest, Farming and Conservation in place of the Divisions earlier defined vide this

department notification of even number, dated 4th February, 1987 with immediate effect:—

Sl. No.	Name of Division earlier defined	Name of Division now defined	Name of Hqrs.
1	2	3	4
1.	Hamirpur working Plan Division.	Bharmaur working Plan Division.	Bharmaur
2.	Dharamshala working Division.	Karsog working Plan Division.	Karsog

Shimla-171002, the 12th February, 1988

No. Fts(1)B(2)3/86(Estt).—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendation of the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to accord sanction for the continuation of *ad hoc* appointment of Shri O. P. Ahlawat, Deputy Director (Statistics) Class-I Gazetted for a period of 3 months i. e. with effect from 25-11-1987 to 29-2-1988 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier. This is in continuation of this department notification of even number, dated the 29th June, 1987.

Shimla-171002 the 12th February, 1988

No. Fts(A)2-1/86.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the Deputy Director Technical (Forest) posted in the Enforcement Wing of Vigilance Department of Himachal Pradesh Government as Forest Officer to do all acts and exercise all powers of a Forest Officer under the following provision of the Indian Forest Act, 1927 and the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 1978, within the territory of Himachal Pradesh:—

Sections of the Indian Forest Act, 1927 under which powers are given	Brief description and nature of power conferred
1. Section 52	Power to seize property liable to be confiscated.
2. Section 64	Powers to arrest without warrant.
3. Section 65	Powers to release on a bond a person arrested.
4. Section 66	Powers to prevent commission of forest-offences.
5. Section 72(b)	Power of Civil Court to compel the attendance of witnesses and production of documents.
6. Section 72(d)	Power to hold an enquiry into forest-offences and in the course of such enquiry to receive and record evidence.

## Rules under which powers are given:—

- |  |   |
|--|---|
| 1. Rule 14 of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 1978 framed under section 41 & 42 of Indian Forest Act, 1927. | Power requiring persons transporting Forest Produce to produce pass/challan |
| 2. Rule 15 of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 1978 framed u/s 41 and 42 of Indian Forest Act, 1927.         | Powers for detention of Forest Produce and other articles.                  |
| 3. Rule 16 of the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 1978 framed u/s 41 and 42 of Indian Forest Act, 1927.         | Power of seizure of forest produce and other articles.                      |

Shimla-2, the 12th February, 1988

No. Fts-I (B) 10-188. The grievances of retired Government servants/employees in respect of the pensionary matters have been engaging the attention of the Government for some time past. Therefore, in order to ensure that pensionary claims of the Government servants are settled expeditiously, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to set up the Departmental Pension Adalat in the Department of Forests Farming and Conservation which shall comprise the following:—

1. Secretary (Forests)
  2. Pr. Chief Conservator of Forests.
  3. Sr. Accounts Officer/Accounts Officer of the Forest Department failing which officer concerned with pension cases.
  4. Accounts Officer from A. G. Office, if necessary (on special invitation).
2. The departmental pension Adalat shall consider the following matters:—
1. Cases of the Forest Department retirees where pension/gratuity has not been sanctioned in favour of the retiree.
  2. Wrong fixation of pension on the initial stage as a result of revision of pension against which a pensioner may have represented to the department.
  3. Other grievances relating to the pensioner of the department.
  4. Cases of such pensioners of the Forest Department who may have gone to the Court of Law for the redress of their grievances with a view to have their settlement outside the Court.
  5. Reviewing of pending pension cases in the Forest Department and finding solution to bring down pendency to minimum and expeditious settlement of pension cases.
  6. Monitoring for expeditious settlement of pension cases at level of Departmental Adalat.

3. Therefore keeping in view the above contents the cases of the retirees will be examined by the Forest Department on receipt of representation from the retirees to settle their pension cases, and thereafter will be placed before the departmental pension Adalat. But the pensioner will be at liberty to address the application to Finance Department (State Pension Adalat) or the Forest Department or both. In cases where it will not be possible to find out a solution, the case will be referred to State Pension Adalat constituted by the Finance Department vide their notification No. Fin (C) B (10)-5/87, dated 25th August, 1987.

4. The meeting of the departmental pension Adalat will be held once every month.

Shimla-2, the 18th February, 1988

No. Van. (Kha) 3-38/79(Estt)-Vol-II.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the promotion of Shri C. L. Sudhera, I.F.S., Conservator of Forests (Level-II) to Conservator of Forests (Level-I) in the pre-revised scale of pay of Rs. 2000-125/2-2250 with effect from 5th April, 1984 and thereafter with effect from 1-1-1986 in the revised scale of Rs. 4500—5700.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the above-mentioned promotion of Shri C. L. Sudhera, I.F.S., C. F. (Level-II) is subject to the decision of the court case pending against him. He will be reverted back to the lower post of C. F. (Level-II) in the event of his non-exoneration or his non-acquittal by the Hon'ble Court from the charges levelled against him due to the Court case.

Shimla-171002, the 23rd February, 1988

No. Fts.I(B)2-3/85(Estt).—In continuation of this department notification of even number, dated the 13th March, 1987, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote the following Superintendent Grade-I (*ad hoc*) on regular basis in the pay scale of Rs. 825—1530 with immediate effect:—

1. Shri Brij Lal
2. Shri Bhanu Dutt

By order.

S. S. SADHU,  
Secretary.

Shimla-2, the 23rd February, 1988

No. Fts. I (B)9-2/83 (Estt).—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to promote Shri P. L. Goswami, Supdt. Grade-I to the post of Registrar (Vigilance) Class-II Gazetted, in the pay scale of Rs. 1200-1700 purely on *ad hoc* basis with immediate effect upto 31-8-88 (*i. e.* the date of his retirement).

2. The *ad hoc* promotion will not confer any right in the matter of seniority or regular promotion upon Shri P. L. Goswami.

By order,

S. S. SADHU,  
Commissioner-cum-Secretary.

शिमला-171002, 8 जनवरी, 1993

संख्या वन-1 (बी०) 6-2/92.—भारत के राष्ट्रपति सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री एस० बी० इस्लाम, भा० व० से०, उप-अरण्याल, कण्डी परियोजना, सोलन अपने कार्य के अतिरिक्त आगामी आदेशों तक श्री एस० के० पाण्डेय, भा० व० से०, परियोजना निदेशक, कण्डी परियोजना निदेशक, सोलन का कार्य भी देखेंगे।

2. यह आदेश तत्काल लागू होंगे।

शिमला-171002, 8 जनवरी, 1993

संख्या वन-1 (बी०) 6-2/92.—भारत के राष्ट्रपति सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री जोगिन्द्र सिंह, भा० व० से०, अरण्याल (सामाजिक बानिकी) द्वितीय वृत्त धर्मशाला अपने कार्य के अतिरिक्त आगामी आदेशों तक श्री आर० ए० सिंह, भा० व० से० अरण्याल, धर्मशाला वृत्त का कार्य भी देखेंगे।

2. भारत के राष्ट्रपति यह भी आदेश देते हैं कि श्रीमती विजय लक्ष्मी तिवाड़ी, भा० व० से०, वन मण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी), शिमला अपने कार्य के अतिरिक्त आगामी आदेशों तक श्री एच० के० गुप्ता, डि० प्र० व० से०, वन मण्डलाधिकारी (भू-कार्य योजना) शिमला का कार्य भी देखेंगे।

3. यह आदेश तत्काल लागू होंगे।

शिमला-171002, 8 जनवरी, 1993

संख्या वन-1 (बी०) 6-2/92.—इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना, दिनांक 4-1-1992 में आंशिक परिवर्तन करते हुए भारत के राष्ट्रपति श्री एस० एस० खुशिल, डि० प्र० व० से०, सहायक अरण्याल, रामपुर वन मण्डल स्थानान्तरणाधीन, सहायक अरण्याल, वन मण्डल सुन्दरनगर मुख्यालय स्थित नरकाघाट की विशेष कार्य अधिकारी, अरण्याल रामपुर वृत्त तैनात करने के लोकहित में सहर्ष आदेश देते हैं।

यह आदेश तत्काल लागू होंगे।



शिमला-171002, 11 जनवरी, 1993

संख्या वन-1 (बी०) 6-2/92.—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रतीति वन सेवा अधिकारियों के लोक हिम में स्वातंत्र्य एवं नाती तत्काल करने के महर्ष आदेश देते हैं:—

प्राधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
श्री मोहिन्दर पाल, भारत सरकार में केन्द्रीय वन से०। प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर।	उप-प्रणाल (एम० एण्ड ई०), शिमला, श्री एस० एस० सेनी के स्थान पर।	
श्री एस० एस० उम-प्रणाल (एम० सेनी, भा० व० से०। एण्ड ई०), शिमला।	वन मण्डलाधिकारी (भू-कार्य योजना) शिमला, श्री हेमन्त गुप्ता, हि० प्र० व० से० के स्थान पर।	
श्री एस० डी० पनी, वन मण्डलाधिकारी, भा० व० से०। रेणुका वन मण्डल।	उप-प्रणाल, Institute of Rain and Moist Deciduous Forest Research Jorhat (Assam). (प्रतिनियुक्ति पर)	

2. भारत के राष्ट्रपति यह भी आदेश देते हैं कि श्री बिनीत पाल, भा० व० से०, वन मण्डलाधिकारी, राहुन वन मण्डल अपने कार्य प्रतिरिक्त वन मण्डलाधिकारी, रेणुका वन मण्डल का कार्यभार भी पूर्ण आदेशों तक सम्भालेंगे।

3. यह आदेश तुरन्त लागू होंगे।

आदेश द्वारा,

पी० टी० गंगदी,  
वित्तियुक्त एवं सचिव।

## FINANCE (REGULATION) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th January, 1988

No. Fin. C (A)-2-1/84-II.—In continuation of this department Notification of even number dated the 11th June, 1987, declaring Sub-Divisional Officer (Civil) Bharmaur, District Chamba as Drawing and Disbursing Officer in r/o the establishment of Food and Supplies department posted at Bharmaur, under head "2408—Food Storage and Warehousing, 01-Food (796)-Tribal area Sub Plan, 01-Expenditure on Food Organisation." the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the Sub-Divisional Officer (Civil) Bharmaur shall so function as Controlling Officer for T.A. in r/o Class I and IV officials of the Food and Supplies Department posted in Bharmaur area.

कार्यालय ज्ञापन

शिमला-171002, 4 जनवरी, 1993

1.—डोडराक्वार क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को अधिकतम ठहराव भत्ते की देयता।

संख्या फिन (सी) बी (7)-21/77-VIII.—प्रधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि शिमला जिला के डोडराक्वार क्षेत्र

में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को अधिकतम ठहराव भत्ता प्रदान किये जाने का मामला कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। मामले पर विचार करने के उपरान्त भारत के राष्ट्रपति, जनजातीय विभाग के पत्र संख्या पी एल जी (एफ) 5-8/80-टी० डी० दिनांक 7 नवम्बर, 198 एवं टी० डी० (बी) 12-5/81, दिनांक 28-11-1981 में जनजातीय क्षेत्र हेतु विहित दरों एवं शर्तों के आधार पर अधिक ठहराव भत्ते की सुविधा को जिला शिमला के डोडराक्वार तहसील एवं उप मण्डल में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 1-11-1992 से प्रदान करने के महर्ष आदेश देते हैं।

अधिकतम ठहराव भत्ते की दरें निम्नलिखित होंगी:—

1. चौथे वर्ष में .. 10 प्रतिशत मूल वेतन का
2. पांचवें वर्ष में .. 17 प्रतिशत मूल वेतन का
3. छठे वर्ष में .. 25 प्रतिशत मूल वेतन का
4. सातवें या उससे अधिक .. 35 प्रतिशत मूल वेतन का

उक्त भत्ते की न्यूनतम सीमा 50/- रुपये व अधिकतम 500/- रुपये प्रतिमास होगी। यह भत्ता उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा जो उक्त क्षेत्र के स्थाई निवासी नहीं होंगे तथा जिन्हें जन हिम में एवं सरकार के आदेशों के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में तीन वर्ष की तैनाती अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी उक्त क्षेत्र में कार्यरत रहना पड़ता है। सम्बन्धित कर्मचारियों को इस भत्ते की स्वीकृति के आदेश प्रत्येक मामले में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे तथा आहरण एवं विनयन अधिकारी उक्त भत्ते को आहरण करते समय यह प्रमाणित करेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारी का उक्त क्षेत्र में अधिकतम ठहराव जन हिम में है।

शिमला-171002, 4 जनवरी, 1993

विषय.— डोडराक्वार क्षेत्र को प्रतिपूरक भत्त की देयता हेतु ग्रुप 4 से ग्रुप 3 में प्रतिस्थापित करने बारे।

संख्या फिन (सी) बी (7)-21/77-VIII.—प्रधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला शिमला के डोडराक्वार क्षेत्र में तैनात हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते की देयता का मामला कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। मामले पर विचार करने के उपरान्त भारत के राष्ट्रपति इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी) बी (7)-21/77, दिनांक 19-8-1987 को जारी किए गए आदेशों में प्रांशिक संशोधन करने हुए डोडराक्वार तहसील/उपमंडल को ग्रुप IV के स्थान पर ग्रुप-III में प्रतिस्थापित करने के महर्ष आदेश देते हैं। जिसके फलस्वरूप वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ता वित्त विभाग के का० जा० समसंख्यक दिनांक 10-4-88 में ग्रुप-III को विहित मु० 475/- रुपये मासिक दर से देय होगा।

ये आदेश दिनांक 1-11-1992 से प्रभावी होंगे।

हस्ताक्षरित/-  
उप सचिव।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

प्रधिसूचना

शिमला-171002, 14 जनवरी, 1993

संख्या एक० डी० ए० बी० (15)-3/91.—भारत के राष्ट्रपति, इस विभाग को समसंख्यक प्रधिसूचना दिनांक 24 जनवरी, 1992 की निरन्तरता में श्री एस० जी० नेगी, उप-निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में प्रबन्धक (कार्यिक) के पद पर बने रहने हेतु दिनांक 2-1-93 से 1-1-94

सक एक वर्ष प्रतिनियुक्ति समय बढ़ाने के लिए, इस विभाग के पत्र संख्या एफ0 डी0 एस0-बी0 (2) (15) 1/90, दिनांक 1-8-1990 में दो गई व्रतमान निबन्धन एवं शर्तों पर स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

शिमला-171002, 18 फरवरी, 1993

सं0 एफ0 डी0 एस0-ए0 (4)-5/87.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0-ए0 (4)-5/87, दिनांक 27-2-91 के क्रम में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 68) की धारा 16(2) के अन्तर्गत जो हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1988 के उप-नियम 14 के साथ पढ़ा जाए, में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा मल्होत्रा, एम0 ए0 एल0 एल0 डी0 को 27-2-93 से हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध "राज्य व्यापार" की सदस्या अंशकालीन आधार पर सहर्ष नियुक्ति करते हैं, जिसकी शर्तें व निबन्धन निम्न प्रकार से होंगी :—

1. श्रीमती प्रतिभा मल्होत्रा को प्रतिदिन प्रति सुनवाई के लिए मंजूर मानदेय रु0 250/- रुपये (दो सौ पचास) केवल दिए जाएंगे।
2. श्रीमती प्रतिभा मल्होत्रा दो वर्ष की अवधि तक सदस्या के पद पर रहने की पात्र होंगी।
3. श्रीमती प्रतिभा मल्होत्रा, यात्रा व दैनिक भत्ता प्रदेश सरकार के उच्चतम ग्रेड-1 के अधिकारियों को दिए जाने वाली यात्रा व दैनिक भत्ते की दरों के बराबर प्राप्त करने की हकदार होंगी।

इनकी नियुक्ति की दूसरी शर्तें व निबन्धन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 व हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही निहित होंगी।

आदेश द्वारा,

अमर नाथ बिद्यार्थी,  
वित्तियुक्त एवं सचिव।

#### GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (C-SECTION)

#### NOTIFICATION

Shimla-2, the 26/29th January, 1988

No. GAD (2)(B) 5/82-GAC.—The Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Hon'ble Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is pleased to appoint Shri L. S. Kashyap, HPAS as Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha in place of Shri V. Verma, with effect from 1-2-1988, on deputation basis.

B. C. NEGI,  
Chief Secretary.

#### HOME (B) DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd February, 1988

No. Home-II (B) 2-2/81.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Ram Murti Bisht, Advocate, as Law Officer in the office of the Advocate

General, Himachal Pradesh, in the pay scale of Rs. 825—1580 (Class-II) per month, on *ad hoc* basis, for six months purely on temporary basis or till the time, the post is filled up in accordance with the rules for the said post whichever is earlier.

2. This *ad hoc* appointment shall not confer upon Shri Ram Murti Bisht any right for continuation, seniority or regular appointment.

Shimla-2, the 23rd, February, 1988

No. Home-II (B) 2-3/80-II.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri M. L. Chauhan, Law Officer in the office of the Advocate General, Himachal Pradesh as Assistant Advocate General (Class-I) in the pay scale of Rs. 2000—2300 per month, on *ad hoc* basis, for six months purely on temporary basis or till the time, the post is filled up in accordance with the rules for the said post whichever is earlier.

2. This *ad hoc* appointment shall not confer upon Shri M. L. Chauhan any right for continuation, seniority or regular appointment.

KANWAR SHAMSHER SINGH,  
Commissioner-cum-Secretary.

अनुभाग-डी

शिमला-2, 29 दिसम्बर, 1992

संख्या होम-डी (बी-2)-14/86-भाग-5.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-12-1992 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-12-1992 का क्रम जारी रखते हुए श्री राम लाल-I, एम0 डी0 पी0 ओ0, नूरपुर, जो उप-पुलिस अधीक्षक (अवकाश आरक्षण) कांगड़ा को स्थानान्तरणाधीन हैं, के स्थानान्तरण आदेश जनहित में तत्काल रद्द करने के सहर्ष आदेश करते हैं। उनके प्रतिस्थानी श्री बालक राम, उप-पुलिस अधीक्षक (नव-पदोन्नत) को अब उप-पुलिस अधीक्षक (अवकाश आरक्षण) कांगड़ा में तैनात किया जाता है।

आदेश द्वारा,

एम0 एस0 मुखर्जी,  
मुख्य सचिव।

शिमला-2, 6/12 जनवरी, 1993

संख्या गृह-11 (बी) 15-19/77.—भारत के राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के निम्न वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों/मण्डल आदेशक (श्रेणी-I) को वेतनमान 3000-100-4000-125-5000 रुपये में तत्काल (कनफर्म) स्थाई करने के आदेश देते हैं :—

1. श्री बी0 एम0 थापा, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रशासन)।
2. श्री जे0 एस0 ठाकुर, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्र0 व0 ओ0)।
3. श्री के0 के0 दीदी, मण्डल आदेशक, धर्मशाला।

एस0 एस0 परमार,  
आयुक्त एवं सचिव।

#### OFFICE ORDER

Shimla-171002, the 13th January, 1993

Subject.—Final Seniority list of Commandants/Junior Staff Officers of Home Guards & Civil Defence Department Himachal Pradesh as on 31-8-1992.

No. HOME-B (B) 13-1/86.—As per the decision in O. A. No. 119/88 of the Hon'ble Administrative Tribunal Shimla on 22-11-1991 to quash seniority list of Commandants/Junior Staff Officers circulated vide this department letter No. 6-58/70-Home, dated 29-6-1983 and to re-draw this seniority list as on 31-1-1982.

In view of above, the final seniority list of Commandants/Junior Staff Officer of Home Guards & Civil Defence Department as on 31-8-1992 is hereby circulated for the information of all concerned.

No representation against this list will be entertained except for clerical omission/mistake or mistakes of the like nature if any, which may be intimated within 15 days from the date of circulation.

# FINAL SENIORITY LIST OF COMMANDANTS/JUNIOR STAFF OFFICERS OF HOME GUARDS & CIVIL DEFENCE DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH AS ON 31-8-1992

Sl. No.	Name of the Officer	Date of birth	Date of joining the Govt. Service/Date of appointment	Date of Confirmation	Remarks
1	2	3	4	5	6
	S/Shri:				
1.	V. S. Thapa	5-3-40	13-8-70	13-12-73	Promoted as SSO.
2.	J. S. Thakur	16-1-42	13-8-70	13-12-73	Promoted as SSO.
3.	K. K. Didi	2-7-43	18-9-70	13-12-73	Promoted as Divisional Commandant.
4.	T. S. Paul	7-1-38	4-2-74	24-12-76	Promoted as Divnl. Commandant.
5.	K. S. Pundir	25-9-40	3-6-74	28-9-77	Promoted as Commandant Training Junga on ad hoc basis.
6.	Jai Lal Manta	10-8-37	7-8-75	8-2-85	
7.	Bahadur Singh Tomar	20-6-39	4-1-82	8-2-85	
8.	J. R. Sharma	1-7-39	1-1-82	8-2-85	
9.	Ajay Kumar Katoch	6-2-47	24-4-78	8-2-85	
10.	Upendra Singh	15-7-40	1-1-82	8-2-85	
11.	Brij Lal Gautam	21-5-41	20-7-83	Temporary	
12.	Rakesh Kumar Sharma	19-5-58	16-4-86	-do-	
13.	Deepak Katyan	9-4-42	15-12-86	-do-	
14.	Birender Singh Paul	13-9-49	21-1-88	-do-	
15.	Ranbir Singh Rana	1-2-45	28-8-91	-do-	

NARENDER CHAUHAN,  
Joint Secretary.

## (SECTION-D)

## NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th February, 1993

No. Home. D (B-3)-4/92.—The President of India is pleased to order that during the probation period, Shri Prem Kumar Thakur, Himachal Pradesh Police Service (Probationer) shall remain attached to Police Training School, Junga for practical training etc.

Sd/-  
Commissioner-cum-Secretary.

## CORRIGENDUM

Shimla-171002, the 26th March, 1993

No. Home-B(B)13-1/86.—Please read in the serial No. 3 date of birth of Shri Rakesh Kumar Sharma, Commandant 19-8-1958 instead of 19-6-1958 in the second page of Final Seniority List of Commandant/Junior Staff Officer of Home Guards and Civil Defence Department, Himachal Pradesh on 31-1-1992, which has been circulated vide this department of even number dated 13-1-1993.

NARINDER CHAUHAN,  
Joint Secretary.

आवास विभाग

अतिरिक्त

शिमला-2, 23 जनवरी, 1993

संख्या आवास-1 (ए) 0-3/80.—राष्ट्रपति, भारत सरकार इस विभाग के समस्त अधिकारियों को 20 सितम्बर, 1990,

5 जनवरी, 1991, 27 अप्रैल, 1991 तथा 26 जून, 1992 का अधिकारण करते हुए और हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972, धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का निम्नलिखित रूप में पुनर्गठन करते हैं अर्थात् :—

1. सलाहकार (पी) अध्यक्ष
2. आयुक्त एवं सचिव (वित्त) सदस्य
3. नितायुक्त एवं सचिव (आवास) सदस्य
4. वित्तायुक्त एवं सचिव (स्वायत्त प्रशासन विभाग) । सदस्य
5. प्रमुख अभियन्ता, सिविल एवं जन स्वास्थ्य सदस्य
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सदस्य
7. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग सदस्य
8. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता आवास बोर्ड सदस्य सचिव

आवास बोर्ड का मुख्यालय शिमला में स्थित होगा ।

आदेश द्वारा,

एस० एस० सिद्ध;  
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

## HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th January, 1988

No. Health-B (9) 6/85.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendation of Departmental Promotion Committee, is pleased to confirm the following Professors, Associate Professors and Assistant Professors in the pay scale of Rs. 1500-2500, 1200-1900 plus Rs. 100/- special pay and Rs. 1200-1900 respectively

from the dates shown against each :—

शिमला-171 002, 12 दिसम्बर, 1991

Sl. No.	Name of the doctor	Department	Post against which confirmed	Date of confirmation
1.	Dr D. J. Dassgupta	Medicine	Profes-	22-7-82
2.	Dr. (Mrs.) Tara Gupta	Ob & Gyana.	-do-	4-5-86
3.	Dr. R. C. Sharma	Skin & VD	-do-	4-5-86
4.	Dr Yogender Mohan	Psychiatry	-do-	4-5-86
5.	Dr. R. K. Sexena	E. N. T.	-do-	22-7-82
6.	Dr. D. V. Behl	C.T.S.	-do-	31-5-86
7.	Dr. S. K. Bansal	Medicine	Ass.	22-7-82
8.	Dr L. S. Paul	-do-	Prof.	4-5-86
9.	Dr. B. K. Goel	Ophthalmology	-do-	22-7-82
10.	Dr. M. L. Sharma	E.N.T.	-do-	30-9-83
11.	Dr. (Mrs.) Raj Puri	Physiology	-do-	22-7-82
12.	Dr. D. N. Sharma	Pathology	Asstt. Prof.	12-9-82
13.	Dr B. B. Sharma	-do-	-do-	13-12-82
14.	Dr. (Mrs.) Jai Shree Sharma.	-do-	-do-	28-7-87
15.	Dr. S. R. Thakur	Orthopaedics	-do-	12-9-82
16.	Dr. Mrs. Suman Sharma.	Medicine	-do-	12-5-83
17.	Dr. B. S. Prashar	-do-	-do-	28-2-84
18.	Dr. Surinder Kashyap	-do-	-do-	8-10-87
19.	Dr. V. Bansal	Ophthalmology.	-do-	2-3-82
20.	Dr. N. L. Sharma	Skin	-do-	4-9-82
21.	Dr. Chander Mohan	E.N.T.	-do-	16-3-87
22.	Dr. R. M. Pathak	Bio-	-do-	7-6-82
23.	Dr. P. K. Nanda	Chemistry.	-do-	10-7-81
24.	Dr. B. P. Gupta	Physiology PSM	-do-	1-6-82

The above confirmations do not indicate the order of seniority.

AJAY PRASAD,  
Secretary.

शिमला-2, 6 दिसम्बर, 1991

क्रमांक हेल्थ-बी (3)-89/87.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर जगदीप सिंह राणा को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रुपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियमित रूप से दिनांक 23-1-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर जगदीप सिंह राणा 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेगा।

शिमला-2, 10 दिसम्बर, 1991

क्रमांक हेल्थ-बी (3)-49/91.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर जगतार सिंह को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रुपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियमित रूप से दिनांक 31-1-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर जगतार सिंह 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेगा।

शिमला-2, 12 दिसम्बर, 1991

क्रमांक हेल्थ-बी (3)-49/87.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर राजेन्द्र सिंह जम्वाल को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रुपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियमित रूप से दिनांक 22-1-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर राजेन्द्र सिंह जम्वाल 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेगा।

क्रमांक हेल्थ-बी (3)-28/91.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर अनिल कुमार गोयल को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रुपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियमित रूप से दिनांक 8-3-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर अनिल कुमार गोयल 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेगा।

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 1991

संख्या हेल्थ-बी (3)-18/90.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर विजय कुमार शर्मा को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रुपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियमित रूप से दिनांक 2-3-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर विजय कुमार शर्मा 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेगा।

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 1991

संख्या हेल्थ-बी (3)-60/90.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर धनश्याम उपाध्याय को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियम 9 के अधीन रुपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियमित रूप से दिनांक 16-1-1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डाक्टर धनश्याम उपाध्याय 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेगा।

आर० के० यानन्द,  
विभागीय एवं सचिव।

शिमला-2, 11 मार्च, 1991

संख्या हेल्थ-बी (3)-50/80-II.—विभागीय कमेटी की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डाक्टर दीना नाथ शर्मा को स्वास्थ्य सेवा नियमों 1974 के नियम 9 के अधीन रुपये 4500—7300 के वेतनमान में आचार्य पेथोलोजी के एक पद पर नियमित रूप से दिनांक 24-1-1991 से नियुक्त करते हैं। डाक्टर दीना नाथ शर्मा दो वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेगा।

हस्ताक्षरित,  
सचिव।

शिमला-2, 6 जनवरी, 1993

संख्या एच० एफ० डब्ल्यू० बी० (एफ०) 2-5/88-II.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5-4-90 का अधिकरण करते हुए राष्ट्रपति, भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र परियोजना (UNFPA) को सूचारु रूप से कार्यान्वित करने हेतु निम्न निर्दिष्ट सदस्यों को राज्य स्तरीय शासी निकाय (Governing Body) का सदस्य गठन करते हैं:—

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश                                      | अध्यक्ष   |
| 2. सहायकार राज्यपाल (के)  | उपाध्यक्ष |
| 3. मुख्य सचिव, हि० प्र० सरकार                                   | सदस्य     |
| 4. सचिव (वित्त)   | सदस्य     |
| 5. सचिव (योजना) हि० प्र० सरकार                                  | सदस्य     |
| 6. सचिव (स्वास्थ्य) हि० प्र० सरकार                              | सदस्य     |
| 7. सचिव (शिक्षा) हि० प्र० सरकार                                 | सदस्य     |
| 8. सचिव (ग्रामीण विकास) हि० प्र० सरकार                          | सदस्य     |
| 9. सचिव (लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य एवं विचार) हि० प्र० सरकार | सदस्य     |
| 10. सचिव (कल्याण) हि० प्र० सरकार                                | सदस्य     |
| 11. उप सचिव (स्वास्थ्य) हि० प्र० सरकार                          | सदस्य     |
| 12. निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हि० प्र०                           | सदस्य     |
| 13. प्रमुख अभियन्ता (लो० नि०) हि० प्र०                          | सदस्य     |
| 14. प्रमुख अभियन्ता (जन स्वास्थ्य एवं विचार) हि० प्र०           | सदस्य     |

- |  |               |   |
|--|---------------|---|
| 15. निदेशक, योजना, हि० प्र०              | सदस्य         | पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश करते हैं। यह पदोन्नति तत्काल में प्रभावी होगी। |
| 16. निदेशक, कल्याण, हि० प्र०             | सदस्य         |   |
| 17. निदेशक, ग्रामीण विकास, हि० प्र०      | सदस्य         |   |
| 18. निदेशक, शिक्षा, हि० प्र०             | सदस्य         |   |
| 19. निदेशक, परियोजना, यू० एन० एफ० पी० ए० | सदस्य-प्रतिन। | 2. डाक्टर एस० सी० शर्मा दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।               |

इस तिकार की बैठक छह मास में एक बार होगी तथा इसका कार्य निम्न होगा :—

शिमला-171002, 30 मार्च, 1993

- (i) परियोजना प्रगति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने वाले समीक्षा।
- (ii) जातीय तिकार द्वारा परिवार कल्याण एरिआ परियोजना की नीति सम्बन्धी मामले तय करना।
- (iii) परिवार कल्याण हेतु परियोजना की मुख्य अन्तर विभागीय समस्याओं का निवारण तथा परियोजना कार्य के लिए राज्य कोष से धन तथा वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का जुटाना।

3. जात्रा देनित अस्ता जहां देय हो वह सदस्य अपने सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करेंगे।

अमर नाथ विद्यार्थी,  
वित्तायुक्त एवं सचिव।

शिमला-2, 6 जनवरी, 1993

संस्था हेल्थ-बी (3) 184/91.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, डा० सुभाष चन्द्र चौहान को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियमों के नियम 9 के अधीन रुपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा द्वितीय श्रेणी के एक पद पर नियमित रूप से दिनांक 9-7-1992 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। डा० सुभाष चन्द्र चौहान 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

शिमला-2, 11 जनवरी, 1993

संस्था स्वास्थ्य-बी (3) 2/93.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय, डा० प्रीतम सिंह शर्मा को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियमों के नियम 9 के अधीन रुपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा द्वितीय श्रेणी के एक पद पर नियमित रूप से दिनांक 2-7-1992 से नियुक्त करते हैं। डा० प्रीतम सिंह शर्मा 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

शिमला-2, 14 जनवरी, 1993

संस्था हेल्थ-बी (3)-1/93.—राष्ट्रपति महोदय, डा० (श्रीमती) चेतना, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, जनरल ड्यूटी अधिकारी प्रेड-II के पद पर 2250—4000 रुपये के वेतनमान में अनुबन्ध आधार पर छः माह के लिए 25-7-1992 से या तब तक के लिए जब तक कि आसामी नियमित रूप से नहीं भरी जाए, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

Shimla-2, the 26th March, 1993

No. Health-B(3)123/89.—The President of India is pleased to accept the resignation of Dr. Kanwar Singh, Dental Surgeon w. e. f. 7-1-93 (A.N.).

शिमला-171002, 30 मार्च, 1993

संस्था हेल्थ-बी (2) 2/93.—राष्ट्रपति महोदय, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर डाक्टर एस० सी० शर्मा, सहायक प्राचार्य (दन्त विभाग), इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाय नियम, 1974 के उप-नियम 9(8) (1) के अधीन छह माह महाविद्यालय में दन्त विभाग में ही प्राचार्य के रूप में रु० 4500—7300 के वेतनमान में

क्रमांक हेल्थ-बी (3) 76/91.—हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय, डाक्टर खिमा राम शर्मा को स्वास्थ्य सेवा के 1974 के नियमों के नियम 9 के अधीन रुपये 2250—4000 के वेतनमान में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा द्वितीय श्रेणी के पद पर नियमित रूप से दिनांक 21-12-1992 (पूर्वाह्न) से नियमित नियुक्त करते हैं। डाक्टर खिमा राम शर्मा दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

हस्ताक्षरित/-  
वित्तायुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य)।

## INDUSTRIES DEPARTMENT

### NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 5th January, 1988

No. Udyog (Chh) 21-14/82 (TPT).—In supersession of this Government notification No. Udyog (Chh) 21-14/82, dated 22-3-1985, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute with immediate effect the State level Committee consisting of the following in order to settle all claims of transport subsidy arising in the Pradesh, under the Transport Subsidy Scheme, 1971 of the Central Government :—

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Director of Industries, Himachal Pradesh.   | Chairman          |
| 2. Joint Secretary (Fin.)/Deputy Secretary (Fin.) to the Government of Himachal Pradesh. | Member            |
| 3. Deputy Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh.                  | Member            |
| 4. Deputy Director of Industries/Senior Technical Officer, Himachal Pradesh.             | Member Secretary. |

Shimla-171002, the 8th February, 1988

No. Udyog-II (Chh) 11-11/87.—In pursuance of sub-section (1) of Section 7 of the State Financial Corporation Act, 1951 (LXIII of 1951), the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Board of Directors of Himachal Pradesh Financial Corporation, Shimla and based on the advice of the Industrial Development Bank of India, hereby fixes the rate of interest, currency of bonds, and issue price on the bonds of the value of Rupees 100.00 lacs (Rupees one crore) only with an option to retain 10% excess subscription to be issued by the Himachal Pradesh Financial Corporation during the year 1987-88 :—

Currency of bonds	15 years.
Issue price	Rupees 100/- per bond worth Rupees 100/- (At par).
Rate of interest	11% per annum.
Brokerage and Underwriting commission.	12 paise and 38 paise respectively. per Rupees 100/-

2. This issues with the prior concurrence of F. D. obtained vide Dy. No. 141-Fin-8/88, dated the 29th January, 1988.

Shimla-171002, the 8th February, 1988

No. Udyog-II (Chh) 11-11/87.—In exercise of powers as contained in sub-section (1) of Section 7 of the State Financial Corporations Act, 1951 (LXIII of 1951), the

5  
—  
S  
i  
c

Governor, Himachal Pradesh is pleased to guarantee the repayment of principal and payment of interest thereon in respect of bonds of the value of Rupees 100.00 lacs (Rupees one crore only) with a right to retain 10% extra subscription over the notified amount to be issued by the Himachal Pradesh Financial Corporation with the prior approval of the Industrial Development Bank of India after observing all codal formalities.

2. The Corporation will pay guarantee fee at the usual prescribed rate of 0.5% and commitment charges (i.e. 0.1% on the total guaranteed amount and furnish a copy of challan to this department. Finance Department and the Director of Industries within one month from the issue of this notification or the availment of money whichever is earlier.

3. This issues with the prior concurrence of F. D. obtained vide their Dy. No. 141-Fin-8/83, dated the 29th January. 1988.

By order,

O. P. YADAVA.  
Commissioner-cum-Secretary.

शिमला-2, 3 दिसम्बर, 1991

संख्या उद्योग (ख) 9-1/84-स्था.—भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत निदेशालय उद्योग, हिमाचल प्रदेश में नियुक्तियुक्त सैन में औद्योगिक मैन्सज के कार्य हेतु महा प्रबन्धक (सैन्सज) के पद का निरन्तरिकरण की स्वीकृति न होने के फलस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री मस्त राम शर्मा, महा प्रबन्धक (सैन्सज) को महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लाहौल-स्पिति के रिक्त पद पर समायोजित करने के तत्काल सहर्ष आदेश करते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, यह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि श्री मस्त राम शर्मा, महा प्रबन्धक, उद्योग निदेशालय में लाहौल-स्पिति के महा प्रबन्धक के पद के विरुद्ध तैनात किये जाते हैं, जब तक कि लाहौल-स्पिति का रोहतांग बरौ न खुले।

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 1991

संख्या उद्योग (ख)-2-3/87-एस्ट.—जबकि श्री अशोक शर्मा, खनन अधिकारी, को सोलन से मण्डी को इस विभाग की अधिसूचना मम संख्या दिनांक 16-9-1991, द्वारा स्थानान्तरण किया गया था ;

जबकि श्री अशोक शर्मा, खनन अधिकारी के उक्त स्थानान्तरण आदेशों को इस विभाग की अधिसूचना मम संख्या दिनांक 20-11-1991, द्वारा रद्द किया गया था, और श्री मदन लाल, खनन अधिकारी, को सोलन से मण्डी स्थानान्तरण किया गया था ;

और जबकि श्री मदन लाल, खनन अधिकारी, द्वारा माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण शिमला, में उनके स्थानान्तरण के विरुद्ध याचिका संख्या: 1724/91 दायर की गई है जिस पर माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, शिमला, ने अन्तिम आदेश दिनांक 22-11-1991, को श्री मदन लाल, खनन अधिकारी के सोलन से मण्डी किये गये स्थानान्तरण पर रोक लगा दी है तथा सोलन में कार्यरत रहने के आदेश किये हैं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, के अन्तिम आदेशों के पालना हेतु, श्री मदन लाल, खनन अधिकारी, के सोलन से मण्डी के स्थानान्तरण आदेशों को रद्द करने तथा श्री अशोक शर्मा, खनन अधिकारी, के सोलन से मण्डी के स्थानान्तरण आदेशों को माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम आदेश तक बहाल रखने के सहर्ष आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,

बी० बी० टाकन,  
विभागाध्यक्ष एवं सचिव।

## IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

### NOTIFICATIONS

Shimla-171002, the 30th January, 1988

No. IPH (4)-15/85.—In continuation of this Department Notification of even number dated the 6th October, 1987, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to extend the period of High Level Committee to scrutinise the recurring claims of compensation for the loss of crops, gharats and private land due to diversion of water as a result of construction of Shah-Nehar Project by the Punjab Government upto 31-12-1988.

The Committee may kindly scrutinise/finalise its recommendations within the aforesaid period and sent its report to the Government before 31-12-1988 positively.

By order,

A. N. VIDYARTHI.  
Secretary.

Shimla-2, the 9th February, 1988

No. IPH-4 (1)-41/87.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the High Powered Committee for the purchase of Non-Levy Cement in the Department of Irrigation and Public Health Himachal Pradesh consisting of the following with immediate effect :—

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Minister of State (Welfare and I. P. H.) Himachal Pradesh. | Chairman          |
| 2. Secretary (I. P. H.)                                       | Member            |
| 3. Secretary (Food and Supplies)                              | -do-              |
| 4. Director of Industries, Himachal Pradesh.                  | -do-              |
| 5. Special Secretary (Finance)                                | -do-              |
| 6. Chief Engineer (I. P. H.), Himachal Pradesh.               | Member Secretary. |

The function of the High powered Committee :

1. All the proposals for the purchase of Non-Levy Cement of the Department is to be submitted to the Committee for consideration and their recommendation thereof before the case is sent to the Government for approval and expenditure sanction.

By order,

A. K. MOHAPATRA,  
Secretary.

## LAW DEPARTMENT

### OFFICE ORDER

Shimla-2, the 9th February, 1988

No. LLR-B (4) 3/76-II.—In exercise of the powers vested in him under F. R. 25, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to allow Shri George, Assistant District Attorney-cum-PP, to cross the efficiency bar at the stage of Rs. 1200/- in the pay scale of Rs. 825-25-850-30-1000/40-1200/50-1400-60-1580 w. e. f. 1-8-87 thus raising his pay to Rs. 1250/- P. M. w. e. f. 1-8-1987 F. N.

Sd/-  
Secretary.

### NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 17th February, 1988

No. LLR-B (3) 3/74.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under Rule 56(d) of the F. Rs, is pleased to grant further extension in service for a period of three months from 1-2-1988 to 30-4-1988 in public interest to Shri Shiv Lal Yaidya, Deputy Director (Prosecution) Himachal Pradesh, whereafter he shall stand retired from Government service.



2. This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U. O. No. F-54-Fin (C)-B (7)13/83, dated 18-1-1988.

भाषा एवं संस्कृति विभाग

आधिसूचना

Shimla-2, the 24th February, 1988

शिमला-2, 29 जनवरी, 1988

Subject.—Constitution of Departmental Pension Adalat.

No. LLR-A(1)1/87.—In order to ensure that pensionary claims of Government servants settled expeditiously, the Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute a Departmental Pension Adalat in the Law Department which shall comprise of the following:—

1. Secretary (Law)
2. Joint Director (Prosecution)
3. Deputy Director (Prosecution)
4. Accounts Officer from A. G. Office, if necessary (on special invitation).

2. The following matters shall be considered by the said Departmental Pension Adalat:—

1. Cases of the Law Department's retirees where pension/gratuity has not been sanctioned in favour of retirees.
2. Wrong fixation of pension on the initial stage as a result of revision of pension against which a pensioner may have represented to the Department.
3. Other grievances relating to the pensioners of Law Department.
4. Cases of such pensioners of Law Department who may have gone to the court of law for the redress of their grievance, with a view to have their settlement outside the court.
5. Reviewing of pending pension cases in that Department and finding solutions to bring down pendency to minimum and expeditious settlement of pension cases.
6. Monitoring for expeditious settlement of pension cases.

3. The meeting of the said Adalat will be held once every month, if necessary.

शिमला-171002, 11 फरवरी, 1993

संख्या एल०एल० आर० बी० (1)-2/78-II.—भारत के राष्ट्रपति, अभियोजन विभाग, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिला न्यायवाधियों के निम्न प्रकार से तुरन्त स्थानान्तरण के जनहित में सहर्ष आदेश देते हैं:—

क्रम अधिकारी का सं०	वर्तमान तैनाती नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	प्रस्तावित स्थानान्तरण	टिप्पणी
1.	श्री जे० सी० कपूर	जिला न्यायवादी, प्रवर्तन (वन)। सतकंठा।	जिला न्यायवादी, श्री कुलवन्त सिंह, जिला न्यायवादी के स्थान पर।	
2.	श्री कुलवन्त सिंह	जिला न्यायवादी, सतकंठा। प्रवर्तन (वन)।	कपूर, जिला न्यायवादी के स्थान पर।	

संख्या-भाषा-एफ- (4)-2/84.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्न व्यक्तियों को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-1-1987 द्वारा स्वतन्त्रता सेवानिवृत्ति पर इतिहास लिखने के लिए गठित स्क्रॉनिंग कमेटी में सदस्य के रूप में मनोनीत करने को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. डा० ए० आर० खान, .. सदस्य  
प्राध्यापक (इतिहास), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला।
2. नियाँ गंधर्वन सिंह, .. सदस्य  
लाइब्रेरियन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला।
3. श्री अमर चन्द शर्मा, .. सदस्य  
115-2 पुरानी मण्डी, मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

उक्त सदस्य उपरोक्त कमेटी के सदस्य होने के नाते उन्हीं शर्तों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिकी भत्ता लेने के हकदार होंगे जिनका व्यौरा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-1-1987 के साथ लगे परिशिष्ट में दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

इसे वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश की डायरी संख्या एफ-89-फिन-सी-बी (15)-10/87 दिनांक 19-1-1988 द्वारा प्राप्त पूर्व स्वीकृति के साथ जारी किया गया है।

परिशिष्ट "अ"

T. A. AND D. A.

The T. A. and D. A. to the non-official members will be paid in the following manners:

1. (i) (a) TRAVELLING ALLOWANCES:

(b) Journey By Rail:

They will be treated at par with Government servants of the first grade and will be entitled to actual rail fare of the class of the accommodation actually used, but not exceeding the fare to which government servants of the first grade are normally entitled i. e. accommodation of the highest class, by whatever name it may be called, provided on the railway by which the journey is performed.

(ii) Journey By Road:

They will be entitled to actual fare for travelling by single seat in a bus, and if the journey is performed by motor/cycle/scooter mileage allowance at 60 paise per km in plain areas and @ 80 paise per km in the hill areas and if the journey is performed by engaging own car, taxi the member will be entitled to mileage allowance @ Rs. 2/50 per km in hilly areas and @ Rs. 2.50 per km in plain areas.

(iii) In addition to the actual fare or mileage as per item (i) and (ii) above, a member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence beginning with departure from the place and ending with return to that place, at the same rate and subject to the same terms and conditions as apply to Grade-I officers to the State Government.

2. DAILY ALLOWANCE:

(iv) Non-official members will be entitled to draw daily allowance for each day of the meeting at the highest rate as admissible to a Government servant of the first grade for the respective locality.

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
सचिव।

(v) In addition to daily allowance for the day(s) of the meeting, a member shall also be entitled to daily allowance for halt on tour at out station in connection with the affairs of the Committee as under:—

- (a) If the absence from headquarter does not exceed Six hours ... Nil.
- (b) If the absence from headquarters exceeds six hours but does not exceed twelve hours ... 70%.
- (c) If the absence from headquarter exceeds Twelve hours ... Full daily.

Daily allowance will be subject to the usual conditions laid down in Supplementary Rules 1973 as amended from time to time.

### 3. CONVEYANCE ALLOWANCE:

A non-official member, resident at place where the meeting of the committee is held will not be entitled to travelling and daily allowance on the scale indicated above but will be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to a maximum of Rs. 10/- per day. Before the claim is actually paid, the controlling officer should verify the claim and satisfy himself after obtaining such details as may be considered necessary, that actual expenditure was not less than the amount claimed. In case he is not satisfied with the details, he may, at his discretion, limit the conveyance allowance to road mileage.

If such member uses his own car, he will be granted mileage allowance at the rates admissible to officials of the first grade, subject to a maximum of Rs. 10/- per day.

The travelling and daily allowances will be admissible to a member on production of a certificate by him to the effect that he has not drawn any travelling or daily

allowance for the same journey and halts from any other government sources.

The non-official members will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meeting of the Committee from and to the place of their permanent residence to be named in advance. If any member performs journey from a place other than the place of his permanent residence to attend meeting of the Committee or return to place other than the place of his permanent residence after the termination of the meeting, travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance actually travelled or the distance between the place of permanent residence and the venue of the meeting, whichever is less.

The provision of rules 4.17 and 6.1 of the Himachal Pradesh Treasury Rules relating to over payments made to government servants will apply *mutatis mutandis* in the case of over payment made on account of Travelling Allowance to non-official members.

The Director, Language and Culture, Himachal Pradesh, Shimla will be Controlling Officer in respect of countersigning of the Travelling Allowance bills of the non-official member and T. A. bills shall also be prepared in his office.

**Official Members.**—The official members shall be entitled to the T. A. and D. A. according to the rules governing them.

अ.देश द्वारा

महाराज कृष्ण काव,  
वित्तायुक्त एवं संचव ।

अम विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 फरवरी, 1993

संख्या: 19-8/90-अम-V.—भारत के राष्ट्रपति, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करने हुए पंडासीन अधिकारी, अम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश द्वारा निम्नलिखित मामलों में दिए गए अर्बाईज को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करने के सहर्ष आदेश देते हैं:—

क्रम सं०	केस नं०	सम्बन्धित पक्षों का नाम	धारा	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	रैफ-107/91	प्रकाश चन्द बनाम मैसर्ज विद्यार्थ सुपर सप्लिंग मिलज लि०, नालागढ़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	धारा 10	प्रकाशन हेतु
2.	रैफ-123/90	दिलबहार खां बनाम मैसर्ज आयशर ट्रेक्टर लि०, सैक्टर 2, परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	"	"
3.	रैफ-62/91	जगदीश चन्द व अन्य बनाम वन मण्डल अधिकारी, पालमपुर, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश।	"	"
4.	रैफ-106/91	प्रीतम चन्द बनाम —अज्ञोपरि—	"	"
5.	रैफ-13/92	सुरिन्द्र सिंह बनाम अधिशासी अभियन्ता निर्माण कक्ष, क्षेत्रीय इंजिनियरिंग कालेज, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।	"	"
6.	रैफ-68/86	तोप चन्द बनाम मैसर्ज वैरा स्थूल प्रोजेक्ट मूरगानी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।	"	"
7.	रैफ-74/92	अश्वान दाम बनाम अधिशासी अभियन्ता सिविल कन्स्ट्रक्शन मण्डल, एच० पी० ए० 30 ई० बी०, कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	"	"
8.	रैफ-23/87	प्रेम सिंह रावत बनाम मै० सलेजा केबलज प्रा० लि० मेहतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।	"	"
9.	रैफ-79/90	सुभाष कुमार बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, एच०आर०डी०सी० नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।	"	"

1	2	3	4	5
10. रैफ-27/88	मन्देशी वीरि सिंह व मूरता राम बनाम अनामिका अभियन्ता व अधिकांसी अभियन्ता, शानन पावर हाऊस, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हि० प्र०।		धारा 10	प्रकाशन हेतु
11. रैफ-93/91	मनोजीति बनाम मै० जे०के० लैटराईज प्रा० लि०, महेतपुर, जिला ऊना, हि० प्र०।		"	"
12. रैफ-16/90	दलेन सिंह बनाम मै० चानना स्टील ट्यूबज प्रा० लि०, परवाणू, जिला सोलन, हि० प्र०।		"	"

अदेशानुसार,  
१० दौरा,  
आयुक्त एवं सचिव।

**Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla**

Ref. 107/91-

Parkash Chand

.. Petitioner.

*Versus*

M/S Sidhartha Saper Spinning Mills, Ltd. Nalagarh, District Solan (H.P.).

.. Respondents.

Sari Parkash Chand, Petitioner in person.

Shri Arun Parohit, Authorised Representative of the respondents.

**AWARD**

1. The parties have arrived at a settlement amicably. The respondent management has agreed to pay Rs. 15,000/- (Fifteen thousand) only to the petitioner in full and final settlement of his claim. In view of this settlement arrived at between the parties amicably, the petitioner has also given up the claim of service with the respondent management forthwith including any other claim which according to the petitioner is not pending at this stage. In the light of the aforesaid settlement arrived at between the parties as per statements made by them in this court to-day and also in the light of the proposals given by this court earlier during its Circuit at Balagarh and accepted by the respondent management at that time, no dispute now survives between the parties. The petitioner has also no objection if the aforesaid amount is deposited in the fixed deposit for a period of one year by the respondent management in the name of the petitioner. The respondent management is directed to ensure under intimation to this court that the aforesaid amount is deposited in the fixed deposit for a period of one year in the name of the petitioner and Fixed deposit pass Book is handed over to him. The petitioner will not be entitled to withdraw this amount for a period of one year from to-day except with the permission of this court in the event of dire necessity. Reference is answered accordingly in terms of the aforesaid settlement arrived at between the parties. Award is passed. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette of H.P. Rajpatra in accordance with the law. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. A copy of this award be given to the parties free of costs, if applied for by them. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 1st day of February, 1993, in open court at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,  
Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh,  
Shimla. 1-2-1993.

**Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla**

Ref.-Case-123/90-

Dilbahar Khan

.. Petitioner.

*Versus*

M/S Eicher Tractors, Ltd.,  
Sector-2, Parwanoo, District  
Solan (H.P.).

.. Respondents.

Shri A. K. Sharma, Authorised Representative of the petitioner.

Shri V. K. Gupta, Authorised Representative of the respondents.

**AWARD**

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla via its notification, dated the 17th April, 1990, referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 (Hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:-

"Whether the action of the management of M/S Eicher Tractors, Pvt., Ltd., Sector-2, Parwanoo, District Solan (H.P.) in terminating the services of Shri Dilbahar Khan after taking into consideration the enquiry report is legal and maintainable? If illegal, what relief and amount of compensation, Shri Dilbahar Khan is entitled to?"

2. Shri Dilbahar Khan, petitioner was employed by one Shri Abdul Hamid Contractor of the respondent management through one Shri Kamrudin Munshi of the Contractor. In other words, the petitioner alleges that he was employed by the Contractor Shri Abdul Hamid on 25-11-1985 @ Rs.600/- per month for the work to be done in connection with the management of the Eicher Tractors, Pvt., Ltd., Parwanoo. The petitioner claims himself to be a trade unionist and as such the respondent framed the false charges against him and thereafter terminated his services on 9-1-1990. He further alleges that no enquiry was conducted by the respondents in consonance with the principles of natural justice. He claims his re-instatement with all the consequential benefits including back wages.

3. The respondent filed the written statement alleging that enquiry was conducted in consonance with the principles of natural justice by appointing Shri V. K. Gupta as the Enquiry Officer and due opportunity was given to the petitioner to defend his case before the enquiry officer but he did not participate in the enquiry proceedings on 23-12-1989 at Parwanoo and was thereafter proceeded ex-parte. The Enquiry Officer on the charges against the petitioner with respect to beating of one Shri Kamrudin Munshi and other charges regarding not attending duties on 3-10-1989 and 4-10-1989 in heat

treatment furnished were established against the petitioner by the Enquiry Officer. The enquiry officer also found that the reply to the show cause notice was also not given by the petitioner. After considering the enquiry report, Abul Hamid Contractor terminated the services of the petitioner as he found the charges were of serious nature and were proved during the course of enquiry. The plea of the second respondent is that there is no relationship of master and servants between the parties. The matter under dispute cannot be adjudicated upon in these proceedings *qua* the respondent management. The allegations of *mala fide* and union activities on the part of the petitioners have been denied, by the respondent No. 2. From the pleadings of the parties the following issues were framed by me on 4-2-1991:—

1. Whether the petitioner has been terminated by not following the principles of natural justice in the matter of holding the enquiry against him? ..(O.P.P.).
2. Relief.

#### 4. FINDINGS ON ISSUES :

##### Issue No. 1 :

The petitioner has placed on record the evidence of P.W. 1 Shri Dilbahar Khan petitioner as his own witness stating that he was not allowed by the Enquiry Officer to take the help of Shri A. K. Sharma in assisting his case and as such he absented from the enquiry proceedings. He also states that there is another ground also for absenting from the enquiry proceedings in view of non-changing of the enquiry officer on account of lack of his impartial character in conducting the enquiry and he had no faith in him. The respondent management produced and placed on record the enquiry report. Abul Hamid also made an offer to the petitioner that he would adjust the petitioner at Faridabad on the same pay as there is no work at Parwanoo but the petitioner declined the offer of the respondent management. The respondent management also produced R.W. 1 Shri Kamrudin Munshi supporting the allegations of the respondent management against the petitioner. He further states that the petitioner is working in SOR Company in sector-5, Parwanoo. The respondent of the petitioner has submitted that enquiry was not conducted in consonance with the principles of natural justice, as he was not allowed to assist the petitioner in the enquiry proceedings. I am unable to agree with the petitioner representatives' contention as the petitioner was offered assistance of a co-worker working with the same management. The enquiry was also held at Parwanoo for the convenience of the petitioner but he did not participate in the enquiry proceedings there also on 23-12-89. The venue was shifted from Chandigarh to Parwanoo at the request of the petitioner. The petitioner was aware of the date and did not participate in the enquiry proceedings at Parwanoo on 23-12-1989 intentionally. The statements of the eye witnesses were also recorded by the Enquiry Officer i.e. Gyasudin and Mahinder Pal regarding the misconduct of the petitioner. They have also supported the case of the respondent management/contractor regarding beating and non attending of duties etc. Enquiry report cannot be set aside unless it is unreasonable and perverse. This is not the case in the present enquiry proceedings. Regarding fairness of the Enquiry Officer as alleged by the petitioner, I also find no reasons to hold that it is a biased enquiry merely on the grounds that he happened to conduct this case in the Labour Court as he conducted the enquiry in this case. The petitioner himself admits that he has no dispute with the enquiry officer. There is no bar in Industrial Law regarding conducting enquiry by a senior officer and defending the case by that officer. In the facts and circumstances of this case and considering the attitude and conduct of the petitioner, I find no merits in this case and the same is dismissed. I would advise the union leaders not to allow the *ex-parte* enquiry proceedings to be held forthwith and they would persuade the workers rather educate them to participate in the enquiry proceedings so that the workers could be granted relief in reasonable cases and

ends of justice may be met. I, therefore, for the reasons recorded decide this issue against the petitioner and in favour of the respondent management.

#### 5. RELIEF :

In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award in favour of the respondent management and against the petitioner holding the termination of the petitioner fully legal and justified by the respondent management in the acts and circumstances of this case and the petitioner is not entitled to any relief at this stage. Reference is answered accordingly in negative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H. P. Rajpatra in accordance with the law. A copy be given to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 27th day of January, 1993, at Shimla.

R. K. MAHAJAN,  
Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh,  
Shimla. 27-1-1993.

Seal.

Before Shri R.K. Mahajan, Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref-62/91-

Jagdish Chand and others ..Petitioners.

Versus

Divisional Forest Officer, Palampur, District Kangra (H.P.) ..Respondent

Shri Ajay Dogra, Authorised Representative of the petitioners.

Shri S.L.Sharma, Authorised Representative of the respondents.

#### AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated the 10th May, 1991, referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. (Hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

“Whether the termination of services of S/Shri Jagdish Chand and Kuldip Kumar workers by the Divisional Forest Officer, Palampur, District Kangra (H.P.) is legal and justified? If illegal, to what relief and amount of compensation, the above daily wages workers are entitled?”.

2. The petitioner, Shri Jagdish Chand and the other Shri Kuldip Kumar have grievances against the respondent management that their services were terminated by the respondent management on 2-7-1990 and 10-8-1990 respectively without following the proper procedure as required under section 25F of the Act. Shri Kuldip Kumar's version is that he worked with the respondent management for six years in the nursery as Mali on daily wages and acquired skill in the trade and an experience certificate to that effect was also given to him by the respondent department, which is placed on record. Similarly, Shri Jagdish claims that he was employed as a Mali by the respondent department in 1984 and he was shunted out from service on 2-7-1990 arbitrarily. He was also given an experience certificate by the respondent department which is placed on record as Ex-P.W. 2/A.

Shri Kuldeep Kumar has admitted that the nursery was wound up. Similarly, Jagdish Chand has deposed that no junior was kept at Marinda Nursery. They pray for their re-instatement with all consequential benefits including back wages.

3. The version of the respondent is that the department required seasonal labour for seasonal work depending upon the availability of funds etc. and other factors. The petitioners were employed in nursery i.e. at Rakh in case of Kuldeep Kumar from May, 1985 till August, 1990 as daily wages casual worker with intermittent breaks in service. He was also told verbally to work in the nearby nurseries when there was no work at Rakh Nursery but he declined to do so. Similarly, Shri Jagdish Chand, petitioner, who was working at Nagri was removed on account of reduction of work as he was junior-most. From the pleadings of the parties, the following issues were framed by me on 23-1-1992:—

1. Whether the petitioners have been terminated by the management without any justification? If so, its effect? ..(OPP).
2. Relief.

#### 4. FINDINGS ON ISSUES:

##### Issue No. 1 :

At the very outset, I would like to point out that with the efforts of this court and reasonable attitude of the respondent department, the petitioner Shri Jagdish Chand has been adjusted at Marinda Nursery by the department though the petitioner wanted to be adjusted within the area very very close to his native place which was not at all possible. Marinda is only at a distance of 8 kilometres on foot and 17 kilometres by bus from the native place of the petitioner. Similarly, Shri Kuldeep Chand was also adjusted at Rakh Nursery. Mr. Dogra, representative of the petitioners has only submitted that back wages and be awarded and the petitioners be regularised in accordance with the law. The respondent has opposed his contention on the grounds that there are budgetary constraints and it also depends upon the availability of the work. The department has assured that there will not be any termination except in accordance with law. I am unable to accept the submissions of Mr. Dogra on the following reasonings. Firstly, the work of a nursery is of a seasonal nature. Secondly, the department has been offering them the jobs in the nearby nurseries and the petitioners were not inclined to accept the offers. Thirdly, the respondent department has accommodated them to the best possible extent but they were not happy in spite of all this and it is not always possible for the department to accommodate the petitioners at the places of their choice. The Government is to give the work within its limits of economic capacity and right to work is a qualified right depending upon the economic limitations and their factors. The respondent department has also assured that there will not be any termination except in accordance with law. Moreover, I have also found that no junior person to the petitioners has been kept by the respondent department. In view of this, I am of the view that it is not a case of termination but is a case of unwillingness of the petitioners to join as revealed from the material placed on record. I, therefore, see no force in the claim of the petitioners and the same is dismissed. I, therefore, for the reasons recorded decide this issue against the petitioners and in favour of the respondent department.

##### 5. RELIEF:

In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the respondent management and against the petitioners. They are not entitled to any relief at this stage. Reference is therefore, answered accordingly in negative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatri in accordance with the law. A copy be given to the parties free of

costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion. Announced on this 23rd day of October, 1992, at Shimla.

Scal. R. K. MAHAJAN,  
Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh,  
Shimla. 23-10-1992.

Before Shri R. K. Mahjan, Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref.-106/91

Pritam Chand

.. Petitioner.

Versus

Divisional Forest Officer, Palampur, District Kangra (H.P.) .. Respondents.

Shri Ajay Dogra, Authorised Representative of the Petitioner.

Shri Rakesh Sood, Divisional Forest Officer, Palampur, Authorised Representative of the respondents.

#### AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated the 7th October, 1991, referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

“Whether the action of the Divisional Forest Officer, Palampur, District Kangra (H.P.) in keeping Shri Pritam Chand away from service w.e.f. 10-8-89 to 9-7-1991 without any notice and reasons and then to re-employ him on the same post and place, w.e.f. 10-7-1991, is legal and justified? If not, to what amount of compensation and service benefits, Shri Pritam Chand is entitled?”.

2. Shri Pritam Chand, petitioner claims that he was working as a chowkidar on daily wages basis with the respondent department w.e.f. 1986 till 10-8-1989 when he was discharged from duties arbitrarily by the respondents as alleged by him. He further alleges that he has been working honestly, diligently and to the best of his ability and his services were recognised and appreciated. He claims that his services were terminated on 10-8-1989 and he was again re-employed on 10-7-1991 by the respondent department. Keeping him away from service for two years has been described to be illegal by the petitioner. He prays that past services may be regularised as he has completed 240 days of continuous service and he may be given all the consequential benefits including wages of Rs. 37/- per day instead of Rs. 22/- per day on the doctrine of “Equal pay for equal work”.

3. The case of the respondent department as appears from the written statement and statement of R. W. 1 Shri Jai Chand Katoch, Forest Ranger is that he was employed as chowkidar on temporary basis till regular chowkidar was appointed vide annexure “B”. Annexure “D” shows that the petitioner was offered the work on daily wages elsewhere on the appointment of a regular chowkidar but he declined the offer. The letter is dated 15-3-1991 placed on record. Annexure “E” dated 17-7-1989 is an order from the Divisional Forest Officer, Palampur showing that since a regular chowkidar has been appointed at Kosri and as such the daily wages chowkidar be removed immediately. Annexure “F” shows that the regular chowkidar was appointed. The plea of the department that the petitioner was appointed as daily wages chowkidar and duty of the chowkidar is to protect the property of the department and to look it

after. In other words, it was a make shift arrangement till the appointment of a regular chowkidar by the respondent department. It is also alleged that the petitioner also refused to work in the nursery where he was offered the alternative work. From the pleadings of the parties, the following issues were framed by me on 19-2-1992:

1. Whether the petitioner has been terminated illegally? (OPP).
2. Whether the petitioner has not been paid the wages of chowkidar as alleged? (OPP).
3. Relief.

#### 4. FINDINGS ON ISSUES:

##### Issue No. 1 & 2:

Both these issues are inter-connected and would be disposed off together in order to avoid the duplicity in discussion.

5. Mr. Dogra has submitted on behalf of the petitioner that the termination of the petitioner is unjustified and he be paid the wages of chowkidar as he was doing the job of a chowkidar with the respondent department. The plea of the respondents is that the petitioner was entitled to the wages of a daily wages labourer and that has already been paid to him during "Make Shift Arrangement". The petitioner has adduced evidence by producing P. W. 1 Sri Pritam Chand, petitioner himself as his own witness and respondent has produced R.W. 1, Sri Jai Chand Katoon, Forest Ranger. The respondent has also placed on record the muster-rolls of the year, 1987 for 10/87 showing that the petitioner was paid emoluments of water and ward and not of chowkidar. Other muster rolls also reflect the same versions of the respondent department. Later on, with the efforts of this court, and the reasonable attitude of the respondent department, the petitioner has been adjusted. I am unable to agree with the contention of the representative of the petitioner that he has been terminated illegally by the respondents. It was a case of *ad hoc* arrangement and such appointment does not confer any right on the petitioner for regularisation especially when the regular incumbent has been appointed. He was made aware of the terms of the appointment. The record also shows that the petitioner was not willing to accept the offer of appointment given to him by the respondents for alternative work. He was only appointed as a temporary labourer. Moreover there is no specific reference regarding determination of the status of the petitioner. In view of his adjustment so his assertion that he was kept away from service, is not correct. I do not find any force in his claim petition on merits or otherwise and the same is, therefore, dismissed. I, therefore, for the reasons recorded decide both these issues accordingly in favour of the respondent department and against the petitioner.

#### RELIEF:

6. In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the respondent department and against the petitioner. The petitioner is not entitled to any relief at this stage. Reference is, therefore, answered accordingly in negative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra in accordance with the law. A copy be also given to the parties free of costs, to be paid for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 23rd day of October 1992 at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN  
Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh,  
Shimla. 23-10-1992.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer, Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref. 13/92—

Surinder Singh

.. Petitioner.

Versus

Executive Engineer, Construction Cell, Regional Engineering College, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)  
.. Respondents.

Sari Surinder Singh, Petitioner in person.

Non for the respondents.

#### AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated the 2nd April, 1992, referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

"Whether the termination of services of Shri Surinder Singh, former Morter Mate w.e.f. 18-9-1990 without any reason and without any notice by the Executive Engineer, Construction Cell, Regional Engineering College, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.) is legal and justified? If not to what amount of compensation and service benefits, Shri Surinder Singh is entitled?"

2. The petitioner, Sari Surinder Singh alleged that he was employed by the respondent firstly as beldar upto 22-4-1987 on daily wages and continued upto 25-11-1987. From 26-11-1987, he was given the muster-roll of Morter Mate at the rates prevalent at the relevant times and he worked with the respondent as such upto 10-9-1990. His grievance is that he was shunted out from service by the respondent on 18-9-1990 without any rhyme and reasons. No enquiry was held. No notice was given. No retrenchment compensation was also given to him. He claims back wages as he has completed 240 days of continuous service with the respondent besides the continuity of service. He further says that termination has not been done by following the proper procedure under section 25(F) of the Act.

3. Written statement was filed by the respondents and it has been stated that in November, 1991, offer was given to the petitioner to work as beldar but he declined the said offer and as such he is not entitled for full wages on the principle of, "No work, no pay". The petitioner failed to reply some specifications of ratio of Cement Morter and thereafter he was terminated by the respondent department for his incompetence in the public interest w.e.f. 19-9-1990. It is further alleged by the respondents that he was offered the job of beldar before leaving the service but he was not inclined to work as beldar. The respondent did not attend the Court inspite knowledge of the date and was as such proceeded *ex parte* on 19-11-1992 and 10-12-1992, after framing the issues. The Court vide its order, dated 6-7-1992 directed the respondent management to keep him as a beldar without prejudice to the rights of both the parties in the present dispute and I was informed that the respondent kept him as beldar by virtue of the court order. I have recorded the statement of the petitioner *ex parte* and the petitioner has established his claim by making a statement on oath. There is also certificate on the record showing that the petitioner worked as a Morter Mate. In my view, Morter Mate is higher than the Beldar irrespective of wages and skill. Even Superintending Engineer has found some defects and he should have given memo of explanation to the petitioner and an opportunity to be heard which has not been done in this case. It is also a violation of principles of natural



justice. I, therefore, for the reasons recorded quash and set aside the termination of the petitioner by the respondent management on this ground also as well according to the petitioner, Suresh Kumar, Junior to have been kept by the respondents and according to the petitioner, still one post is lying vacant with the respondent management.

#### 4. RELIEF :

In view of my above findings, I pass an award accordingly in favour of the petitioner and against the respondent department holding the petitioner entitled for the re-instatement along with the continuity of service to him in such a manner as if his services were not terminated. He is however, not entitled any back wages except to the compensation of Rs. 2,000/- (Two thousand) only in lieu of back wages and in case he has joined as a beldar in pursuance of this court order, dated 6th July, 1992, the amount be adjusted accordingly. This would, however not, disturb the amount of compensation, only the difference of wages between Master Mate and beldar is to be paid to the petitioner, for the relevant period of the different works done by him from the date of joining reference is answered accordingly in affirmative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H. P. Rajpatra in accordance with law. A copy of this award be also given to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 23rd day of December, 1992 at Shimla.

Sd/-

R. K. MAHAJAN,  
Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh,  
Shimla. 23-12-92.

Before Shri R.K. Mahajan, Presiding Officer, Labour Court,  
Himachal Pradesh, Shimla

Ref. Case-68/86

Teep Chand

.. Petitioner.

Versus

M/s Baira Sieul Project, Surangani, District Chamba,  
(H. P.) .. Respondents.

Shri Teep Chand, Petitioner in person.

Shri V. K. Gupta, Authorised Representative of  
the respondents.

#### AWARD

The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated 31-3-1986, has referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:-

"Whether the termination of services of Shri Teep Chand, Ex-beldar by the Management of M/s Baira Sieul Project, Surangani, District Chamba (H. P.) is justified and in order? If not, to what assistance and exact amount of compensation, Shri Teep Chand is entitled?"

2. The petitioner, Shri Teep Chand claims that he was employed by the respondent management as beldar in the year, 1976 i.e. on 20-5-1976 on daily wages. He was appointed as work-charged on 18-6-1979 in the same capacity on 29-11-1982, as revealed from the statement of the petitioner, he suffered an injury on the same date and was taken to Surangani Hospital for treatment and remained under treatment there from 30-11-1982 to

8-12-1982. He further states that he remained on medical leave upto 7-4-1983 and has been sending leave applications from 14-12-1982 onwards on different dates. He approached the respondent management for joining the duties on 8-4-1983 with a medical fitness certificate. He approached again and even reported to the Executive Engineer of the respondents to join duty but the later refused to accept the joining report of the petitioner and he handed over his joining report to the Head Clerk against a receipt. Head clerk happened to talk to the Executive Engineer on telephone at Tissa and on receipt of the instructions from the Executive Engineer from Tissa, the petitioner was asked to join at Tissa. He joined on 9-4-1983 at Tissa vide annexure P. 2 placed on record. He has further alleged that he has worked at the residence of the Executive Engineer from 9-4-1983 to 30-4-1983 and he became very upset when he came to know that he was not being marked as present by the authorities. He approached the Sub-Divisional Officer on this aspect and Sub-Divisional Officer told him that he could be marked present from 30-4-1983 onwards only and not prior to that. He represented to the Chief Engineer of the respondent Project on 2-5-1983, vide P. 3 (Annexure) but of no avail. The petitioner states to have been shocked on 24-5-1983 when he received a termination letter from the respondent management. Termination order is dated 5-5-1983. Thereafter he has been running from pillar to post for justice but of no avail. He prays for his re-instatement in the service of the respondent management with all consequential benefits including back wages. It may be mentioned also that the petitioner approached the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh but Hon'ble High Court vide its order placed on record and mentioned in the petition as well dismissed the writ petition filed by the petitioner on the grounds that adjudication was a question of facts and his case may be considered sympathetically. The petitioner has also described his termination illegal arbitrary and unjust as he was not given opportunity to be heard as provided under the standing orders of the Management to explain his absence. The dismissal has also been described as illegal for want of an enquiry in consonance with the principles of natural justice for overstay on leave. It may be mentioned at the very outset that the respondent management employed him before the present termination on sympathetic grounds as he remained absent at different reasons and time mercy was shown to him. I am told that the petitioner has been given mercy treatment four times on earlier occasions for condoning his fault and re-employed him. The respondent management was ready for settlement with the petitioner by paying Rs. 10,000/- (Ten thousand) only to him in full and final settlement of his claim in lieu of service considering the litigious attitude of the petitioner and also to bring harmony and peace but the petitioner declined the offer of the respondent management.

3. The case of the respondent management as revealed from the written statement filed by them as well as from the evidence of Shri Anil Gaikwarh, Personnel Manager of the respondents is that the petitioner remained absent for more than 600 days between 18-6-1979 to 23-4-1983 vide copies of the service record placed on record by the respondents vide EX. R.W. 1/A. The petitioner never came on duty from 9-12-1982 after the production of the medical certificate from Project hospital w.e.f. 13-11-82 to 8-12-82. On 8-4-1983, the petitioner did not report for duty. The petitioner got entered falsely in the office record an application to the effect that he was not allowed to join duty on 9-4-83. On 23-4-1983, the petitioner was again informed to join duty but he did not join at all. Both parties have placed voluminous correspondence on record, especially the petitioner. After receiving the report from the Assistant Manager to the effect that the petitioner was not working and was absent, his services were terminated by the respondent management. Copy of the report is EX. R.W. 1/B. From the pleadings of the parties, the following issues were framed by my learned predecessor on 3-8-1986:-

1. Whether the termination of services of the petitioner are in accordance with the law and the

rules governing his condition of service ? If so, to what effect ? (OPR).

## 2. Relief

4. Later on, the amended pleadings were filed by the parties and the following additional issue was framed by me on 24-4-1991:—

A Whether real dispute has been referred, as the petitioner has abandoned the service ? (OPR).

## 5. FINDINGS ON ISSUES.

Issue No. 1 and 1-A.

Both the above issues are inter-connected and would be disposed off together in order to avoid the duplicity in discussion.

6. Mr. Teep Chand, petitioner has placed on record voluminous correspondence and also has appeared in the witness box as his own witness stating that his services were terminated unlawfully and without justification and he was not taken on duty by the respondent management with a view to harm him. He has also produced P.W. 2, Parkash Chand Sharma, who has stated that he received the copies submitted by the petitioner dated 9-4-1983 as Work Assistant and then submitted the same to the Head Clerk Documents is EX. P. W. 4/A. It is also in his evidence that he cannot say if the petitioner came in office on 8-4-1983 as alleged by him. P.W. 2, Shri Gulam Mohammad is a witness regarding supply of medicines for three days to the petitioner and has proved slip to that effect as EX. P.W. 2/A. It is admitted by the respondent management that he got manipulated the application regarding his joining of duties by him submitting the same to the Head Clerk. Actually, he did not join the duty before the Sub-Divisional Officer or the Executive Engineer. He has made false allegations against the respondent management that he was not allowed to join the duty in the facts and circumstances of the case.

7. The respondent management informed the petitioner on 23-4-1983 to join the duty but he did not join at all. The respondent management took a lenient view and gave him employment on compassionate grounds four times on earlier occasions as mentioned in the earlier part of this award. The management had no remedy except to inform the petitioner to join duty or in the event of his failure to do so, the contract of employment automatically expires. It has been argued by the petitioner that he was not given an opportunity to explain his case before the respondent management. This plea has been coined up by the petitioner afterthought and cannot be accepted, especially taking into consideration the background of his past service record of closure rate of absenteeism. The plea of the petitioner that he was shocked to learn that he was not marked present by the SDO when he was working with the XEN, cannot be believed as the SDO can not dare the superiors, if the petitioner does not join duty even after the receipt of the information as stated by the management's witness, R.W. 1, the only inference is that he is not interested to join the service. The management sent a letter to the petitioner on 23-4-1983 to join duty but he did not join. What more could be expected from the management in such situation. This is evident from the termination order served on the petitioner dated 5-5-1983. The respondent management promised in this order to regularise the period of absence of the petitioner from 6-12-1982 to 22-4-1983 on submission of the application supported by a medical evidence certificate by the petitioner which he did not do at all. The petitioner remained silent in May, 1983 and then started giving noticed to the respondent management and in the end of June, 1983 for redressal of his grievances. I think that under these circumstances and the situation created by the petitioner besides the evidence adduced in this court, the respondent management is fully justified in terminating the services of the petitioner. The respondent management gave him the opportunities to explain his conduct

by way of informing him from time to time to join duties besides employing him four times on earlier occasions on compassionate grounds in spite of his conduct as mentioned *ibid*. Since he was not interested in joining the duties, the provisions of section 17 of the Model Standing Orders are not attracted in his case. It would be a travesty of justice if a situation is created by a worker and application of section 17 is sought then in such circumstances, it would amount to put a premium on an indisciplined and habitual unbecoming conducts of the worker. In my view, real dispute is nothing but that of the termination of the petitioner by the respondent management which has been upheld above. I, therefore, for the reasons recorded decide both these issues against the petitioner and in favour of the respondent management.

## 8. RELIEF :

In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the respondent management and against the petitioner holding that the petitioner is not entitled to any relief at this stage in the facts and circumstances of this case. Reference is answered accordingly in negative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh Shimla-2, for its due publication in the official Gazettee i.e. H.P. Rajpatra in accordance with the law. A copy of this award be given to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 28th day of January, 1993, at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,  
Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh,  
Shimla 28-1-93.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer,  
Industrial Tribunal, Himachal Pradesh, Shimla

Ref.-74/92—

Bhagwan Dass

..Petitioner.

Versus

Executive Engineer, Civil Construction Division,  
Himachal Pradesh State Electricity Board, Kunihar,  
District Solan (H.P.).  
..Respondents.

Shri J. C. Bhardwaj, Authorised Representative of the petitioner.

Shri S. P. Sharma, Authorised Representative of the respondents.

## AWARD

The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated the 19th August, 1991, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

1. "Whether the retrenchment of Shri Bhagwan Dass s/o Shri Jagat Ram by the Executive Engineer, HPSEB, Civil Construction Division, Kunihar w.e.f. 24-5-1990 is legal and justified ? If illegal, to what relief and amount of compensation, Shri Bhagwan Dass is entitled ?"
2. "Whether the action of the Executive Engineer, HPSEB, Civil Construction Division, Kunihar in taking 22 workers back in service and ignoring Shri Bhagwan Dass Mistry is justified and in order ? If not, to what relief and amount of compensation, Shri Bhagwan Dass is entitled ?"

2. Shri Bhagwan Dass, petitioner alleges that he was employed by the respondent management as a mistry grade on 21-10-1986 and he had enjoyed a good record of service as a mistry. The respondent despite large number of pending construction works on account of paucity of funds issued retrenchment notices dated 24-5-90 to the petitioner along with other co-workers without rhyme and reasons. It is also alleged that no reason was communicated to the workers. Later on, it appears that the Government withdrew retrenchment order *vide* letter dated 14-8-1990 through its Secretary. In other words, Government expressed unwillingness to retrench the workers and it is further alleged that the petitioner was not taken on duty whereas other 22 workers were taken on back duty and as such the management has committed unfair labour practice. The petitioner prays for his re-instatement with all consequential benefits as the provision of section 25 F&H were not followed by the respondent management.

3. The case of the respondent management is that the respondent along with other workers was served notice of termination but later on, it was withdrawn *vide* Ex. RW. 1/A. It is also pleaded that the respondent was offered job to the petitioner of beldar which was available with him but he declined to accept the offer. From the pleadings of the parties the following issues were framed by me on 15-11-1991:

1. Whether the termination of the petitioner is not justified and legal? (OPF).

2. What is the effect of withdrawal of termination order dated 21-8-1990 *qua* the petitioner by the Management? (OPR).

3. Relief.

#### 4. FINDINGS ON ISSUES:

Both the above issues are inter-connected and would be disposed off together in order to avoid the duplicity in discussion.

5. It is admitted fact that notice of termination was taken back by the respondent management as admitted by Shri Bhagwan Dass, petitioner, who appeared as PW. 1 as his own witness. It is also in dispute that all the co-workers were allowed to join duty *vide* Ex. R. 1. Mr. Bhardwaj's submission that he was not allowed to join the duty and given the work of mason grade-I, cannot be accepted on the following reasons. Firstly, the retrenchment notice was issued as there were no funds available with the respondent management to continue their services. Later on, it was assured by Secretary of the respondent Board *vide* Ex. P.W. 1/B that the workers would not be retrenched as adequate funds would be placed at the disposal of the Chief Engineer of the respondent Board *vide* Ex. R.W. 1/A, it was ordered by the Assistant Executive Engineer, Kuniher that the workers who have not received compensation, they would not be retrenched and would be absorbed on the job. There is a letter, dated 21-8-1990 from the Assistant Engineer, Kuniher to workers that alternative job as daily paid labourers can be made available to them and in this letter, the name of the petitioner also appears. The reason mentioned was absence of sufficient funds. Again the petitioner was also informed to join duty on 25-9-1990 with reference to the earlier letter of dated 21-8-1990 and a time of one week was given to him to join duty failing which the offer was to be treated as cancelled. Bhagwan Singh petitioner did not join. The respondent management is still ready to take him as beldar and adjust him as a mistry depending upon the availability of the work. In my view, the worker is asking something which is not within the means of the management. The management is to offer the job within its economic means and not beyond that. The plea of the Mr. Bhardwaj that the provisions of section 25F and H were not complied with by the management, is not valid as one month's notice as required under the rules was given to the petitioner and that later on the termination notice was withdrawn by the management.

The offer of retrenchment compensation as required under section 25(F) was also made *vide* letter, dated 24-5-1990. Before this event was to happen, the retrenchment notice was withdrawn by the respondent management and offer for alternative job available with the management at that time was made to the petitioner which was not accepted by him and as such the compliance of section 25(F) of the Act has also been fully made. In fact, the termination orders were nullified by the management and the workers including the petitioner were given benefit of adjusting them suitably against the available jobs. In industrial law, the workers are made to work against the particular assignments and as soon as that assignment is over, their services can be terminated by following the proper procedure of section 25(F) etc. If the management has no job work to be given to the workers, the workers cannot compel the management to provide the work against that job. He is only entitled to get the benefit under section 25(F) of the Act. In the facts and circumstances of this case, the worker is not entitled to any relief at this stage. The management is to offer him a job if he likes to work as a beldar as and when available with the management and offered to him depending upon the availability of work with them. I, therefore, for the reasons recorded decide both these issues accordingly in favour of the respondent management and against the petitioner.

#### 6. RELIEF :

In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the respondent management and against the petitioner. He is not entitled to any relief at this stage. The parties are left to bear their own costs of these proceedings. A copy of this award be given to the parties free of costs, if applied for by them. A copy be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra in accordance with the law. The file be consigned to the record room after its due completion. Announced on this 22nd day of December, 1992, at Shimla.

R. K. MAHAJAN,  
Presiding Officer,

Seal.

Labour Court, Himachal Pradesh,  
Shimla-2. 22-12-1992.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer  
Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref. Case-23/87

Prem Singh Rawat.

..Petitioner.

Versus

M/S Salecha Cables, Pvt. Ltd., Mehatpur, District  
Una (H.P.).

..Respondent.

Shri Prem Singh Rawat, Petitioner in person.

Non for the respondents.

#### AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla *vide* its notification, dated the 17th January, 1987, referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

“Whether the termination of Shri Prem Singh Rawat by the Management of M/S Salecha Cables, Pvt. Ltd., Mehatpur, district Una (H.P.) is justified and if not, to what relief and amount

## RELIEF :

6. In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the respondent management and against the petitioner. He is not entitled to any relief at this stage in the facts and circumstances of this case. Reference is answered accordingly in negative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i. e. Himachal Pradesh Rajpatra in accordance with law. A copy be also given to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 24th Day of December, 1992, at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,  
Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh,  
Shimla-2, 24-12-1992.

Before Shri R. K. Mahajan Presiding Officer  
Labour Court Himachal Pradesh, Shimla

Ref.-27/88

S/Shri Biri Singh and Murta Ram ..Petitioners.

Versus

Resident Engineer and Superintending Engineer,  
Shanan Power House, Jogindernagar, District Mandi,  
Himachal Pradesh. ..Respondents.

Shri S. S. Pathania, Authorised Representative of  
the petitioners.

Shri Chaturbhuj Garg, Authorised Representative  
of the respondents.

## AWARD

## 1. The petitioners have alleged as under:—

Shri Biri Singh claims that he worked in Shanan Power House, Jogindernagar under various divisions as daily wages worker from 1972 to 1982 and 1987 to 1988. His grievance is that he has been shunted out arbitrarily without chargesheet and enquiry. He further alleges that some juniors have been kept in the employment and he has been ignored. His grievance is also that the management has violated the policy of Electricity Board, Punjab dated 28-7-1986 regarding the conversion of daily rated workers who have put more than 1000 days into work-charged category. He has also alleged that the management has violated the settlement dated 30-1-1988 regarding re-employment. He wants re-instatement with back wages and continuity of service. Similarly, in case of Murta Ram, the workman states that he worked from 1972 to 1984 and his services were terminated without following procedure in 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 and policy decision of Electricity Board of Punjab regarding conversion of his service from daily rated worker to work-charged. He also alleges that the management has not implemented the conciliation agreement EX-PW-2/R for regularisation of service which was to be referred by S.E. Shanan Power House, Jogindernagar to General Manager, Shanan Power House, Jogindernagar. He also seeks re-instatement with back wages and continuity of service. Murta Ram was stated to have been shunted out first time in 1984 and Biri Singh on 10-6-1982. It is also stated that both were re-employed for two months in 1987-88.

2. The case of the respondent is that the management neither appointed nor terminated their services. Their simple plea is that the circle in which they were working ceased to function and as such their services were no more

equired. It is also disputed that Biri Singh has worked more than 240 days. It is denied by the management that the petitioner worked for more than 240 days. It is also pleaded that the workers left the job voluntarily.

3. From the pleadings of the parties, following issues were framed by my predecessor:—

1. Whether the petition is not maintainable as alleged ? (OPR).
2. Whether the Construction Project became *functus-officio* and the petitioners could not be re-employed by the respondents as alleged ?
3. Whether the retrenchment of the petitioners by the respondents is legally justified and in orders? If not to what effect ? (OPR).
4. Whether the petitioners are entitled to be reinstated as alleged ? If so, to what relief and amount of compensation, they are entitled ? (OPR).

## 5. Relief :

## 4. Issue No. 1:

1. This issue has not been pressed during the course of arguments by the respondents. Once a reference has been made by the Government after applying the mind this Court has to answer in one way or the other. I hold that the reference is maintainable.

## 5. Issues No. 2, 3 and 4:

Issues No. 2, 3 and 4 are inter-connected and they are disposed off not jointly, duplicity in discussion on facts and law is bound to arise. Mr. Pathania representative of the worker submitted that the procedure of retrenchment under section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 has not been followed. He further submitted that workcharge policy as discussed above has not been implemented *qua* the workers. He describes the termination is illegal on these grounds. He further submits that procedure of 25 H of the Industrial Disputes Act, 1947 has not been followed. The plea of the respondent is that offices in which they were working were abolished. The management has also submitted that the petitioners deserted the job and no question of compensation arises. In my view, the management has not honoured the conciliation agreement F.W.1/C dated 30-1-1988 by virtue of which the case was to be referred of both workers to the General Manager for regularising them on work-charge basis. The conciliation is binding on the management, once a competent authority as a party to it i. e. S. E. C. Mr. B. K. Bhatia Shanan Power House, Jogindernagar. The repeated reminders were sent to the management but of no use as appears from the letter dated 5-3-1988, addressed by the conciliation Officer to the Resident Engineer, Shanan Power House, Jogindernagar.

It is also on record that these workers have served for more than three years as per certificates issued by the department vide Ex-PW-2/N consisting of five pages. It is also an admitted fact that no compensation was given as required under section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947. It is also on record that so many persons were employed such as Jai Singh, Amar Singh, Puran Chand and Pyar Chand and no other opportunity was given to the petitioners under section 25H read with H. P. Rules framed under the I. D. Act, 1947. It is admitted by RW-1 Shri Kishori Lal from the list Ex-P-1 that eight workers have been made work charged who have completed more than 1000 days. He states that he does not know whether the petitioners completed 1000 days on 31-8-1988. It is also admitted by him that even workers who have completed 500 days, they have been made workcharged in different circles. List has been produced with respect to the working days of the petitioner Shri Biri Singh and it appears that he worked for 429 days from 1975 to 1980. The fact remains that the

workers have been retrenched without payment of compensation and no notice required under section 25F of the Act was issued. This provision is mandatory and has to be followed in letter spirit as it is meant for the protection of the workers. Even if the offices in which they were working, were abolished with the completion of the job, the management was bound to follow the provision of section 25H of the Act. The management has violated the spirit of 25F.H. of the Act and rule 82 and 83 of the H.P. Industrial Disputes Rules, 1974 (hereinafter shortly referred to as the rules).

I would like to quote the provision of the 25H and 25F of the Act.

**Section 25 H.**—It lays down where any workman retrenched or are retrenched and the employer proposes to take into his employment any reasons, he shall, in such manner as may be prescribed, give an opportunity to the retrenched workmen who are citizens of India to offer themselves for re-employment and such retrenched workmen who offer themselves for re-employment shall have preference over other persons.

**Rule 82 : Maintenance of Seniority list of workmen.**—The employer shall prepare a list of workmen in the particular category from which the retrenchment is contemplated arranged according to the seniority of their service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in a conspicuous place in the premises of industrial establishment at least seven days before the actual date of retrenchment.

**Rule 83 : Re-employment of retrenched workmen :** At least ten days before the date on which vacancies are to be filled, the employer shall arrange for the display on a notice board in a conspicuous place of the Industrial establishment details of those vacancies and shall also give intimation of those vacancies by registered post to everyone of all the retrenched workmen eligible to be considered therefore, to the address given by him at the time of retrenchment at any time thereafter.

The management has not produced the record to revert the statement of PW-1 and PW-2 i.e. the petitioners who are illiterate to show that no fresh workers junior to them, have been employed. The management has also not produced seniority list of the workers qua other workers. The spirit of the aforesaid rule is that no arbitrariness is shown in the matter of retrenched workers, if they are otherwise suitable for re-employment. The management is bound to offer opportunity of re-employment to the retrenched employees.

In my view, the management has not completed the legal formalities of 25F of the Act while retrenching the workers and also 25H of the I.D. Act, 1947. Their termination is void *ab initio*. The management has also not honoured the commitment arrived at the time of settlement and poor workers have not taken any action under section 29 of the I.D. Act, 1947. The Conciliation Officer also did not take any step. The settlement is binding under section 18 of the I.D. Act, 1947. I do not find any substance in the objections raised by the respondent.

In view of the reasons recorded above, the termination of the petitioners is unjustified and illegal and the same is quashed and set aside. I decide the issues in favour of the petitioners and against the respondent.

#### RELIEF :

In view of my finding on issues/reasons recorded I set aside the termination orders of the petitioners holding them illegal and unjustified and award the compensation in lieu of back wages of Rs. 6,000/- (Rupees Six Thousand) only to each worker in the facts and circumstances of the case. I further order that the workers are re-instated with all consequential benefits of continuity of service and seniority and the management

is ordered further to implement the settlement for the purpose of regularisation. The management is not to retrench them except in accordance with law. They would be considered to be in service as if no order of retrenchment has been issued as their termination is illegal. The award on such terms is passed in favour of the petitioners and against the respondent. Reference is answered accordingly in affirmative. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra in accordance with law. A copy be also supplied to the parties free of costs, if applied for by them. The parties, are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 29th day of December, 1992, at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,  
Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh,  
Shimla. 29-12-1992.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref. Case No. 93/91

Satanjeet.

.. Petitioner.

Versus

M/s J. K. Leatheries (P) Ltd., Mehatpur, Una,  
District Una (H.P.) .. Respondents.

Shri P. L. Bery, Authorized Representative of the  
petitioner.

Shri V. K. Gupta, Authorized Representative of the  
respondents.

#### AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla has referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties vide its notification, dated the 22nd August, 1991:—

“Whether the action of the management of M/s J. K. Leatheries (P) Ltd., Mehatpur, Una District, Himachal Pradesh in terminating the services of Shri Satanjeet, Helper on the charges of theft is legal and justified? If not, to what relief and amount of compensation, Shri Satanjeet is entitled?”

2. Shri Satanjeet, petitioner was employed by the respondent management as a packer of leather goods in the year October, 1990. Firstly he served the management as a helper and then as a packer. It is alleged by the petitioner that when he reported for duty on 6-12-1990 at 4 P.M., in second shift, he was told by the Supervisor that he should cut up the scraps near the factory. His grievance is that he had not committed any theft as alleged by the respondents of the Rexine Cloth and false charge has been concocted against him. No enquiry was held. No chargesheet was given for misconduct. No compensation was given. He describes his termination as arbitrary and unjustified. He has also described the letter of his resignation as fictitious alleging that the company obtained so many signatures of the petitioner on the blank papers and later on manufactured the record of its own choice. He was not allowed to join duty on 6-12-1990 which is reportedly date of his termination of the services. He prays that he may be reinstated with all the consequential benefits including the back wages.



3. The plea of the respondent management is that the petitioner resigned of his own on 6-12-1990, on 7-12-90 vide Ex. R.1 which is on record. The resignation was accepted by the respondent management on 8-12-1990 and all dues were cleared on 15-12-1990 as stated by the respondent management and which the petitioner has received. Respondent management has denied all the allegations levelled against them by the petitioner. Rather it has emphatically pleaded that the resignation was submitted to the plant Manager by the petitioner and there is no question of preparing the contested documents as alleged by the petitioner. From the pleadings of the parties, the following issues were framed by me on 16-5-1992:—

1. Whether termination of the petitioner by the respondent management is legal and justified on the grounds of allegations of theft ?  
(O.P. Parties).
2. Whether the reference is bad as it is not maintainable under section 12(5) of the Industrial Disputes Act, 1947 ?  
(OPR).
3. Whether the reference is without any basis in the form in which it has been made ?  
(OPR).
4. Whether no dispute has been raised by the petitioner himself ?  
(OPR).
5. Relief.

#### FINDINGS ON ISSUES

##### Issue No. 1

4. Mr. Dogra and Mr. Bery have been representing the petitioner at different intervals. Sometime they appeared and sometime they did not appear before this Court. I have heard the petitioner. The petitioner has told the court that he did not commit any theft as alleged at all. He further submitted that he has signed on the original resignation, the photostat copy of which is Ex. R.1 placed on record. His explanation is that the respondent management got signatures on so many blank papers at the time of his initial recruitment. They used these papers according to their convenience. He has admitted that he signed only the bio-data which was given to the respondent management by him at the time of his recruitment. He also admits that he has received the payment of all his dues on 15-12-1990. There is a gap of one week in acceptance of the resignation and payment of dues to the petitioner. The respondent has led evidence regarding the theft allegedly committed by the petitioner of R.W. 1 and R.W. 2. According to Jai Dev, R. W. 1, the respondent management has placed a roll of 90 meters of rexin cloth near the wall and out of which the petitioner cut 5 meters of cloth without permission of the competent authority. He further states that it was a part of duty to cut the roll. He reported the matter to the Supervisor. R.W. 2 states that when the petitioner was asked for cutting the roll and for what purpose he needed the rexin cloth, the petitioner was that he needed it but did not specify the purpose. The matter was reported to the Director who made a verbal enquiry. Thereafter, the petitioner was sent to jail. The petitioner came the next day and submitted his resignation. In my view if the petitioner has committed the theft, the best course to the management was to hold an enquiry in consonance with the principles of natural justice. There is an evidence on theft but there is no specific mentioning in the resignation as to what were the circumstances of the resignation by the petitioner. Theft was committed on 6-12-1990. Resignation was submitted on 7-12-1990 and it was accepted on 8-12-1990 and the dues were cleared by 15-12-1990. Later on the petitioner persuaded the union to lodge a complaint on 23-1-1991 regarding practice of obtaining the signatures on the blank papers by the respondent management which is not substantiated. From the circumstances, it is revealed that if a veil is lifted, then the purpose of resigning was commission of theft

by the petitioner but no enquiry has not been conducted by the respondent management. Question not leading evidence under section 11(A) of the Act does not arise as there was no enquiry at all. Resignation does not appear to have been made after taking into consideration the consequences. In view of this technical defect, set-aside the order of termination of the petitioner but do not consider it appropriate to re-instate him as there is a loss of confidence and the respondent management and the petitioner are not in a position to maintain the harmonious industrial relations. However, the petitioner is ordered to be paid a sum of Rs. 7,000 (Seven thousand) only as compensation by the respondent management taking into consideration the facts and peculiar circumstances of this case. I, therefore, for the reasons recorded decide this issue accordingly.

##### Issues No. 2, 3, and 4

5. These issues have not been pressed during the course of either evidence or the arguments not are the subject matters of the reference. No findings are, therefore, required to be made in respect of these issues. These issues are, therefore, decided accordingly.

##### RELIEF :

In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly setting aside the termination orders of the petitioners without re-instatement but allowing him a compensation of Rs. 7000/- (Seven thousand) only to him payable by the respondent management. Reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazette i.e. H.P. Rajpatra in accordance with the law and a copy be given to the parties free of costs, if applied for by them. No orders as to the costs of these proceedings. The file be consigned to the record room after its due completion.

Announced on this 1st day of January, 1992 at Shimla

Seal.

R. K. MAHAJAN,  
Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh,  
Shimla.  
1-1-1993.

Before Shri R. K. Mahajan, Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla

Ref.-Case-16/90

Dalel Singh

..Petitioner

Versus

M/s Chanana Steel Tubes, (P) Ltd., Parwanoo, Distric  
Solon (H.P.) ..Respondent.

Shri Dalel Singh, Petitioner in person.  
Shri Daljeet Singh, Clerk, for the respondents.

##### AWARD

1. The Government of Himachal Pradesh, Shimla vide its notification, dated the 26th February, 1990 has referred the following dispute to this court for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter shortly referred to as the 'Act') on failure of the conciliation proceedings between the parties:—

1. Whether the termination of services of Shri Dalel Singh by the Management of M/s Chanana Steel Tubes (P) Ltd., Parwanoo is legal and maintainable? If illegal, to what relief and service benefits, Shri Dalel Singh is entitled ?
2. Whether the action of the management not to implement the settlement, dated 3-10-198



constitutes unfair labour practice under schedule 5th, item No. 13 of the Industrial Disputes Act, 1947 or not? If yes, what penalty is to be imposed on the employer?

3. Whether the management has made unfair labour practice under 5th schedule, item No. 5(6) of the Industrial Disputes Act, 1947, terminating the services of Sri Daler Singh in utter disregard to the principles of natural justice? If unfair on this account, what penalty is to be imposed on the employer?

2. The petitioner, Sri Daler Singh joined with the respondent management as Turner on 7-12-1983 @ of Rs. 900/- per month. He worked with the respondent management for six years. His grievance is that he was inducted by the respondent management from service on 15-9-1989 and was not allowed to join duty. No chargesheet was given, No. compensation was given. No enquiry was held against him in consonance with the principles of natural justice. He further alleges that the respondent management did not want to regularise him as the management feared that the petitioner would form a union and would also claim the terminal benefits. The petitioner approached the Labour Inspector, Parwanoo where he was not allowed to join duty by the respondent management and during conciliation proceedings, it was agreed by the respondent management vide Ex. P.W. 1/A dated 3-10-1989 that the petitioner would be taken on duty on 4-10-1989 and his seniority will be kept in tact and further agreed to pay him the half wages for the period of his absence. The settlement was not implemented as alleged by the petitioner and he again approached the Labour Inspector, Parwanoo for redressal of his grievances by way of a demand notice. Ultimately the conciliation proceedings failed and this matter was referred to this court by the Government of Himachal Pradesh, Shimla for adjudication. The petitioner says that he may be re-instated with all the consequential benefits including the back wages. The case was heard in this court in pursuance of the directions issued by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, Shimla but the management has been playing hide and seek policy sometimes by attending the court and remaining absent for most of the dates. Today, the respondent management has deputed a clerk requesting for an adjournment on account of illness of senior authorised representative of the respondents. It may be mentioned that Company appointed representative, who cross examined the witnesses, of the petitioner, has never produced the evidence of his own. The delaying tactics on the part of the respondent management is not conducive to the norms of justice and the management wants to exhaust the petitioner by not co-operating with this court for expediting the quick disposal of this case. The respondent management has been proceeded *ex parte* on 23-9-1992 as the representative of the company was present on 27-8-1992, i.e. the earlier date. I would proceed to decide this case on the basis of the material and evidence brought on record by the parties.

3. The respondent management has put in a written statement and denied all the allegations against them by the petitioner. It was averred that the respondent management never resiled from implementing the settlement, dated 3-10-1989. In fact, the petitioner himself absented from duties and has made out his case of voluntary abandonment. From the pleadings of the parties, the following issues were framed by my learned predecessor on 28-5-1990:—

1. Whether the termination of services of the petitioner by the respondent management is illegal and invalid? If so, to what effect? (OPP).
2. Whether there is any settlement, dated 3-10-89 arrived at in between the parties, as alleged? (OPP).

3. If issue No. 2 is held in the affirmative, whether non-implementation thereof amounts to unfair labour practice, as alleged? (OPP).

4. In case, issue No. 1 is decided in the affirmative, whether the petitioner is entitled to be re-instated in service with full benefit of back wages etc., as alleged? (OPP).

5. Relief.

#### FINDINGS ON ISSUES

##### Issues No. 1 and 2 :

4. Both the above issues are inter-connected and would be disposed off together in order to avoid the duplicity in discussion.

5. The petitioner adduced evidence of Sri Daler Singh, who appeared as his own witness as P.W. 1 and placed reliance on the settlement, dated 3-10-1989, Ex. P.W. 1/A. The respondent has produced R.W. 1, Sri Daljit Singh, Office Clerk. He states that he was telephonically informed by Sri Bipul Cuanana, Manager to take the petitioner on duty, if he happened to come but the petitioner did not turn up. Sri Daljit Singh is referring this sequence of events after the settlement placed on record. Daljit Singh, R.W. 1, Office Accounts Clerk states that he has no knowledge whether the petitioner submitted application on 4-10-1989 to the Labour Inspector, Parwanoo informing him of the violation of the settlement by the respondent management. The petitioner submitted that had the management *bonafide* intentions to implement the settlement, dated 3-10-1989, then he would not have filed application before the Labour Inspector, Parwanoo for further conciliation proceedings on which the matter was later on referred to the Labour Court for adjudication. The respondent management also did not show sincere efforts to implement the settlement, dated 3-10-1989 even later on or at the time of the conciliation proceedings. There is nothing on record to show that any registered letter was sent to the petitioner, asking him to join duty by the respondent management, in case he was showing reluctance to do so. The conduct of the petitioner shows that he was willing to join duty with the respondent management but it was the respondent management which did not accept him on duty.

6. The respondent management has violated the settlement, dated 3-10-1989 arrived at between the parties in his presence i.e. the Labour Inspector. It means that the settlement was arrived at during the conciliation proceedings and falls within the 5th Schedule item No. 13 of the Act. The Court cannot take any action but action can be initiated by the Labour Commissioner, Himachal Pradesh under section 29 read with section 34 of the Act for breach of settlement and this complaint can be filed before the competent authority. As regards the termination of the petitioner by the respondent management, I find from the record that no enquiry has been conducted against the petitioner in consonance with the principles of natural justice. No chargesheet was served on him. No retrenchment compensation has been given to him as required under section 25(F) of the Act. In view of this, the termination of the petitioner by the respondent management is void *ab initio*. I, therefore, for the reasons recorded decide both the above issues accordingly in favour of the petitioner and against the respondent management by setting aside his termination order by the respondent management as if no such order was ever passed.

##### Issue No. 3 and 4

7. The action of the respondent management amounts to unfair labour practice as discussed above against issues No. 1 and 2. As regards issue No. 4, this issue requires no separate findings.

## Relief :

8. In view of my findings on issues and the reasons recorded, I pass an award accordingly in favour of the petitioner and against the respondent management. The petitioner is ordered to be re-instated in the service of the respondent management in such a manner as if no termination order was ever passed by the respondent management against the petitioner. I award to the petitioner a sum of Rs. 20,000 (Twenty thousand) only as the compensation in lieu of back wages with the continuity of service rendered by him with the respondent management. The amount of compensation would be payable by the respondent management to the petitioner within a period of two months from the date of publication of this award in the official gazettee i.e. H.P. Rajpatra failing which an interest of 18% would be payable by the respondent management on this amount to the petitioner. Reference is answered accordingly in affirmative. Award is passed in terms of the above. Let a copy of this award be sent to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, for its due publication in the official gazettee i.e. H.P. Rajpatra in accordance with the law. A copy be given to the parties free of costs, if applied for by them. The parties are, however, left to bear their own costs of these proceedings. The file after its due completion, be consigned to the record room.

Announced on this 22nd day of January, 1993, in open court at Shimla.

Seal.

R. K. MAHAJAN,  
Presiding Officer,  
Labour Court, Himachal Pradesh,  
Shimla-22-1-1993.

बहुदेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 7 दिसम्बर, 1991

संख्या एम० पी० पी० ए० (3) 11/76-पार्ट.—हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (अध्यक्ष की शक्ति और अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवाओं के निबन्धन और शर्तें) नियम, 1991 के नियम 19 के उपबन्धों के अनुसरण में, राज्य सरकार यह आदेश करती है कि सचिव (बहुदेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत), हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए यात्रा करना/करने की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यात्रा करने की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

2. यह भी आदेश किया जाता है कि मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, अध्यक्ष और/या बोर्ड के सदस्यों को राज्य से बाहर दौरे पर जाना अनुज्ञात करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा यदि ऐसे दौरे बोर्ड के बाह्य में किए जाना प्रस्तावित हों।

3. आगे यह भी आदेश किया जाता है कि अध्यक्ष और/या बोर्ड के सदस्यों द्वारा किसी विदेश दौरे के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
मुख्य सचिव।

[Authoritative english text of the Government Notification No. M. P. P.-A (3) 11/76-Part, dated 7-12-1991 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution].

Shimla-2, the 7th December, 1991

No. MPP-A (3) 11/76-Part.—In pursuance of the provisions of Rule 19 of the Himachal Pradesh State

Electricity Board (Power of the Chairman and terms & conditions of services of the Chairman & Members) Rules, 1991 the State Government is pleased to order that the Secretary (MPP & Power) will be the competent authority to allow the Chairman, H. P. S. E. B. to undertake journey for the discharge of duties of the Board and the Chairman, H. P. S. E. B. shall be the competent authority to allow the members of the Board to undertake journey for the discharge of duties of the Board.

2. It is also ordered that Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh shall be the competent authority to allow the Chairman and/or the members of the Board to undertake tours outside the State in case such tours are proposed to be undertaken in the vehicle of the Board.

3. It is further ordered that any tours abroad by the Chairman and/or members of the Board will need prior approval of the Government.

By order,  
Sd/-  
Chief Secretary.

शिमला-171002, 30 मार्च, 1993

संख्या विद्युत-छ (5)-24/92.—यतः भारत के राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निबन्धन संहिता (एन० एच० पी० सी०) जो कि भूमि अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी० सी०) के अर्थात्सर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु चमेरा जल विद्युत परियोजना प्रथम के जलाशय क्षेत्र के लिए भूमि अर्जित अपेक्षित करनी है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और अधिकारियों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए भारत के राष्ट्रपति उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विवरणी

जिला : चम्बा

तहसील : चम्बा

मुहाल	खसरा नं०	क्षेत्र		
		बी० बि०	वि०	विस्ती०
1		3	4	5
प्राहनुई	712	0	3	0
	714	0	7	0
	715	1	19	0
	716	0	7	0
	717	3	6	0
	718	0	4	0
	719	0	1	0
	720	0	3	0
	721	0	2	0
	722	0	2	0

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT

## NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 4th February, 1988

No. PBW-2-B (4) 14/17.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to place the services of Shri Raj Kumar, Assistant Engineer presently posted as Assistant Engineer (Design), 9th Circle, Nurpur with the Himachal Pradesh Forest Corporation Limited, Shimla on deputation with immediate effect, for one year in the first instance.

The terms and conditions of deputation will be issued separately.

By order,  
Sd/-

Commissioner-cum-Secretary.

## "Special Cell"

Shimla-2, the 6th February, 1988

No. 1-98/72-PWD-Vol-V.—Whereas the Joint Integrated Seniority list of Assistant Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department as on 1-11-1966 was declared final and issued vide letter No. 1-241/69-P.W.D., dated 6-1-1973;

2. Whereas on the basis of above seniority list of Assistant Engineers (C) the Departmental Promotion Committee for promotion to the posts of Executive Engineers (Civil) Himachal Pradesh Public Works Department was held in Himachal Pradesh Public Service Commission on 27th, 28th and 29th December, 1973 and 11th January, 1974;

3. Whereas on the recommendations of the said Departmental Promotion Committee, 48 Assistant Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department were promoted to the posts of Executive Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department on officiating basis vide notification No. 1-98/70-PWD-Vol-II, dated 22-3-1974;

4. Whereas, the Himachal Pradesh Government in the department of Personnel vide their O. M. No. 1-19/73-DP(Appt-II), dated 28-9-1973 circulated a judgement of the Supreme Court of India laying down certain principles for refixing the seniority of Government servants;

5. Whereas in accordance with the above judgement of the Supreme Court of India, the integrated seniority of Assistant Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department as on 1-11-1966 was refixed and with the prior approval of Government of India made final and accordingly circulated amongst all concerned vide letter No. 1-241/69-PWD-Vol-II, dated 1-7-1987;

6. Whereas as a result of revision of the final joint integrated seniority list of Assistant Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department as on 1-11-1966, it became imperative to review the proceedings of the earlier Departmental Promotion Committees, held on 27th, 28th 29th December, 1973 and 11th January, 1974;

7. Whereas the review Departmental Promotion Committee was held in the Himachal Pradesh Public Service Commission on 18th to 21st January, 1988 and 29th January, 1988 to review the earlier proceedings of the departmental Promotion Committee for promotion to the post of Executive Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department;

8. Now, therefore, on the recommendations of the review Departmental Promotion Committee and in

2	3	4	5
723	0	3	0
724	0	3	0
725	0	2	0
726	0	2	0
727	0	12	0
728	0	7	0
729	0	11	0
730	0	7	0
731	0	4	0
733	0	0	8
734	0	0	18
736	0	1	0
737	0	0	13
738	0	1	0
739	0	2	0
740	0	4	0
741	0	2	0
742	0	2	0
743	0	3	0
744	0	1	0
745	0	2	0
746	0	2	0
748	0	6	0
751	2	17	0
752	1	0	0
753	1	9	0
754	4	11	0
755	0	7	0
756	0	4	0
758	0	0	14
759	0	1	0
697/1	3	14	0
704/1	0	6	0
705/1	0	9	0
कुल .. 45	25	13	13

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
वित्तियुक्त एवं सचिव।

लोक सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 फरवरी, 1993

सं० पब-बी (2)-1/86-III.—इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31-7-1992 के क्रम को जारी रखते हुये, राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से निम्नलिखित स्थाई सहायक लोक सम्पर्क अधिकारियों को जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों/सूचना अधिकारियों वेतनमान रुपये 2200—4000 (श्रेणी-II) के पद पर तदर्थ सेवाएं दिनांक 1-1-1993 से 30-6-1993 तक बढ़ाने को या जब तक ये पद नियमित रूप में न भरे जायें, जो भी पहले हो, को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. श्री सी० एम० कपूर
2. श्री आर० एस० नेगी
3. श्री के० एल० रैणा
4. श्री रोशन लाल
5. श्री आर० सी० शर्मा

आदेश द्वारा,  
पी० एस० नेगी,  
आयुक्त एवं सचिव।

consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote the following Assistant Engineers (Civil), Himachal Pradesh Public Works Department to the post of Executive Engineer (Civil), H.P.P.W.D. on regular basis from the dates mentioned against each:—

S/Shri:	
1. T. L. Sharma	22-3-1974
2. J. R. Kainth	-do-
3. Amar Nath	-do-
4. A. K. Bhatia	-do-
5. Y. R. Kashyap	-do-
6. Dewan Chand	-do-
7. D. S. Parmar	-do-
8. S. K. Aggarwal	-do-
9. N. P. Vakil	-do-
10. S. D. Kathuria	-do-
11. Dilbag Singh	-do-
12. H. N. Gandhi	-do-
13. Krishan Lal	-do-
14. N. C. Trehan	-do-
15. M. P. Sachdeva	-do-
16. Thakur Singh	-do-
17. K. K. Mahajan	-do-
18. S. P. Sharma	-do-
19. Mehnga Singh	-do-
20. D. N. Handa	-do-
21. Raj Kumar Sharma	-do-
22. P. C. Bisht	-do-
23. S. N. Bhatia	-do-
24. Varinder Kapoor	-do-
25. V. P. Mongra	-do-
26. B. P. Singh	-do-
27. Ram Asra	-do-
28. I. C. Goel	-do-
29. R. D. Jain	-do-
30. G. C. Gupta	-do-
31. I. C. Kapoor	-do-
32. S. K. Vaidya	-do-
33. D. V. Handa	-do-
34. J. S. Roorkee	-do-
35. Behari Lal	-do-
36. R. L. Vaidya	-do-
37. Mohinder Partap	-do-
38. B. P. Handa	-do-
39. Sadhu Singh	-do-
40. R. K. Kaur	-do-
41. T. C. Bhagoria	8-10-1974
42. S. S. Juneja	22-3-1974
43. R. B. Singh	-do-
44. Yashpal Sharma	-do-
45. Balwant Rai	-do-

9. This supersedes all the notifications in this behalf issued previously from time to time.

ATTAR SINGH,  
Financial Commissioner-cum-Secretary.

Shimla-2, the 8th February, 1988

No. PBW-I-B (3) 48/77.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer and posting of Shri Lavanya Malhotra, A. E., Shimla Development Authority, Shimla to 5th Circle, Palampur as Assistant Engineer (D) on repatriation with immediate effect in public interest.

2. He is entitled to T. T. A. and joining time as admissible under the rules.

Shimla-2, the 10th February, 1988

No. PBW-2-B-12/79.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the posting of Shri K. K. Sen, Assistant Engineer (Civil) on repatriation from H. P. State Co-operative Bank Ltd., Shimla in Sub-Division, Jassoor against the vacant post with immediate effect in the public interest.

2. He is entitled to T. T. A. and joining time as admissible under the rule,

By order,  
A. K. MAHOPATRA,  
Commissioner-cum-Secretary.

Shimla-2, the 10th February, 1988

No. PBW (B&R) 26(B) (95)/86.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute Shimla Art and Heritage Committee with immediate effect. The Constitution of the Committee will be as under:—

1. Chief Minister	Chairman
2. Minister of State (B&R)	Vice-Chairman
3. Chief Secretary	Member
4. F. C.-cum-Secretary (Art, Language and Culture)	-do-
5. Secretary (Urban Development and LSG)	-do-
6. Director (Art, Language and Culture)	-do-
7. Mayor, M. C., Shimla	Non-Official Member
8. Shri Harbhajan Singh, M.L.A., Shimla	-do-
9. Mr. Bani Prasanno (Artist)	-do-
10. President, Himalayan Environment Group	-do-
11. President and Secretary, INTACH, Shimla	-do-
12. Senior Architect	-do-
13. Prof. Moitra, Town Planner, Delhi	Outside expert
14. Prof. B. N. Goswami, Head of Department of Fine Arts, Panjab University, Chandigarh	-do-
15. Director, TCPO	Member-Secretary.

2. The Function of the Committee will be as under:—

- To identify the distinct characteristics of Shimla's architecture in the context of her history and built heritage.
- To suggest a range of architectural styles consistent with Shimla's distinct architectural character and heritage so that new construction can be regulated to be in harmony with her distinct character.
- To suggest guide lines in specific terms on the basis of which facades, roof paints, colour-schemes of the buildings, designs of hoarding etc. can be regulated.
- To examine all other matters relating to the preservation, enhancement and modifications of Shimla's cultural and built heritage in harmony with her past and further beautification of Shimla and suggest appropriate measures.
- To formulate appropriate regulatory measures to ensure preservation of Shimla's heritage and harmonisation of new construction activities repairs, renovations and all other activities connected with exterior-design of the buildings of Shimla with her heritage.

A. K. MAHOPATRA,  
Commissioner-cum-Secretary.

Shimla-2, the 24th February, 1988

No. PBW-2 (B) 6/87.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Ram Lal Sharma, Junior Engineer (Horticulture), H. P. P. W. D. to the post of Assistant Engineer (Hort.) in the pay scale of Rs. 940-30-1000/40-1200/50-1400/60-1700-75-1850 purely on *ad hoc* basis from the date of his taking over the charge of the post.

2. The *ad hoc* appointment will not confer on him any right of seniority/continuity as Assistant Engineer (Hort.).

3. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Shri Ram Lal Sharma,

as Assistant Engineer (Horticulture) in the newly created H. P. P. W. D. Horticulture Sub-Division, Bilaspur against the vacant post.

शिमला-2, 28 नवम्बर, 1991

संख्या पी० बी० डब्ल्यू०-1 बी० (2)-1/77-राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 29-10-1991 का आशिक संशोधन करते हुए, श्री आर० डी० कौडल, अधीक्षक अर्द्ध-1 जिन्हें सतर्कता अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए जाने पर मुख्य अभियन्ता (उत्तर), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, धर्मशाला के कार्यालय में तैनात किया गया था, को मुख्य अभियन्ता (दक्षिण), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला के कार्यालय में सतर्कता अधिकारी के रिक्त पद पर तत्काल जनहित में समायोजित करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-2, 10 दिसम्बर, 1991

स० लो० नि० वि० (क) 2 (बी०) 6-1/91-राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री आर० पी० आचार्य, सहायक अभियन्ता (सिविल) को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में आवंटित करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

2. राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-8-91 की आशिक का से संशोधित करते हुए श्री आर० पी० आचार्य, सहायक अभियन्ता (सिविल) जोकि विकास विभाग, धर्मशाला से लोक निर्माण उप-मण्डल, बानेधार के लिए स्थानान्तरणा-धीन थे को सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में बतौर सहायक अभियन्ता के रिक्त पद के तहत सिचाई एवं जन स्वास्थ्य उप-मण्डल, चडियार में तत्काल जनहित में समायोजित करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
विस्तारुक्त एवं सचिव।

शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या 1-7/73-पी० डब्ल्यू० ए० भाग-II-भारत के राष्ट्रपति महोदय, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (विद्युत) को तदर्थ आधार पर अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) के पद पर वेतनमान रु० 3000-4500 में पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश देते हैं:-

1. श्री जे० के० खन्ना, डिप्लोमा होल्डर
2. श्री भारतेन्दु कपूर, स्नातक

2. यह आदेश उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से उक्त अधिकारी अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर की जा रही है और इस तदर्थ पदोन्नति से अधिकारी की वरिष्ठता तथा नियमित पदोन्नति का कोई हक हासिल नहीं होगा।

4. सरकार उक्त तदर्थ पदोन्नति को रद्द करने तथा उसे वापिस उसी पद पर भेजने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस पद पर से उसे पदोन्नत किया जा रहा है।

भारत के राष्ट्रपति महोदय, उपरोक्त अधिशासी अभियन्ताओं (विद्युत) को पदोन्नति के उपरान्त हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित विद्युत मण्डलों में तैनाती के जनहित में सहर्ष आदेश देते हैं:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	तैनाती स्थान
1	2	3
1.	श्री जे० के० खन्ना	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, विद्युत मण्डल नं०-II, शिमला रिक्त स्थान पर।

1 2 3

2. श्री भारतेन्दु कपूर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, विद्युत मण्डल, मण्डो रिक्त स्थान पर।

उक्त अधिकारी अपने-अपने तैनाती स्थान पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण करेंगे और कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस विभाग को भेजेंगे।

शिमला-2, 15 जनवरी, 1993

संख्या 1-43/75-पी० डब्ल्यू० ए० बोल-II-भारत के राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को तदर्थ आधार पर अधिशासी अभियन्ता (सिविल) वेतनमान रुपये 3000-4500 में पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश देने हैं। यह आदेश उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से यह अधिकारी पदोन्नत पद पर कार्यभार सम्भालेंगे:-

1. श्री ललित कुमार वैद्य, स्नातक
2. श्री माधो प्रसाद लोहिया, डिप्लोमा प्राप्त
3. श्री कमलेश कुमार गुप्ता, स्नातक
4. श्री प्रकाश चन्द, स्नातक

2. उपरोक्त पदोन्नतियों, जो श्री पी० सी० गौतम, सहायक अभियन्ता (सिविल) ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सिविल रिट पैटिशन संख्या 224/1984 दायर की थी और जो बाद में माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में बतौर टी० ए० 240/1986 स्थानान्तरित हुई थी, के अन्तिम निर्णय पर मान्य समझी जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों का उनकी वरिष्ठता एवं नियमितता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और जब अधिशासी अभियन्ताओं (सिविल) की नियमित पदोन्नतियां होंगी तब उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। सभी पदोन्नत अधिकारी इस बारे अपना कार्यभार सम्भालने से पूर्व एक शपथ-पत्र भी कार्यग्रहण सूचना के साथ भेजेंगे।

3. भारत के राष्ट्रपति महोदय, उपरोक्त अधिशासी अभियन्ताओं को पदोन्नति के उपरान्त हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में तैनाती के निम्नलिखित रूप से जनहित में सहर्ष आदेश देते हैं:-

क्रमांक अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान
1. श्री ललित कुमार वैद्य	लोक निर्माण मण्डल, कुमारसैन में रिक्त स्थान पर।
2. श्री माधो प्रसाद लोहिया	नगर एवं ग्रामीण योजना में प्रतिनियुक्ति पर।
3. श्री कमलेश कुमार गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता (रूपांकन), लोक निर्माण मण्डल, शिमला, रिक्त स्थान पर।
4. श्री प्रकाश चन्द	लोक निर्माण मण्डल, शिलाई (कफोटा), रिक्त स्थान पर।

4. श्री माधो प्रसाद लोहिया, अधिशासी अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति की निबन्धन और शर्तें बतौर अधिशासी अभियन्ता अलग से जारी की जाएंगी।

5. सभी अधिकारी अपने-अपने तैनाती के स्थान पर तुरन्त कार्यग्रहण करेंगे और कार्यग्रहण सूचना इस विभाग को तुरन्त भेजेंगे।

शिमला-2, 23 जनवरी, 1993

संख्या 1-92/72-पी० बी० डब्ल्यू०-भारत के राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति की सिफारिशों पर श्री वेद भूषण, अनुसंधान अधिकारी (सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला) (राजपति वर्ग-II) को वेतनमान रुपये 2000-3500 में तत्काल नियमित करने के बारे में सहर्ष आदेश देते हैं। नियमित पदोन्नति पर अधिकारी कार्यालय मुख्य

अभियन्ता (दक्षिण), हि० प्र० लो० नि० वि०, शिमला-171001, में ही तैनात रहेंगे।

2. अधिकारी पदोन्नति के प्रथम दो वर्षों में परिवीक्षा पर रहेंगे।

शिमला-2, 2 फरवरी, 1993

संख्या पी०बी० डब्ल्यू०-2बी० (6) 8/91.—भारत के राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधीक्षण अभियन्ताओं, लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश को जनहित में तत्काल स्थानान्तरित करने के सहर्ष आदेश देते हैं :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम व तैनाती स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1.	श्री आर सी० गोयल, अधीक्षण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालनपुर से प्रत्यावर्तन पर।	अधीक्षण अभियन्ता, क्षेत्रीय अभियान्तिक महाविद्यालय हमीरपुर में प्रतिनियुक्ति पर श्री एस० डी० कोण्डल के स्थान पर।
2.	श्री आई० सी० गोयल, अधीक्षण अभियन्ता (रूपांकन-II), लोक निर्माण मुख्यालय, शिमला-1.	अधीक्षण अभियन्ता, आरबी-टेशन, सोलन, रिक्त स्थान पर।
3.	श्री एस० डी० कोण्डल, अधीक्षण अभियन्ता, क्षेत्रीय अभियान्तिक महाविद्यालय, हमीरपुर।	अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम वृत्त लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर, रिक्त स्थान पर।
4.	श्री एस० एस० जुनेजा, अधीक्षण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से प्रत्यावर्तन पर।	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में श्री आर० ए० चौधरी के स्थान पर।
5.	श्री आर० ए० चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी।	अधीक्षण अभियन्ता (रूपांकन-II), लोक निर्माण मुख्यालय, शिमला में श्री आई० सी० गोयल के स्थान पर।

उक्त अधिकारी अपने-अपने स्थानान्तरित स्थान पर तुरन्त प्रस्थान करेंगे तथा कार्यग्रहण सूचना इस विभाग को भेजेंगे।

शिमला-2, 10 फरवरी, 1993

संख्या पी० बी० डब्ल्यू०-2बी० (6) 1/91.—भारत के राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधीक्षणी अभियन्ताओं, लोक निर्माण विभाग को जनहित में तत्काल स्थानान्तरित करने के सहर्ष आदेश देते हैं :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम व तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1.	श्री एम० एम० कानरा, अधीक्षणी अभियन्ता, शिमला विकास प्राधिकरण।	अधीक्षणी अभियन्ता (रूपांकन), द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, शिमला में श्री आर० सी० गुप्ता के स्थान पर।
2.	श्री आर० सी० गुप्ता, अधीक्षणी अभियन्ता (रूपांकन), द्वितीय वृत्त, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला।	अधीक्षणी अभियन्ता, शिमला विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर।

2. उक्त अधिकारी अपने-अपने स्थानान्तरित स्थान पर तुरन्त प्रस्थान करेंगे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भेजेंगे। या मृत्ता की प्रार्थनापूर्वक सेवा अर्पण अलग से जारी की जाएगी।

3. उक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

शिमला-2, 15 फरवरी, 1993

संख्या पी०बी० डब्ल्यू०-2बी० (6) 9/90.—भारत के राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधीक्षणी अभियन्ताओं, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश को जनहित में तत्काल स्थानान्तरित करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम व तैनाती स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1.	श्री अरुण महाजन, अधीक्षणी अभियन्ता (रूपांकन), लोक निर्माण, मुख्यालय, शिमला-1.	अधीक्षणी अभियन्ता, लोक निर्माण मण्डल-II, शिमला श्री अमर सिंह चौहान के स्थान पर।
2.	श्री अमर सिंह चौहान, अधीक्षणी अभियन्ता, लोक निर्माण मण्डल-II, शिमला.	अधीक्षणी अभियन्ता (रूपांकन), लोक निर्माण मुख्यालय, शिमला श्री अरुण महाजन के स्थान पर तथा आपस में।

2. उपरोक्त अधिकारी तुरन्त अपने-अपने स्थानान्तरित स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे तथा कार्यग्रहण सूचना इस विभाग को अविलम्ब भेजेंगे।

शिमला-171002, 17 मार्च, 1993

संख्या पी० बी० डब्ल्यू०-2बी० (3)-38/91.—भारत के राष्ट्रपति, श्री जसवंत लाल छावड़ा, अधीक्षक ग्रेड-I, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, शिमला को उनकी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से दिनांक 30-4-1993 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

यतः भारत के राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः\* भूमि अर्जन करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणों में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त\* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और अधिकारियों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाह्वी, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

\*गांव लोल, तहसील करसोग, जिला मण्डी में करसोग, परलोग मण्डक के निर्माण हेतु।

संख्या लो० नि० (ख) 7(1) 63/92.

शिमला, 27 मार्च, 1993.

विवरण

जिला : मण्डी

तहसील : करसोग

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बो० वि० कि०
सोल	34/1	0 08 08
422	92/1	0 02 02
	101/1	0 00 09
	103/1	1 15 06
	105/1	0 04 11
	107/1	0 02 13
	107/2	0 01 10
	108/1	0 06 18
	291/110/1	0 13 05
	159/1	0 01 16
	172/1	0 00 09
	183/1	0 09 14
	184/1	0 14 08
	205/1	0 12 07
कित्ता ..	14	5 13 16

\*गांव करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी में करसोग-परलोग सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या लो० नि० (ख) 7(1) 41/92.

शिमला-2, 27 मार्च, 1993.

करसोग/416	397/1	0 00 08
	407/1	0 00 02
	409/1	0 00 15
	410/1	0 00 02
	413/1	0 00 13
कित्ता ..	5	0 02 00

आदेश द्वारा,

एन० एस० सिद्ध,  
वित्तियुक्त एवं सचिव।

## REVENUE DEPARTMENT

### NOTIFICATIONS

Shimla-2, 1st February, 1988

No. Rev. D(A)2-2/82.—In exercise of the powers vested in him under clause (a) of Sub-Section (1) of Section 28 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (Act No. 6 of 1954) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to confer upon the following Sub-Divisional Officers, the powers of Collector under the said Act to be exercised by them within the local limits of their jurisdiction as specified against each name below from the date the officers concerned have assumed the charge as such:—

1. Shri Dharuv Vashist, Sub-Divisional Officer (C), Chopal. Chopal Sub-Division.
2. Smt. Upma Chaudhary, Sub-Divisional Officer (C), Shimla. Shimla (Urban) Sub-Division.

By order,  
ATTAR SINGH,  
Secretary.

## PONG DAM CELL

Shimla-2, the 5th February, 1988

No. 5-1/85-Pong Cell.—In partial modification of this Department notification of even number, dated the 24th June, 1985, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate Shri Nand Kumar Chauhan, M. L. A. as a member of the State Level Chamara Project Oustees Rehabilitation Advisory Committee with immediate effect.

2. Other terms and conditions as contained in paras 2-5 of the notification referred to above shall remain unchanged.

By order,

ATTAR SINGH,  
Financial Commr-cum-Secretary (Rev.).

Shimla-2, the 19th February, 1988

No. Rev. D (A)2-10/82.—In exercise of the powers vested in him under clause (a) of Sub-Section (1) of Section 28 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (Act No. 6 of 1954) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to confer upon the following Assistant Settlement Officers, the powers of Collector under the said Act to be exercised by them within the local limits of their jurisdiction as specified against each name below from the date the officers concerned have assumed the charge as such:—

1. Shri Raj Gopal Sharma (Vashist), Kangra and Una Assistant Settlement Officer. districts.
2. Shri Manbeer Chand Rana, Una District. Assistant Settlement Officer.

Shimla-2, the 20th February, 1988

No. Rev. D(D) 1-18/85-I.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to hold in abeyance this department Notification No. 12-14/67-Rev. I (II), dated the 21st July, 1980, pending the recommendations of the committee to go into the whole question of the entry in revenue records namely 'Khudro Drakhtan Malkiet Sarkar' constituted vide Notification No. Rev. D (D) 1-18/85, dated 22-1-1986.

By order.

ATTAR SINGH,  
Secretary.

Shimla-2, the 22nd February, 1988

No. Rev.-A (B) 10-6/87.—The grievances of retired Government servants/employees relating to pensionary matters have been engaging the attention of the Government for some time past. In order to ensure that pensionary claims of Government employees are settled expeditiously, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to set up a Departmental Pension Adalat in the Himachal Pradesh Revenue Department, which shall comprise of the following:—

- (1) The Secretary (Revenue).
- (2) The Commissioners, Kangra, Mandi and Saimla Divisions.
- (3) The Director of Land Records-cum-Director, Consolidation of Holdings, H.P., Shimla-171002.
- (4) The Settlement Officers, Kangra at Dharamshala and Shimla and Kinnaur districts at Sanjauli, Shimla-171006.

2. The Departmental Adalat shall consider the following matters:—

- (1) Cases of the H. P. Revenue Department's retirees to whom pension/gratuity has not been sanctioned.



- (2) Wrong fixation of pension on the initial stage as a result of revision of pension against which a pensioner may have represented to the department.
- (3) Other grievances relating to the pensioner of the department.
- (4) Cases of such pensioners of H. P. Revenue Department, who may have gone to the Court of Law for the redressal of their grievances with a view to have their settlement outside the Court.
- (5) Reviewing of pending pension cases in the H.P. Revenue Department and finding solution to bring down pendency to the minimum and expeditious settlement of pension cases.
- (6) Monitoring for expeditious settlement of pension cases at the level of Departmental Pension Adalat.

3. The retired Government employees will be at liberty either to address their representations to the Finance Department (in the State Pension Adalat) or to the concerned Head of Office/Head of Department who had prepared their pension papers, with copies thereof to be endorsed to the Secretary (Revenue) as well as to the Senior Deputy Accountant General (A & E), Himachal Pradesh. On receipt of representations from the retirees, the concerned Head of Office/Head of Department will prepare detailed background note on each case and thereafter send/place the same before the Departmental Pension Adalat for consideration and decision. In cases, where it is not possible to find out a solution, the same will be referred to the Finance Department (in the State Pension Adalat).

4. The Meeting of the Departmental Pension Adalat will be held once every month.

गिमला-171002, 7 दिसम्बर, 1991

संख्या रेव-ए(बी) 2-5/90.—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (सी०)(बी०)(7) 6/88, दिनांक 4-7-1989 द्वारा सरकार ने प्रत्येक जिनश्रेणी कार्यालय में कार्यरत अधीक्षक (ग्रेड-II) के एक पद का, पंजाब पद्धति के आधार पर, दिनांक 20-1-1989 से अधीक्षक ग्रेड-I (राजपत्रित श्रेणी-II) वेतनमान 2200—4000 रुपये में, क्रमान्वित करने का निर्णय किया है।

2. उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश प्रत्येक जिलाधीन कार्यालय में कार्यरत निम्नलिखित क्रमान्वित किये गये अधीक्षक (ग्रेड-II) के पदाधिकारी को अधीक्षक ग्रेड-I (द्वितीय श्रेणी) वेतनमान रुपये 2200-50-2400-60-2700-75-3000-100-4000 के पद पर तदर्थ आधार पर 6 मास के लिए या ये पद नियमित रूप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो, क्रमान्वित करने के तत्काल सहर्ष आदेश करते हैं :—

1. श्री दीना नाथ, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर
2. श्री निचक राज शर्मा, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, ऊना
3. श्री मरघा नन्द, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, कांगड़ा
4. श्री सोम दत्त, अधीक्षक, कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना०), देहरा, जिला कांगड़ा।
5. श्री नेक राम, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, मण्डी
6. श्री ऊमा शर्कर, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, मिरमौर
7. श्री एस० बी० लाल, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, मिरमौर
8. श्री बर्की राम, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, जिलासपुर
9. श्री हेम चन्द, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, मण्डी
10. श्री पीयूष स्वामी, अधीक्षक, उपायुक्त कार्यालय, मण्डी

3. राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिकारियों की तैनाती

निम्न रूप से करने का आदेश भी सहर्ष करते हैं :—

क्रम	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान संख्या
1.	श्री दीना नाथ	उपायुक्त कार्यालय, चम्बा
2.	श्री निचक राज शर्मा	उपायुक्त कार्यालय, ऊना
3.	श्री मरघा नन्द	उपायुक्त कार्यालय, कांगड़ा
4.	श्री सोम दत्त	उपायुक्त कार्यालय, हमीरपुर
5.	श्री नेक राम	उपायुक्त कार्यालय, किन्नौर
6.	श्री ऊमा शर्कर	उपायुक्त कार्यालय, मिरमौर
7.	श्री एस० बी० लाल	उपायुक्त कार्यालय, सोलन
8.	श्री बर्की राम	उपायुक्त कार्यालय, जिलासपुर
9.	श्री हेम चन्द	उपायुक्त कार्यालय, शिमला
10.	श्री पीयूष स्वामी	उपायुक्त कार्यालय, मण्डी।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
वित्तियुक्त एवं सचिव।

(राजस्व-क)

गिमला-171 002, 28 दिसम्बर, 1992

संख्या रेव-ए(बी) 3-9/91.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री हेम चन्द कपूर, अधीक्षक वर्ग-I—(राजपत्रित श्रेणी-II), उपायुक्त कार्यालय, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-1-1993 (अप्रैल) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने के आदेश देते हैं।

श्री० पी० यादव,  
वित्तियुक्त एवं सचिव।

गिमला-2, 30 दिसम्बर, 1992

संख्या रेव-ए(बी) 1-5/85-II.—भारत के राष्ट्रपति, श्री रती राम शर्मा, नाथन तहसीलदार, अम्बर, जिला ऊना को तहसीलदार (राजपत्रित श्रेणी-II) वेतनमान रुपये 2100—3700 के पद पर तदर्थ आधार पर 6 मास के लिए या वह पद नियमित रूप से भरे जाने तक जो भी पहले हो, पदोन्नत करने के तत्काल सहर्ष आदेश करते हैं।

2. भारत के राष्ट्रपति, श्री रती राम शर्मा को बतौर तहसीलदार, कांगा (जिला लाहौल एव स्पिति), श्री कल्याण चन्द, तहसीलदार के स्थान पर तैनात करने के आदेश भी सहर्ष करते हैं।

3. इन पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रती राम शर्मा का तहसीलदार पद पर नियुक्त रहने, बरिष्ठता या नियमित पदोन्नति पर अधिकार नहीं होगा।

गिमला-2, 8 जनवरी, 1993

संख्या राज० ए (बी०) 2-3/76-4.—भारत के राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्शानुसार श्री मखन लाल, अधीक्षक ग्रेड-II को भू-एकत्रीकरण अधिकारी के पद पर श्रेणी-II (राजपत्रित) वेतनमान 2000—3500 रुपये में पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश करते हैं।

राष्ट्रपति पुनः आदेश करते हैं कि श्री मखन लाल, भू-एकत्रीकरण अधिकारी के पद पर तैनाती से पूर्व भू-संस्था अधिकारी, कांगड़ा के अन्तर्गत छ. माह का भू-संस्था प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(डी-शाखा)

गिमला-2, 14 जनवरी, 1993

संख्या रेव-बी०(ए०) 1-12/91.—भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का अधिनियम संख्या 6) की धारा 28 की उप-धारा 1 के खण्ड (बी०) में प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत और सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री माहन लाल शर्मा, सहायक

आयुक्त, परमाणु को महापक्ष समर्पित प्रथम श्रेणी की शक्तियों सहित प्रदान करते हैं, जो कि उनके द्वारा जिला साला के परमाणु में उनके क्षेत्राधिकार को स्थानीय सीमाओं के अन्दर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रमाण की जायेगी।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
वित्तियुक्त एवं सचिव।

शिमला-2, 22 जनवरी, 1993

संज्ञा रैव-1(बी0) 3-7/79.—भारत के राष्ट्रपति इस विभाग की समसंयुक्त अधिसूचना, दिनांक 5-12-1992 जिसके अन्तर्गत श्री जगत बन्धु, जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू का जिला राजस्व अधिकारी, ऊना क पद पर स्थानान्तरित किया गया था, को अनहित में तत्काल प्रभाव से रद्द करने के सहित आदेश करते हैं।

एम0 एम0 सिद्ध,  
वित्तियुक्त एवं सचिव।

शिमला-171002, 20 मार्च, 1993

संज्ञा रैव-0-ए (बी) 1-1/93.—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित तहसीलदारों के स्थानान्तरण/नियुक्तियों के आदेश अनहित में तत्काल प्रभाव से सहित करते हैं:—

1. श्री बी0 एम0 अतरी, तहसीलदार, भू-व्यवस्था, ऊना को स्थानान्तरित करके तहसीलदार, मरगावाट श्री सुभाष चन्द पाल के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
2. श्री सुभाष चन्द पाल, तहसीलदार, मरगावाट को स्थानान्तरित करके तहसीलदार, कोटबाई, जिला शिमला के रिक्त स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
3. श्री जगदीश चन्द शर्मा, तहसीलदार जिन्हें न.दोन (भू-व्यवस्था) से कुल्लू स्थानान्तरित किया गया है, को अब तहसीलदार (भू-व्यवस्था), ऊना, श्री बी0 एम0 अतरी के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
4. श्री भागी रथ हिमालयन, तहसीलदार (भू-व्यवस्था), प्रन्व, जिला ऊना को स्थानान्तरित करके तहसीलदार, काजा के रिक्त पद पर नियुक्त किया जाता है।
5. श्री सुभाष चन्द सकलानी, तहसीलदार, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी को स्थानान्तरित करके तहसीलदार, संगडाह स्थित रेणुका, श्री लायक राम झामटा के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
6. श्री लायक राम झामटा, तहसीलदार संगडाह, जिला सिरमौर को स्थानान्तरित करके तहसीलदार, कसौली, जिला सोलन श्री मोती लाल डमालू के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
7. श्री मोती लाल डमालू, तहसीलदार, कसौली, जिला सोलन को स्थानान्तरित करके तहसीलदार, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, श्री सुभाष चन्द सकलानी के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।
8. श्री मदन सिंह पुण्डीर, तहसीलदार, कुल्लू को तहसीलदार, कोटबाई, जिला शिमला क पद पर किया गया स्थानान्तरण रद्द किया जाता है।

आओ पी0 यादव,  
वित्तियुक्त एवं सचिव।

## RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATIONS

Shimla-171002, the 2nd January, 1988

No. RD-I-B(2)/1/83.—The Governor, Himachal Pradesh on recommendations of the Departmental Promotion

Committee and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to order promotion of Smt. Sheela David to the post of Lady Circle Supervisor (Class-II Gazetted) in the pay scale of Rs. 825-25-850-30-1000/40-1200/50-1400-60-1580 on regular basis with immediate effect and post her as such at Dharamshala (Kangra), Himachal Pradesh.

2. Smt. Sheela David will be on probation for a period of two years from the date of her taking over as Lady Circle Supervisor on regular basis.

Shimla-171002, the 2nd January, 1988

No. RID. I-B (3)27/83.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Smt. Usha Chopra, Lady Social Education Organiser as Lady Circle Supervisor in the pay scale of Rs. 825-25-850-30-1000/40-1200/50-1400-60-1580 (Class-II Gazetted) purely as a temporary measure on *ad hoc* basis for a period of six months or till the post is filled up on regular basis in accordance with the Recruitment and Promotion Rules relating to the post of Lady Circle Supervisor whichever is earlier, with immediate effect.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post Smt. Usha Chopra as Lady Circle Supervisor at Hamirpur (H. P.) against a vacant post.

3. This will not confer any right whatsoever for promotion to the post of L.C.S., Seniority etc. upon Smt. Usha Chopra.

Shimla-2, the 4th January, 1988

No. RDD-II-B(5)-6/86.—Consequent upon the introduction/implementation of Training and Visit System of Agriculture Extension in Himachal Pradesh with the assistance of the World Bank, the following 522 posts of Village Development Co-ordinators (Gram Sewaks) and Panchayat Secretaries are hereby transferred to Agriculture/Horticulture Departments respectively for the smooth implementation of the said project as under:—

No. of posts	Transferred to		Remarks	
	I Agri- culture Department	I Horticul- ture De- partment		
(a)	(b)	(c)	(d)	
(i) Filled	257	157	100	From Village Development Co-ordinators. =130
				From Panchayat Secretaries. =127
(ii) Vacant posts	265	165	100	From Village Development Co-ordinators. =240
				From Panchayat Secretaries. =25
Total ..	522	322	200	

By order,  
Sd./-

Financial Commissioner Dev.-cum-Secretary(RD.).

### ORDERS

Shimla-2, the 22nd February, 1988

No. RDI-B(6) 2/87-5580.—In partial modification of this Department Order No. RD-I-B(6) 2/86, dated

19-10-1987, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to post Shri Padam Singh Block Development Officer (Ad hoc) in Rewalsar Block with immediate effect in public interest.

Shimla-2, the 26th February, 1988

No. RD-I-B(6)2/87-6543.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Dev Singh Negi, SE & BPO as Block Development Officer (Class-II Gazetted) in the pay scale of Rs. 825-25-850-30-1000/40-1200/50-1400-60-1580 on ad hoc basis. This is a purely temporary promotion and will not confer any right of seniority etc. on him.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post him as Block Development Officer in Keylong Block, District Lahaul and Spiti in public interest.

V. K. BHATNAGAR,  
Director-cum-Joint Secretary.

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 2 फरवरी, 1993

संख्या डी० डी० ए०-109/89-मार्ट-197.—भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश में इस विभाग की अधिसूचना संख्या डी० डी० ए०-106/89-II, दिनांक 4-7-89 व संख्या डी० डी० ए०-122/90-आर० डी०, दिनांक 10-7-1990 द्वारा मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर गठित राज्य स्तरीय तालमेल एवं स्वीकृति समिति को भंग करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

भारत के राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश में मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय तालमेल एवं स्वीकृति समिति के निम्न प्रकार के तत्काल पुनर्गठन का सहर्ष आदेश देते हैं :—

1. मलाहकार, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष
2. माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला सदस्य
3. मयूक्त सचिव (डी० पी० ए० पी०), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, ब्लाक नं० 11, मन्जिल-6, सी० जी० आर० कम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली। सदस्य
4. वित्तयुक्त (विकास) एवं सचिव (ग्रा० वि० वि०), हिमाचल प्रदेश। सदस्य
5. वित्तयुक्त एवं सचिव (जनजातीय विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2। सदस्य
6. सचिव (सिचाई एवं जन स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला। सदस्य
7. सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला सदस्य
8. उप-कुलपति, डा० यशवन्त सिंह परमाणु उद्यान एवं वाणिज्य विद्यालय, नौशी, मानन, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
9. उप-कुलपति, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
10. मलाहकार (योजना), हिमाचल प्रदेश, शिमला सदस्य
11. मुख्य अभियन्ता (सिचाई एवं जन स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश, शिमला। सदस्य
12. प्रधान, मुख्य प्रशासन (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला। सदस्य
13. मुख्य मन्त्र आरक्षी, हिमाचल प्रदेश, बिलामपुर सदस्य
14. निदेशक, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 सदस्य

15. निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 सदस्य
16. निदेशक, उद्यान, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 सदस्य
17. जिलाधीश, लाहौल एवं स्पिति, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
18. जिलाधीश, किन्नोर स्थित रिकांग पिमो, जिला किन्नोर, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
19. अधीक्षण अभियन्ता (सिचाई एवं जन स्वास्थ्य), रिकांग पिमो, जिला किन्नोर, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
20. परियोजना निदेशक, मरुस्थल विकास परियोजना, काजा, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
21. परियोजना निदेशक, मरुस्थल विकास परियोजना, पूह, जिला किन्नोर, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
22. अध्यक्षपाल, वन, रामपुर बुझहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
23. वन मण्डलाधिकारी, काजा, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
24. वन मण्डलाधिकारी, पूह, जिला किन्नोर, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
25. अधिशासी अभियन्ता (सिचाई एवं जन स्वास्थ्य), काजा, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
26. अधिशासी अभियन्ता (सिचाई एवं जन स्वास्थ्य), पूह, जिला किन्नोर, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
27. परियोजना अधिशासी, मरुस्थल विकास कार्यक्रम राज्य समन्वयक शाखा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2। सदस्य
28. निदेशक (ग्रा० वि० एवं परियोजना) समन्वयक, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2। सदस्य-सचिव

अतार सिंह,  
वित्तयुक्त (विकास) एवं सचिव।

शिमला-2, 4 मार्च, 1993

संख्या: एस० एम० टी०-41/85.—इस विभाग की पूर्व अधिसूचना संख्या एस० एम० टी०-41/85-आर० डी० डी०, दिनांक 3 अक्टूबर, 1985 का अधीक्षण करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय ट्राईसम संचालन उप-समिति के पुनर्गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. मलाहकार (क) माननीय राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश .. अध्यक्ष
2. वित्तयुक्त (विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार .. सदस्य
3. निदेशक (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार .. सदस्य
4. कार्यकारी अधिकारी खादी एवं ग्रामीण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश .. सदस्य
5. प्रबन्ध निदेशक, लघु उद्योग एवं निर्यात निगम, हिमाचल प्रदेश .. सदस्य
6. प्रबन्ध निदेशक, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, हिमाचल प्रदेश .. सदस्य
7. मलाहकार (योजना), हिमाचल प्रदेश, शिमला .. सदस्य
8. मुख्य परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अधिभरण, हिमाचल प्रदेश .. सदस्य
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूको बैंक .. सदस्य
10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिमला .. सदस्य
11. क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक .. सदस्य
12. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, सुन्दरनगर, जिला मण्डी .. सदस्य
13. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश .. सदस्य सचिव

उप-समिति के निम्नलिखित मुख्य कार्य होंगे :—

प्रशिक्षण संस्थानों और मास्टर काफ्ट्समैन/दस्तकार जो ग्रामीण युवकों को ट्राईसैस के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं के कार्यों को देखना।

विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता का पता करना तथा चल रहे प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा किस तरह सफल प्रशिक्षण का मंचालन हो और उनकी सुदृढ़ता के लिए सिफारिशें करना।

विभिन्न व्यवसायों के लिए चल रहे पाठ्यक्रम की देख-रेख और जहाँ आवश्यकता हो पाठ्यक्रमों में बदलाव लाना।

ज़िला ग्रामीण विकास अधिकरणों से प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने हेतु प्राप्ति प्रस्तावनाओं का अनुमोदन और अनुमोदित प्रस्तावनाओं का ग्रामीण विकास मन्त्रालय को ग्रामीण कार्यकारी हेतु प्रेषण करना।

चयनित समूहों के ग्रामीण युवकों से सम्बन्धित कार्यों की उन्नति हेतु कार्य।

ट्राईसैस योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना।

प्रचार अभियान को कार्य रूप देना।

अन्तर सिंह,  
वित्तायुक्त एवं सचिव।

## SOCIAL AND WOMEN'S WELFARE DEPARTMENT

### NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 12th February, 1988

No. Kalyan. A(4)-1/88.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Shri Rangila Ram Rao, I.L.A. as non-official member in the Gujjar Welfare Board constituted vide this Department notification No. Kalyan-A(4)-8/83, dated 6-12-83 the term of which as further been extended for a period of three years with effect from 6-12-86 vide this department notification No. Kalyan A(4)-15/86, dated 7-7-1987.

2. The above non-official member will be entitled to draw T. A. and D. A. in respect of the journey performed by him in connection with the meetings of the Board as defined in the Annexure circulated vide this department notification No. WLF.A(4)-8/83, dated 12-12-1983.

AJAY PRASHAD,  
Secretary (Welfare).

शिमला-171002, 5 जनवरी, 1993

संख्या कल्याण (बी) 9-4/75.—भारत के राष्ट्रपति, विभागीय पदेनति समिती को सिफारिश पर, समाज एवं महिला कल्याण विभाग में निम्न जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारियों (श्रेणी-II राजपत्रित) को वेतनमान 2100-50-2400-60-2700-75-3000-100-3700 रुपये में स्थाई करने के आदेश सहित तत्काल से करते हैं :—

1. श्री ज्ञान सिंह ठाकुर
2. श्री प्रमर नाथ नर
3. श्री हरि कृष्ण कोशल

परमिन्दर हीरा,  
आयुक्त एवं सचिव।

## TRANSPORT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd February, 1988

No. 912/88-Transport.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a High Powered Committee to go into the entire working of Himachal Road Transport Corporation. The Committee will constitute the following members:—

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Hon'ble Transport Minister                          | Chairman.        |
| 2. Shri Jagdev Chand, M.L.A.                           | Member           |
| 3. Kanwar Durga Chand, M.L.A.                          | -do-             |
| 4. Shri Hira Singh Pal, M.L.A.                         | -do-             |
| 5. Shri Yogindra Chandra, M.L.A.                       | -do-             |
| 6. Shri Rangila Ram Rao, M.L.A.                        | -do-             |
| 7. Shri Dharam Vir, Vice Chairman, H.R.T.C.            | -do-             |
| 8. The Secretary (Finance), Govt. of H. P.             | -do-             |
| 9. The Secretary (Transport), Govt. of H. P.           | -do-             |
| 10. Commissioner, Transport, H. P.                     | -do-             |
| 11. Shri B. D. Thapar                                  | -do-             |
| 12. Managing Director, M.J.D.C.                        |                  |
| Managing Director, Himachal Road Transport Corporation | Member-Secretary |

The terms of reference of the Committee will be as follows:—

1. The Committee would go into the entire working of Himachal Road Transport Corporation including the causes of accidents in the buses of H.R.T.C. and would suggest ways to reduce the accident.
2. The Committee would also suggest the streamlining of the working of H.R.T.C.
3. The Committee would submit its report within the period of 2 months.
4. The non-official members will be entitled to the TA/DA as admissible under the rules.

By order,

S. S. SIDHU,  
Commissioner-cum-Secretary.

## TOURISM DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 1988

No. 10-8/84-TSM(Sectt).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute district level "Fossil Park Committee" to devise ways and means for systematic development of Fossil Park, Suketi, District Sirmour, Himachal Pradesh, as under with immediate effect:—

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Deputy Commissioner, Sirmour, Himachal Pradesh.                            | Chairman |
| 2. Shri Ajay Bahadur Singh, M.L.A., Nahan.                                    | Member   |
| 3. Commissioner, Tourism, Himachal Pradesh or his representative.             | Member   |
| 4. Director, Geological Survey of India, Himachal Pradesh Circle, Chandigarh. | Member   |
| 5. Executive Engineer (B&R), Nahan  | Member   |
| 6. Executive Engineer (I&PH), Nahan   | Member   |
| 7. Himachal Pradesh Tourism Development Corporation officer at Chandigarh.    | Member   |

8. State Geologist, Himachal Pradesh, Shimla.	Member	The Committee will hold its meetings from time to time and take necessary steps for the proper development of the Park.
9. Block Development Officer, Nahan	Member	
10. Divisional Forest Officer, Nahan	Member	The terms and conditions for TA/DA to the non-official member who is the member of Himachal Pradesh Vidhan Sabha shall be as usual.
11. Sub Divisional Magistrate, Nahan.	Member-Secretary.	

## भाग 2—वैधानिक नियमों की छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा)

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

नीलामी सूचना

अधिसूचना

शिमला, 4 अप्रैल, 1993

कुल्लू, 3 अप्रैल, 1993

संख्या उद्योग-भू (खनि-4) लघु-174/92.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला ऊना को लघु खनिज खानों की नीलामी महा-प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊना के कार्यालय में दिनांक 12-5-1993 को प्रातः 11.00 बजे की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए महा-प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊना से सम्पर्क स्थापित करें।

भवदीय,  
हस्ताक्षरित/-  
निदेशक, उद्योग।

लोक सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 4 फरवरी, 1993

संख्या 5-128/90-पब-भाग-2.—हिमाचल प्रदेश वितीय नियम 1971 के उप-नियम 1.17 और 1.26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री वीर चन्द्र भूक, संयुक्त निदेशक, लोक सम्पर्क को निदेशालय लोक सम्पर्क के ग्रहण एवं वितरण अधिकारी तथा निदेशालय लोक सम्पर्क में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं आकस्मिक व्यय के कार्यालय प्रमुख तथा नियंत्रण अधिकारी की शक्तियों मुख्य शीर्ष 2220—सूचना एवं प्रचार के तहत दिनांक 4-2-1993 से श्री छैरिंग डूंगे, उप निदेशक के स्थान पर जो इस समय अवकाश पर है, प्रदान की जाती है। यह आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।

देवी प्रसाद जोशी,  
निदेशक।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

अधिसूचना

बिलासपुर, 26 मार्च, 1993

संख्या एक0डी0एस0बी0एस0पी0 (आपूर्ति) 86-11-1211 से 71.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एक0डी0एस0 7-181 (आपूर्ति) 86-11-445-505, दिनांक 8 फरवरी, 1993 द्वारा आवश्यक वस्तुओं का अधिकतम परचून विक्रय मूल्य निर्धारण किया गया था कि प्रसंग जारी रखते हुए जो कि हिमाचल प्रदेश अनायास राजपत में दिनांक 20 फरवरी, 1993 को प्रकाशित हो चुकी है तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी, मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3(1) (ई) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, मैं, तम्बू श्रीधर, जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर आदेश जारी करता हूँ कि उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित अधिकतम परचून विक्रेता मूल्य अगले दो माह यानि 20-5-1993 तक लागू रहेगा।

तम्बू श्रीधर,  
जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

संख्या 3681-3800.—मैं, जीवनन्द जीवन, जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम परचून मूल्य निर्धारण सम्बन्धी पिछले सभी आदेशों व अधिसूचनाओं का अधि-क्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी, मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अधिसूचनाओं संख्या एक0डी0एस0 0-3(2)/77, दिनांक 30-10-80 द्वारा संशोधित है कि धारा 3 (1)(ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं के सभी कर सहित प्रत्येक के सक्षम दर्शाए गए अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करता हूँ:—

क्रमांक आवश्यक वस्तु का नाम अधिकतम निर्धारित परचून दरें सभी करें सहित

1	2	3
1. मोट बकरा/मेढा	40.00	रु0 प्रति किलोग्राम
2. मुर्गी डेस्ट	40.00	" "
3. मुर्गी ब्राईलर	45.00	" "
4. मोट सूअर	30.00	" "
5. मछली तली हुई	56.00	" "
6. मछली कच्ची	30.00	" "
7. डबल रोटी वजन 400 ग्राम	3.25	थोक भाव तथा 3.50 परचून भाव।

पका हुआ खाना किसी भी होटल/ढाबे में :

8. चपाती तन्दूरी	1.00	रुपये प्रति
9. चपाती तवे वाली	0.75	" "
10. परांठा स्टफड	2.50	" "
11. दो परी चना सहित	3.50	" "
12. प्रति खुराक दाल सब्जी सहित	8.00	" "
13. चावल प्रति प्लेट	3.00	" "
14. दाल सादी प्रति प्लेट	2.00	" "
15. दाल फ्राईड प्रति प्लेट	5.00	" "
16. सब्जी सादी प्रति प्लेट	2.00	" "
17. सब्जी स्पेशल प्रति प्लेट	8.00	" "
18. सब्जी पनीर वाली प्रति प्लेट	18.00	" "
19. मोट प्रति प्लेट	16.00	" "
20. मोट रोस्टेड प्रति प्लेट	18.00	" "
21. ग्रामलेट दो अण्डों का दो	5.00	" "
स्लाईस सहित।		
22. चिकन करी प्रति प्लेट	18.00	" "
23. दूध कच्चा प्रति किलोग्राम	6.50	" "
24. दूध उबला प्रति किलोग्राम	7.00	" "
25. दूध उबला मोठा सहित प्रति किलोग्राम	7.50	" "
26. दही प्रति किलोग्राम	10.00	" "
27. चाय प्रति गप	1.00	" "
28. छुपका मोट सहित प्रति प्लेट	8.00	" "
29. छुपका मोट सहित आधी प्लेट।	5.00	" "
30. मोमो प्रति प्लेट जिसमें पांच पीस हो।	7.00	" "

यह भी आदेश देना है कि सभी दुकानदार को दुकान में महज दृष्टिगत स्थान पर मूल सूची हिन्दी (देवनागरी में) प्रदर्शित करना और उस पर दुकानदार/भागीदार/प्रबंधक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक दुकानदार ग्राहक को कैशमेंमो जारी करेगा जिसमें दुकानदार का नाम व पता तथा हस्ताक्षर और ग्राहक ने ली गई कीमत का पूर्ण विवरण हो।

यह आदेश सम्पूर्ण जिला कुल्लू में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने से एक माह को प्रवृत्ति तक लागू रहेगा।

जीवानन्द जीवन,  
जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, सोलन, जिला सोलन

आदेश

सोलन, 24 मार्च, 1993

संख्या पेसी/3-19/87.—भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम नं० 59 अथवा 1988) की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क जो उन्मायाधीन, अर्को के न्यायालय में शुरू होकर पुलिस बाना, उप-कोष, तहसील एवं उप-मण्डल कार्यालय अर्को तक जाती है कच्ची होने के कारण दुर्घटना होने और सड़क के धंसने की आशंका से भारी वाहनों के यात्रागमन के लिए प्रतिबन्धित घोषित की जाती है।

यह आदेश तुरन्त लागू होंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

उपमा चौधरी,  
जिला दण्डाधिकारी, सोलन।

INDIRA GANDHI MEDICAL COLLEGE, SHIMLA-1

OFFICE ORDER

Shimla-171001, the 14th December, 1992

No. HFW(MC-A)(A)2-2/79-27155.—In exercise of the powers vested in me under Rule 126 of Himachal Pradesh Financial Rules, 1971 (Vol. I), I hereby declare Dr. K. S. Rana, Deputy Medical Superintendent, Indira Gandhi Hospital, Shimla as Drawing and Disbursing Officer under the following heads of accounts in place of Dr. D. S. Puri, Medical Superintendent, Indira Gandhi Hospital, Shimla who is proceeding on winter vacation w. e. f. 15-12-1992 to 28-1-1993:—

(i) 2210—Medical & Public Health  
01—Urban Health Services (Allopathy)  
110—Hospital and Dispensaries I. G. Hospital (N P)

(ii) 05—Medical Education, Training and Research  
Post Graduate Training of Doctors (NP)

(iii) 06—Public Health  
Training in Public Health Services

(iv) 101—Prevention & Control of diseases Leprosy  
Eradication Programme (N P)

2. Dr. K. S. Rana Deputy Medical Superintendent will also function as Medical Superintendent, Indira Gandhi Hospital, Shimla during the leave period of Dr. D. S. Puri and shall be Controlling Officer in respect of T. A. claims of Class III and Class IV employees of Indira Gandhi Hospital, Shimla.

Sd/-

Director of Medical Education  
and Research, Indira Gandhi  
Medical College, Shimla.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी सभायें (पूर्वीय मण्डल), शिमला-171001

अधिसूचना

शिमला-1, 5 जनवरी, 1993

संख्या डी० ग्रा० ई०-21-6/86-कूप.—जबकि इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3164-66, दिनांक 23-12-91 द्वारा दी सुन्नी तहसील सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता संघ सीमित के मनोनीत संचालक मण्डल की अवधि, दिनांक 22-12-92 को समाप्त हो चुकी है।

जबकि महायुक्त पंजीयक, सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला से पत्र संख्या ए० ग्रा०/एन० एम० एन०/कूप-3-201/91 (सामान्य)-197, दिनांक 5 जनवरी, 1993 के द्वारा सूचित किया है कि संघ की कुल 20 सहकारी सभायें सदस्य हैं जिसमें से 13 सहकारी सभायें हिमाचल प्रदेश, राज्य सहकारी बैंक सीमित की दोषी कृणी हैं। अतः प्रजातान्त्रिक रूप से संचालक मण्डल का गठन करना सम्भव नहीं है तथा अनुरोध किया है कि दी सुन्नी तहसील सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता संघ सीमित में मनोनीत संचालक मण्डल का गठन किया जावे जिस हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की सिफारिश की गई है तथा यह भी प्रमाणित किया गया है कि मनोनीत किये जाने वाले निम्न सदस्य सहकारी सभायों के प्रत्यक्ष रूप से दोषी कृणी नहीं हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए मैं, ग्रा० डी० नं०, उप-पंजीयक सहकारी सभायें (पूर्वीय मण्डल), शिमला-1 हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1968 की धारा 35-ग के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न को दी सुन्नी तहसील सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता संघ सीमित सुन्नी के कार्य संचालन हेतु मनोनीत संचालक मण्डल के रूप में एक वर्ष की अवधि का प्रजातान्त्रिक रूप से संचालक मण्डल के गठन तक जो भी पहले हो मनोनीत करता हूँ।

1. श्री जीत राम वर्मा, पुत्र श्री मन्ना राम, गांव गटेरी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश .. अध्यक्ष।
2. श्री नीम चन्द पुत्र श्री टी० ग्रा० वर्मा, गांव बनी रियोग (डुर्गापुर), तहसील सुन्नी, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश .. संचालक
3. श्री पञ्चम देव पुत्र श्री हेम दत्त, गांव चवेडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला ..
4. श्री हुकम चन्द वर्मा पुत्र श्री जीत राम, गांव दीमान, तहसील सुन्नी, जिला शिमला ..
5. श्री बालक राम, गांव जिलडू, डा० बटनोल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला ..
6. श्री दुर्गा दत्त वर्मा पुत्र श्री मनी राम, गांव शकरोडी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला ..

सरकारी प्रतिनिधि :

1. निरीक्षक सहकारी सभायें, मशोबरा
2. तहसीलदार, सुन्नी, जिला शिमला
3. विकास खण्ड अधिकारी, मशोबरा, जिला शिमला

रत्न चन्द गंग,  
उप-पंजीयक, सहकारी सभायें,  
(पूर्वीय मण्डल, शिमला-10)

कार्यालय महायुक्त पंजीयक, सहकारी सभाएं, जिला सिरमौर, नाहन

कार्यालय आदेश

नाहन, 17 मार्च, 1993

संख्या कोप 3-46/90-1481-84.—जैसा की दि सिरमौर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति महिला बहुदेशीय सहकारी सभा सिमिन, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर सहकारी सभा का कार्य बन्द पड़ा है और सभा लगातार हानियों को और बढ़ रही है।

जैसाकि उपरोक्त के सम्बन्ध में सभा के प्रधान को इस कार्यालय के पत्र संख्या कोप 3-46/90-1521, दिनांक 11 मार्च, 1992 द्वारा एक माह के भीतरी स्पष्टीकरण देने हेतु दिया गया था व जिसका कोई उत्तर कार्यालय में सभा द्वारा नहीं प्राप्त हुआ।

जैसाकि निरीक्षक सहकारी सभाएं, नाहन ने अपने निरीक्षण पत्र में भी सभा को विघटन में डालने हेतु सिफारिश की है।

अतः मैं, जगतेंद्र सिंह, महायक पंजीयक, सहकारी सभाएं जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं, अधिनियम, 1968 (एक्ट नं० 3 आफ 1969) की धारा 78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सभा को विघटन में डालने के आदेश देता हूँ व धारा 79 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षक सहकारी सभाएं, नाहन को विघटक नियुक्त करता हूँ तथा साथ में यह निर्देश देता हूँ कि इस सभा को विघटन सम्बन्धी कार्य तीन माह में पूर्ण किया जावे।

जगतेंद्र सिंह,  
महायक पंजीयक, सहकारी सभाएं,  
जिला सिरमौर, नाहन।

## INDUSTRIES DEPARTMENT

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER,  
DISTRICT INDUSTRIES CENTRE, CHAMBA  
HIMACHAL PRADESH

### NOTICE UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Chamba, the 2nd February, 1991

No. Ind./C/MM/43/861.—Whereas a notice under section 23 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971, was served on Shri Tej Singh son of Shri Bhikho Ram Prop. M/s Tej Singh Handloom Industries, Village Parel, P. O. Sultanpur, Tehsil and District Chamba on 6-2-1991, calling upon the said Shri Tej Singh son of Shri Bhikho Ram to pay to me the said sum of Rs. 1998/- (Rupees 1300/- Principal + 698/- interest) upto date on or before 23-10-91 and whereas the said sum has not been paid. I hereby declare that the said sum of Rs. 1140/- (Rs. one thousand one hundred forty only) along with interest thereon upto the date of final payment is due and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

### SCHEDULE

All assets already existed before taking above loan and thereafter raised with the help of above loan by the Proprietor M/s Tej Singh Handloom Industries, V.P.O. Parel, Tehsil and District Chamba (Shri Tej Singh s/o Bhikho Ram and his legal heirs as the case may be).

D. K. SHARMA,  
General Manager,  
District Industries Centre, Chamba,  
District Chamba, Himachal Pradesh.

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER,  
DISTRICT INDUSTRIES CENTRE, CHAMBA  
HIMACHAL PRADESH

### NOTICE UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Chamba, the 2nd February, 1993

No Ind./C/MM/38/862.—Whereas a notice was served on Shri Bhagat Ram s/o Shri Hira Lal of Village and P.O. Masroond, Tehsil and District Chamba on 18-9-1992

under section 23 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971, calling upon the said Shri Bhagat Ram to pay to me the said sum of Rs. 2500/- (rupees two thousand five hundred only) and interest thereon upto date on or before 23-10-1992 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the said sum of Rs. 2500/- (rupees two thousand five hundred only) along with interest thereon upto the date of final payment is due and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

### SCHEDULE

Immoveable and moveable property exists with Shri Bhagat Ram son of Shri Hira Lal including that raised by way of above loans and such machinery tools etc. installed in the factory premises.

D. K. SHARMA,  
General Manager,  
District Industries Centre, Chamba,  
District Chamba, Himachal Pradesh.

### FORM 'L'

(See Rule 52)

### CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1848.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Shivalik Gram Udayog Brick workers Tile Industries works Association Village Basdehra, Tehsil and District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w. e. f. 1989-90 to 1992-93.

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent | } 10,000/- upto 1992-93 |
| 2. Surface Rent      |                         |
| 3. Contract Money    |                         |

JAI SINGH  
General Manager,  
District Industries Centre, Una,  
District Una, Himachal Pradesh.

### FORM 'L'

(See Rule 52)

### CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1876.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby Certify that a sum of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen Thousand) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Bishal Brick Kiln Production-cum-sale. Prop. Shri Bodh Raj, Village Raipur Saharon (Una) on account of following in respect of royalty for manufacture/ sale of pucca brick w. e. f. 1987-88 to 1992-93.

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent | } 15000/- up to 1992-93 |
| 2. Surface Rent      |                         |
| 3. Contract Money    |                         |

JAI SINGH  
General Manager  
District Industries Centre, Una,  
District Una, Himachal Pradesh.



FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1860.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70 SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 12500/- (Rupees Twelve Thousand five hundred only) is recoverable as arrears of Land revenue from M/s Gupta Brick comp. Village Basdehra, Tehsil and District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w. e. f. 1988-89 to 1992-93.

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent. | } 12500/- up to 1992-93 |
| 2. Surface Rent       |                         |
| 3. Contract Money     |                         |

JAI SINGH  
General Manager  
District Industries Centre Una,  
District Una, Himachal Pradesh.

FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1864.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 7500/- (Rupees Seven Thousand five hundred) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Shivshakti Brick Gram Udoyog Association Village Basdehra, Tehsil and District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w. e. f. 1990-91 to 1992-93.

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent- | } 7500/- up to 1992-93 |
| 2. Surface Rent.      |                        |
| 3. Contract Money.    |                        |

JAI SINGH,  
General Manager,  
District Industries Centre, Una,  
District Una, Himachal Pradesh.

FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 26th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1844.—In exercise of the power conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 12500/- (Rupees Twelve Thousand five hundred) only is recoverable as arrears of Land revenue from M/s

Rama Gram Udoyog Welfare Village Mobar Bhattali, Tehsil and District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of Pucca bricks w. e. f. 1988-89 to 1992-93.

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent | } 12500 - up to 1992-93 |
| 2. Surface Rent      |                         |
| 3. Contract Money    |                         |

JAI SINGH,  
General Manager,  
District Industries Centre, Una,  
District Una, Himachal Pradesh.

FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1872.—In exercise of the power conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concessions Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 7500/- (Rupees seven thousand five hundred) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Satluj Brick Gram Udoyog Association Village Basdehra, Tehsil and District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w. e. f. 1990-91 to 1992-93.

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent | } 7500/- upto 1992-93. |
| 2. Surface Rent      |                        |
| 3. Contract Money    |                        |

JAI SINGH,  
General Manager,  
District Industries Centre Una,  
District Una (H. P.).

FORM 'L'

(See rule 52)

CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1868.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 17500/- (Rupees seventeen thousand five hundred) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Shiv Shankar Kuteer Gram Udoyog Workers Village P. O. Andora, Tehsil Amb, District Una on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w. e. f. 1986-87 to 1992-93.

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent | } 17500/- upto 1992-93 |
| 2. Surface Rent      |                        |
| 3. Contract Money    |                        |

JAI SINGH,  
General Manager,  
District Industries Centre Una,  
District Una, (H. P.).

## FORM 'L'

(See rule 52)

## CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1856.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 12500/- (Rupees twelve thousand five hundred) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Himachal Brick Kiln Gram Udayog Workers Welfare Association Village Kungrat, Tehsil & District Una, on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w. e. f. 1988-89 to 1992-93.

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent. | } 12500/- upto 1992-93 |
| 2. Surface Rent.      |                        |
| 3. Contract Money.    |                        |

JAI SINGH,  
General Manager,  
District Industries Centre Una,  
District Una, (H. P.).

## FORM 'L'

(See rule 52)

## CERTIFICATE

Una, the 24th March, 1993

No. Ind/U/Brick Kiln/1828.—In exercise of the powers conferred by rule 52 of the Himachal Pradesh (Concession) Revised Rules, 1971 read with Himachal Pradesh Government Order No. 13-3/70-SI, dated 13th April, 1971.

I, Jai Singh, General Manager, District Industries Centre, Una, hereby certify that a sum of Rs. 17500/- (Rupees seventeen thousand five hundred) only is recoverable as arrears of land revenue from M/s Bharti Brick Gram Udayog Village Basdehra, Tehsil and District Una, on account of following in respect of royalty for manufacture/sale of pucca bricks w. e. f. 1986-87 to 1992-93 :—

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Royalty/Deed rent | } 17500/- upto 1992-93 |
| 2. Surface Rent      |                        |
| 3. Contract Money    |                        |

JAI SINGH,  
General Manager,  
District Industries Centre Una,  
District Una, (H. P.).

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रचलित संपत्ति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनेंशियल कमिशनर तथा कमिशनर आफ स्कूल टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ।

कृषि विभाग

शिमला, 8 जनवरी, 1993

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 28 दिसम्बर 1992

संख्या एच-बी (1)-1/75.—भारत के राष्ट्रपति, श्री ओ. सी. 0 वर्मा, उप निदेशक (कृषि) को संयुक्त निदेशक (कृषि), श्रेणी-1 राजपत्रित पद पर रुपये 3000—4500 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रथम तीन मास की अवधि अथवा जब तक संयुक्त निदेशक (कृषि) का पद विशिष्ट रूप से नहीं भरा जाता, जो भी पहले हो, तब तक पदोन्नति के तत्काल महर्ष आदेश देते हैं ।

उक्त पदोन्नति पूर्णतया अस्थायी तौर पर की गई है और इस अधिकांश को इससे इस पद पर निरन्तरता/पदोन्नति/वरीयता का कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा ।

राष्ट्रपति महोदय श्री ओ. सी. 0 वर्मा का तदर्थ पदोन्नति पर उन्हें कृषि निदेशालय में तैनात करने के महर्ष आदेश प्रदान करते हैं ।

शिमला-171002, 28 दिसम्बर, 1992

संख्या कृषि 0 बी-2 (10)/87.—विभागाध्यक्ष पदोन्नति समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति श्री एच. 0 एस. 0 दुग्गा, संयुक्त निदेशक (कृषि) को कृषि विभाग में अतिरिक्त निदेशक (कृषि) के पद पर अग्रणी एवं प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रेणी-1 राजपत्रित पद पर रु. 4500—6100 के वेतनमान में पदोन्नति के तत्काल महर्ष आदेश देते हैं ।

2. श्री एच. 0 एस. 0 दुग्गा, पदोन्नति की दो वर्ष की अवधि तक परिवर्तनीय अधीन रहेंगे ।

आदेश द्वारा,  
अन्तर सिंह  
वित्तियुक्त एवं कृषि उत्पादन आयुक्त ।

आदेश द्वारा/-  
हस्ताक्षरित/-  
कृषि उत्पादन आयुक्त ।

संख्या कृषि-बी-14 (1)/91.—भारत के राष्ट्रपति, श्री जे. 0 एस. 0 चन्देल प्रधानाचार्य, कृषि प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, मशाबरा को स्थाना-न्तित कर उप-निदेशक कृषि (पी. 0 एण्ड. 0 एम. 0) के कृषि निदेशालय में रिक्त पद पर तत्काल तैनात करने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

राष्ट्रपति महोदय श्री सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि डा. 0 भगत सिंह वीर, सज्जो विशेषज्ञ कृषि निदेशालय अग्रणी पद के अतिरिक्त प्रधानाचार्य, कृषि प्रसार प्रशिक्षण केंद्र मशाबरा का कार्यभार भी अगली अवस्था होने तक सम्भालेंगे ।

शिमला-2, 16 जनवरी, 1993

संख्या कृषि 0 एफ. 0 1 (3)/26-जून.—इस विभाग की सम-संयोजक अधिसूचना दिनांक 16-11-92 के क्रम को जारी रखते हुए भारत के राष्ट्रपति महोदय "प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम" के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण कार्य के सूचारु व समय-बद्ध संचालन हेतु श्री एम. 0 एस. 0 राणा, सहायक भू-संरक्षण अधि-कारी, पालमपुर को कृषि अभियन्ता (बायोमैस), शिमला व कृषि अभियन्ता, भंगरोट्ट की प्रदत्त मण्डल स्तरीय अधिकारी की तरह वित्तीय व तकनीकी शक्तियां निर्वहन करने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

राष्ट्रपति महोदय उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के भवन निर्माण कार्य को तीन मण्डलों में आवंटन करने व उनके मण्डल स्तरीय कार्य क्षेत्र विभिन्न प्रकार से निर्धारण के सहर्ष आदेश देते हैं :—

मण्डल	प्रभारी	कार्यक्षेत्र
1	2	3
1. शिमला (मुख्यालय)	कृषि अभियन्ता (बायोमैस)	शिमला शिमला, सोन व निरमौर ।
2. मण्डी (मुख्यालय)	कृषि अभियन्ता (भंगरोट्ट)	जिला मण्डी, जिलासपुर, कुल्लू व हमीरपुर ।
3. पालमपुर (मुख्यालय पालमपुर)	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, पालमपुर व ऊना ।	

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-3, the 15th January, 1988

No. 14-27/67-E&T-VI-906.—Whereas it has been reported that the declaration form 'F' (as mentioned below) referred to in sub-section 4 of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) are declared obsolete/invalid on account of the reasons stated against therein. Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-rule 10 of Rule 6 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970 the declaration forms bearing number as mentioned below shall be deemed to be obsolete/invalid with effect from the date noted against them :—

Sl. No.	No. of declaration form 'F' which have been declared invalid/obsolete	Name and address of the dealer to whom declaration form 'F' issued	Name and designation of Assessing Authority who issued form 'F'	Date from which declaration 'F' declared/obsolete invalid
1	2	3	4	5
1.	74051 to 74075	The 'F' forms were found lost in the office of Assessing Authority, Sirmaur at Nahan.	—	17-10-1987

Shimla-3, the 15th January, 1988

No. 14-27/67-E&T-VI-836.—Whereas it has been reported that the declaration form 'C' (as mentioned below) referred to in sub-section 4 of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) are declared obsolete/invalid on account of the reasons stated against therein. Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-rule 10 of the Rule 6 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970 the declaration form bearing number as mentioned below shall be deemed to be obsolete/invalid with effect from the date noted against them :—

Sl. No.	No. of declaration forms 'C' which have been declared invalid obsolete	Name and address of the dealer to whom declaration form 'C' issued	Name and designation of Assessing Authority who issued form 'C'	Date from which declaration forms 'C' declared obsolete/invalid
1	2	3	4	5
1.	Q/3 528115 and Q/3 528116	These forms found in torn condition by the Assessing Authority Solan District Solan.	—	22-12-1987

Shimla-3, the 17th February, 1988

No. 14-27/67-E&T-VI-3450-3540.—Whereas it has been reported that the declaration forms 'C' (as mentioned below) referred to in sub-section (4) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) are declared obsolete/invalid on account of the reasons stated against therein. Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-rule 10 of Rule 6 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970 the declaration forms bearing numbers as mentioned below shall be deemed to be obsolete/invalid with effect from the date noted against them :—

Sl. No.	No. of declaration forms 'C' which have been declared obsolete invalid	Name and address of the dealer to whom declaration forms 'C' issued	Name and designation of Assessing Authority who issued form 'C'	Date from which declaration forms 'C' declared obsolete/invalid.
1	2	3	4	5
1.	Q/3 794526 to Q/3 794550	M/s. New Daily Needs Store, Lakkar Bazar Solan SOL-CST-No. 1144.	Assessing Authority Solan	9-2-1988 (destroyed in fire).

HEM CHAND,

Excise and Taxation Commissioner,  
Himachal Pradesh.

## मत्स्य पालन विभाग

## अधिसूचना

शिमला-171002, 6 जनवरी, 1993

संख्या मत्स्य-खा0(6)-1/88.—भारत के राष्ट्रपति, श्री आर०पी० सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अधिकरण (एजन्सी), ऊना के प्रतिनिधित्वित कार्यकाल को एक वर्ष अर्थात् (दिनांक 11-10-92 से 10-10-93 तक) प्रतिनिधित्वित की सामान्य शर्तों के आधार पर और बढ़ाये जाने की महर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं।

आदेश द्वारा,  
अतार सिंह,  
कृषि उत्पादन आयुक्त,।

## उद्यान विभाग

## अधिसूचना

शिमला-171002, 10 फरवरी, 1993

सं० उद्यान-ख(8) 10/87.—भारत के राष्ट्रपति, श्री यदुवीर सिंह, अधीक्षक, ग्रेड-II को अधीक्षक ग्रेड-I वेतनमान रुपये 2200—4000, उद्यान विभाग में तदर्थ आधार पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

राष्ट्रपति, श्री यदुवीर सिंह को उद्यान निदेशालय में अधीक्षक ग्रेड-I के पद पर तैनाती के भी सहर्ष आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-  
वित्तायुक्त (विकास)।

DEPARTMENT OF INDUSTRIES  
NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 1988

No. Udyog (Ka) 3-2/81-II.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to add the following clause under Rule 22(2) of Procedure and Rules for the purchase of Stores by all Departments and Offices of the Government of Himachal Pradesh :—

- (c) "if any firm/firms (local unit) manufacturer, some more items at a later stage i.e. after opening of the tenders, such firm(s) may also be considered for the award of parallel rate contract with the prior approval of the Government."

By order,  
O. P. YADAV,  
Secretary.

हस्ताक्षरित/-  
अमायुक्त।

भाग 4—स्थानीय स्वायत्त शासन, म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

## अज्ञ

## भाग 5—व्यक्तिगत अधिसूचनाएं और विज्ञापन

व अदालत श्री बी. आर. जम्वाल, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री मुरेश चौधरी सुपुत्र अमृतमरिया राम, निवासी सामन, तहसील व जिला ऊना (हि० प्र०)।

वनाम

आम जनता

दरखास्त जे० धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट, 1969.

श्री मुरेश चौधरी सुपुत्र अमृतमरिया राम, निवासी सामन, तहसील व जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारी की है कि उनके पुत्र श्री दिनेश तथा विनाल का जन्म दिनांक 22-5-88 व 1-10-1989 को हुआ है लेकिन उनकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एनराज हो तो वह

दिनांक 10-5-93 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है वरना उपरोक्त व्यक्तियों की जन्म तिथि दर्ज करने वाले सम्बन्धित मन्त्रि, पंचायत को उपरोक्त बनाई गई तिथि दर्ज करने वाले आदेश दे दिये जायेंगे।

अज दिनांक 24-2-93 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

बी० आर० जम्वाल,  
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,  
ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)।

व अदालत श्री बी० आर० जम्वाल, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री परमेश्वरी दाम शर्मा सुपुत्र अनन्त राम शर्मा, निवासी बडेगाह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, (हि० प्र०)।

वनाम

आम जनता

दरखास्त जे० धारा 13 (3) जन्म एवम् मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट, 1969.

शिमला-171002, 20 मार्च, 1993

संख्या 11-2/93 (लंब) आई० डी०.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री दिनेश मेहता मारफत श्री पी० के० ककरेजा, मकान नं० 3346, सेक्टर 19-बी, चण्डीगढ़ और प्रबन्ध निदेशक, मै० हिम टैकनो फोरज प्रा० लि०, गांव व डाकघर वही, जिला सोलन तथा प्रबन्ध निदेशक, मै० हिम फोरज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मकान नं० 39, सेक्टर 28-ए, चण्डीगढ़ के मध्य नीचे दिए गये विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत को गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह भालना श्रम न्यायालय को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-अम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"कि क्या श्री दिनेश मेहता सुपुत्र श्री एम० एल० मेहता, इलेक्ट्री-शियन का प्रबन्ध निदेशक, मै० हिम टैकनो फोरज प्रा० लि० एवं मै० हिम फोरजिंग इंडिया प्रा० लि०, वही, जिला सोलन, (हि० प्र०) द्वारा बिना नोटिस व बिना जांच कार्यवाही के नौकरी से निकालना उचित व न्याय संगत है? यदि नहीं तो श्री दिनेश मेहता, इलेक्ट्रीशियन किस बेतन, मवा लाभ व राशन का पात्र है।"

श्री परमेशवरी दाम शर्मा सुपुत्र अनन्त राम शर्मा, निवासी बडेराह, हसील वनाणा, जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र महेश कुमार शर्मा का जन्म दिनांक 7-11-1989 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस शरे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-5-93 को सुबह 10 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है वरना उपरोक्त व्यक्ति की जन्म तिथि दर्ज करने वाले सम्बन्धित सचिव, पंचायत को उपरोक्त बताई गई तिथि दर्ज करने वाले आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-2-93 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

बी० आर० जम्वाल,  
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,  
ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० आर० जम्वाल, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना जिला ऊना (हि० प्र०)

श्री जगत राम सुपुत्र सुख राम, निवासी सैसोवाल, सब-तहसील हरोली, जिला ऊना (हि० प्र०)।

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर घारा 13 (3) जन्म एम् मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट, 1969.

श्री जगत राम सुपुत्र सुख राम, निवासी सैसोवाल, सब-तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री सीमा देवी का जन्म दिनांक 10-5-1987 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस शरे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-5-93 को सुबह 10 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है वरना उपरोक्त व्यक्ति की जन्म तिथि दर्ज करने वाले सम्बन्धित सचिव, पंचायत को उपरोक्त बताई गई तिथि दर्ज करने वाले आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-2-93 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

बी० आर० जम्वाल,  
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना;  
जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० आर० जम्वाल, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री यशवन्त सुपुत्र श्री रघवीर सिंह, निवासी भड़ियारा, सब-तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर घारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट, 1969.

श्री यशवन्त सिंह सुपुत्र श्री रघवीर सिंह, निवासी भड़ियारा, सब-तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके भानजे श्री प्रदीप कुमार सुपुत्र प्रताप सिंह उबा अश्वनी कुमार सुपुत्र सुभाष चन्द व अशोक कुमार सुपुत्र श्री रामलाल का जन्म दिनांक क्रमशः 6-6-1987, 23-10-1988 तथा 12-3-88 को हुआ है लेकिन उनकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस शरे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-5-1993 को सुबह 10 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है वरना उपरोक्त व्यक्तियों की जन्म तिथि दर्ज करने वाले सम्बन्धित सचिव, पंचायत को उपरोक्त बताई गई तिथियां दर्ज करने वाले आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-2-1993 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय से जारी हुआ।

मोहर।

बी० आर० जम्वाल,  
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,  
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ध्रुव वशिष्ठ, उप-मण्डल अधिकारी, शिमला (ग्रा०) जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री नरिन्दर कुमार नन्दा पुत्र श्री लेख राज नन्दा, निवासी न्यू टूट, गांव मजठारी, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर घारा 13 (3) जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट, 1969.

श्री नरिन्दर कुमार नन्दा पुत्र श्री लेख राज नन्दा, निवासी न्यू टूट, ग्राम मजठारी, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में उपरोक्त ऐक्ट के अन्तर्गत अपनी व अपने बच्चों की जन्म तिथि व मृत्यु दर्ज करवाने वाले प्रार्थना-पत्र गुजारा है। श्री नरिन्दर कुमार नन्दा उपरोक्त के अनुसार उनकी अपनी व पत्नी व बच्चा की जन्म तिथि निम्नलिखित है:-

1. श्री नरिन्दर कुमार नन्दा जन्म तिथि 2-5-1945, 2. श्रीमती सुदेश पत्नी श्री नरिन्दर कुमार की जन्म तिथि 9-8-1946, 3. श्री प्रसीम नन्दा पुत्र मृत्यु की तिथि 31-5-1991, 4. सुनील नन्दा पुत्र की मृत्यु तिथि 3-2-1993, 5. कु० नीरू नन्दा पुत्री जन्म तिथि 2-12-1974, 6. कु० नीलू नन्दा पुत्री जन्म तिथि 9-12-1977 है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जिनकी भी उक्त जन्म तिथि व मृत्यु की तारीख दर्ज करवाने वाले किसी भी प्रकार कोई शक हो तो वे इस न्यायालय में मिलि 18-5-1993 तक अपने आरोप पेश कर सकते हैं। यदि कोई भी आरोप उक्त तिथि तक इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि श्री नरिन्दर कुमार की अपनी व उनके बच्चों की जन्म तिथि व मृत्यु की तारीख नहीं है और वह तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज की जाएगी।

आज दिनांक 16-4-1993 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

ध्रुव वशिष्ठ,  
उप-मण्डल अधिकारी (ग्रा०),  
शिमला, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री भूलोक सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर

मुकद्दमा नं० 18/92 तारीख पेशी 30-4-93

नाम मुकद्दमा : विजय सिंह बनाम सर्वजनता

क्रिम मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर घारा 13 (3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण ऐक्ट, 1969.

श्री विजय सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी भवारना, तहसील पालमपुर ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनकी लड़की कुशल बन्धू का

जन्म 15-1-86 को हुआ है और उसका नाम ग्राम पंचायत रमेहड़ में दर्ज ही हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिस किसी को इस जन्म पंजीकरण के प्रति आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-4-93 प्रातः 10 बजें हाजर ग्रामालत आकर पेरवी मुकद्दमा करें अन्यथा जन्म पंजीकरण की इजाजत दे दी जाएगी।

आज दिनांक 27-3-93 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर यद्वाले से जारी किया गया।

मोहर।

मलोक सिंह,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

### भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

#### LAW DEPARTMENT (LEGISLATIVE WING)

#### NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 5th February, 1988

No. LLR-E(9)8/87-Legis.—The Delhi Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 1987 (Ordinance No. 9 of 1987) and the Delhi Administration (Amendment) Ordinance, 1987 (Ordinance No. 10 of 1987) recently promulgated by the President of India, which have already been published in the Gazette of India, Extra Ordinary Part-II, Section-I, dated the 24th December, 1987 are hereby republished in the Rajpatra, Himachal Pradesh, for general information of the public.

By order,  
Sd/-  
Secretary.

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 24th December, 1987/Pausa 3, 1909 (Saka)

#### THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1987

No. 9 OF 1987

*Promulgated by the President in the thirty-eight Year of the Republic of India.*

*An ordinance further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.*

Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following ordinance:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Ordinance may be called the Delhi Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 1987.

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment of section 4.*—In the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) in sub-section (1) of section 4, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, extend for reasons to be specified in the notification, the term of office of all the councillors and aldermen by such period not exceeding one year at a time as it thinks fit, so, however, that the total period so extended shall not exceed three years.”

R. VENKATARAMAN,  
President.

C. RAMAN MENON,  
Additional Secretary to the Government of India.

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 24th December, 1987/Pausa 3, 1909 (Saka)

#### THE DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1987

No. 10 OF 1987

*Promulgated by the President in the thirty-eight Year of the Republic of India.*

*An ordinance further to amend the Delhi Administration Act, 1966.*

Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This ordinance may be called the Delhi Administration (Amendment) Ordinance, 1987.

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment of section 10.*—In section 10 of the Delhi Administration Act, 1966 (19 of 1966), for the words “Provided that the said period”, the following shall be substitute, namely:—

“Provided that the Central Government may, by notification, in the Official Gazette, extend the said period for reasons to be specified in the notification by such period not exceeding one year at a time as it thinks fit, so, however, that the total period so extended shall not exceed three years :

Provided further that the said period or extended period.”

R. VENKATARAMAN,  
President

C. RAMAN MENON,  
Additional Secretary to the Government of India.

#### Legislation (English) Section

Shimla-171002, 30th June, 1992

No. LLR-E (9)-3/91-Legis.—The Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992 (Ordinance No. 10 of 1992) which have been already published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section I, dated 6th June, 1992 are hereby republished in the Rajpatra, Himachal Pradesh for general information of the public.

By order,  
Sd/-  
Secretary.



**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND  
COMPANY AFFAIRS  
(Legislative Department)**

New Delhi, the 6th June, 1992/Jaistha 16, 1914 (Saka)  
**THE SPECIAL COURT (TRIAL OF OFFENCES  
RELATING TO TRANSACTIONS IN SECURITIES)  
ORDINANCE, 1992**

No. 10 of 1992

*Promulgated by the President in the Forty-third Year  
of the Republic of India*

*An Ordinance to provide for the establishment of a  
Special Court for the trial of offences relating to  
transactions in securities and for matters connected  
therewith or incidental thereto.*

WHEREAS Parliament is not in session and the President  
is satisfied that circumstances exist which render it  
necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred  
by clause (1) of article 123 of the Constitution, the  
President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Ordinance  
may be called the Special Court (Trial of Offences Relat-  
ing to Transactions in Securities) Ordinance, 1992.

(2) It shall come into force at once.

2. *Definitions.*—In this Ordinance, unless the context  
otherwise requires,—

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure,  
1973 (2 of 1974);

(b) "Custodian" means the custodian appointed under  
sub-section (1) of section 3;

(c) "securities" includes—

(i) shares, scrips, stocks, bonds, debentures, debenture  
stock, units of the Unit Trust of India or any  
other Mutual Fund or other marketable securities  
of a like nature in or of any incorporated company  
or other body corporate;

(ii) Government securities; and

(iii) rights or interests in securities;

(d) "Special Court" means the Special Court estab-  
lished under sub-section (1) of section 5.

3. *Appointment and functions of custodian.*—(1) The  
Central Government may appoint one or more Custod-  
ian as it may deem fit for the purposes of this Ordinance.

(2) The Custodian may, on being satisfied on infor-  
mation received that any person has been involved in  
any offence relating to transactions in securities after  
the first day of April, 1991 and on and before the  
promulgation of this Ordinance, notify the name of  
such person in the Official Gazette.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code,  
on and from the date of notification under sub-section  
(2), any property, moveable or immovable, or both  
belonging to any person notified under that sub-section  
shall stand attached simultaneously with the issue of  
the notification.

(4) The property attached under sub-section (3) shall  
be dealt with by the Custodian in such manner as the  
Special Court may direct.

(5) The Custodian may take assistance of any person  
for discharging his duties under this section.

4. *Contracts entered into fraudulently may be cancel-  
led.*—If the Custodian is satisfied, after such inquiry as  
he may think fit, that any contract or agreement entered  
into at any time after the first day of April, 1991 and on  
and before the proclamation of this Ordinance in rela-  
tion to any property of the person notified under sub-  
section (2) of section 3 has been entered into fraudu-  
lently or to defeat the provisions of this Ordinance, he  
may cancel such contract or agreement and on such  
cancellation such property shall stand attached under  
this Ordinance.

Provided that no contract or agreement shall be can-  
celled except after giving to the parties to the contract or  
agreement a reasonable opportunity of being heard.

5. *Establishment of Special Court.*—(1) The Central  
Government shall, by notification in the Official Gazette,  
establish a court to be called Special Court.

(2) The Special Court shall consist of a sitting Judge  
of the High Court nominated by the Chief Justice of the  
High Court within the local limits of whose jurisdiction the  
Special Court is situated, with the concurrence of the  
Chief Justice of India.

6. *Cognizance of cases by Special Court.*—The  
Special Court shall take cognizance of or try such  
cases as are instituted before it or transferred to it as  
hereinafter provided.

7. *Jurisdiction of Special Court.*—Notwithstanding  
anything contained in any other law, any prosecution in  
respect of any offence referred to in sub-section (2) of  
section 3 shall be instituted only in the Special Court and  
any prosecution in respect of such offence pending in  
any court shall stand transferred to the Special Court.

8. *Jurisdiction of Special Court as to joint trials.*—  
The Special Court shall have jurisdiction to try any  
person concerned in the offence referred to in sub-  
section (2) of section 3 either as a principal, conspirator  
or abettor and all other offences and accused persons  
as can be jointly tried therewith at one trial in accor-  
dance with the Code.

9. *Procedure and powers of Special Court.*—(1) The  
Special Court shall, in the trial of such cases, follow the  
procedure prescribed by the Code for the trial of warrant  
cases before a magistrate.

(2) Save as expressly provided in this Ordinance, the  
provisions of the Code shall, in so far as they are not  
inconsistent with the provisions of this Ordinance, apply  
to the proceedings before the Special Court, and for  
the purposes of the said provisions of the Code, the  
Special Court shall be deemed to be a Court of Session  
and shall have all the powers of a Court of Session, and  
the person conducting a prosecution before the Special  
Court shall be deemed to be a Public Prosecutor.

(3) The Special Court may pass upon any person  
convicted by it any sentence authorised by law for the  
punishment of the offence of which such person is con-  
victed.

10. *Appeal.*—(1) Notwithstanding anything in the  
Code, an appeal shall lie from any judgment, sentence or  
order, not being interlocutory order, of the Special  
Court to the Supreme Court both on facts and on law.

(2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall  
lie to any court from any judgment, sentence or order  
of the Special Court.

(3) Every appeal under this section shall be preferred  
within a period of thirty days from the date of any  
judgment, sentence or order of the Special Court.

Provided that the Supreme Court may entertain an  
appeal after the expiry of the said period of thirty  
days if it is satisfied that the appellant had sufficient  
cause for not preferring the appeal within the period  
of thirty days.

11. *Discharge of liabilities.*—(1) Notwithstanding  
anything contained in the Code and any other law for the  
time being in force, the Special Court may make such  
order as it may deem fit directing the Custodian for the  
disposal of the property under attachment.

(2) The following liabilities shall be paid or discharged  
in full, as far as may be, in the order as under:—

(a) all revenues, taxes, cesses and rates due from the  
persons notified by the Custodian under sub-  
section (2) of section 3 to the Central Govern-  
ment or any State Government or any local  
authority;

(b) all amounts due from the person so notified by  
the Custodian to any bank or financial institu-  
tion;

(c) any other liability as may be specified by the  
Special Court from time to time.

12. *Protection of action taken in good faith.*—(1) No  
suit, prosecution or other legal proceeding shall lie  
against the Central Government or the Custodian for  
anything which is in good faith done or intended to be  
done under this Ordinance.



(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government or any of its officers or other employees for any damage caused or likely to be caused by any thing which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.

13. *Ordinance to have over-riding effect.*—The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law, other than this Ordinance, or in any decree or order of any court, tribunal or other authority.

14. *Powers to make rules.*—(1) The Central Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Ordinance.

(2) Every rule made by the Central Government under this Ordinance shall be laid, as soon as may be

after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

R. VENKATARAMAN,  
President.

K. L. MOHANPURIA,  
Secretary to the Government of India.

### भाग 7— भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

शून्य

अनुपूरक

शून्य

भाग 1

#### HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AT SHIMLA-171 002 NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th April, 1993

No. HPAT-D (7)-190.—It is hereby notified for general information that the 14th April, 1993 shall be observed as Public Holiday in this Tribunal as also in the Sub-Offices of Mandi and Dharamshala on account of Birth anniversary of Dr. B. R. Ambedkar.

By order,  
Sd/-  
Registrar.

कार्यक विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 अप्रैल, 1993

संख्या का (नि-1)-बी0 (2)-2/90-II.—भारत के राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श पर, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के निम्नलिखित स्टाई अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के पद पर रु० 3000-100-4000-125-4500 के वेतनमान में रु० 400/- प्रतिमाह विशेष वेतन सहित, पदोन्नति/नियुक्त करने के तत्काल से सहर्ष आदेश करते हैं:—

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. श्री बरकत राम मंहता        | } ये तीनों अधिकारी पूर्णतया अस्थाई तौर पर पहले ही अवर सचिव के पद पर पदोन्नत हैं। |
| 2. श्री गोपाल सिंह            |  |
| 3. श्री राजेन्द्र कुमार चौहान |  |
| 4. श्री पदम राज गुप्ता        |  |
| 5. श्री बाल मुकुन्द           |  |

उपरोक्त सभी अधिकारी दो वर्ष की परब अवधि पर रहेंगे।

ये पदोन्नतियाँ निम्नलिखित याचिकाओं पर होने वाले अन्तिम निर्णय पर निर्भर होंगी:—

क्र०स० न्यायालय जहाँ याचिका याचिका संख्या वादी एवं प्रतिवादी दायर है

1	2	3	4
1. उच्चतम न्यायालय, भारत	श्री 0ए0 सं 02615/ 87 एवं सी 0ए0 एन 0 10114/87.	श्री गुरु लाल नेगी एवं अन्य विरुद्ध श्री भगत राम कपरेट एवं अन्य।	

1	2	3	4
2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधीकरण।	श्री 0ए0 संख्या 4/ 1988	श्री बोध राज एवं अन्य विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य।	
3. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधीकरण।	श्री 0ए0 संख्या 161/ 1988	श्री ज्योति स्वरूप एवं अन्य विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य।	

भारत के राष्ट्रपति, लोकहित में यह भी सहर्ष आदेश करते हैं कि अपनी पदोन्नतियों पर निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाये गये पदों पर कार्य करेंगे:—

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. श्री बरकत राम मंहता        | यह पूर्ववत अवर सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार के पद का कार्य करते रहेंगे।                |
| 2. श्री गोपाल सिंह            | यह पूर्ववत अवर सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार के पद का कार्य करते रहेंगे।            |
| 3. श्री राजेन्द्र कुमार चौहान | यह पूर्ववत अवर सचिव (आयकारी एवं कराधान), हिमाचल प्रदेश सरकार के पद पर कार्य करते रहेंगे। |
| 4. श्री पदम राज गुप्ता        | अवर सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार।   |
| 5. श्री बाल मुकुन्द           | अवर सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार।   |

आदेश द्वारा,  
एस० के० चौहान,  
मुख्य सचिव।